RNI No. DELHIN/2022/85477 | पेज - 32

नई दिल्ली, 24 अगस्त - 6 सितंबर, 2026

आजादी से विकसित देश तक, नए भारत का संकल्प

16-17

विकास की पत्रकारिता का अग्रदूत

ब्लिट्ज इंडिया

वर्ष : 4, अंक : 45 https://hindi.blitzindiamedia.com/ ₹30/-

कोलाहल का अखाड़ा न बने संसद
प्रधान संपादक की कलम से दीपक द्विवेदी 2

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए समिति गठित 12

13,041 करोड़ के चार रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी 15

युद्धों के बीच मोदी की मजबूत संवाद नीति का दिखा प्रभाव

कश्मीर पर बदली अमेरिकी भाषा भारत की बढ़ती साख का संदेश

श्रीनगर से अमेरिकी राजदूत का बयान पाकिस्तान के लिए कड़ा संकेत

दीपक द्विवेदी

नई दिल्ली। कश्मीर को लेकर अमेरिका की भाषा में आया बदलाव भारत की बढ़ती वैश्विक साख का नया और महत्वपूर्ण संकेत है। वॉशिंगटन लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर पर बेहद सावधानी से बोलता रहा है। 1993 में अमेरिकी अधिकारी रॉबिन राफेल ने इसे "विवादित क्षेत्र" (डिस्प्यूटेड टेरिटरी) तक कहा था और अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 से जुड़े बदलाव के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा था कि कश्मीर पर उसकी नीति नहीं बदली है लेकिन अब अमेरिका के भारत स्थित राजदूत सर्जियो गोर ने श्रीनगर की धरती से जम्मू-कश्मीर को भारत का "अहम हिस्सा" (इंपोर्टेंट पार्ट) बताया है। यह औपचारिक अमेरिकी नीति परिवर्तन की घोषणा नहीं है लेकिन सात दशकों की अमेरिकी कूटनीतिक शब्दावली को देखते हुए इसे बड़ा बदलाव

माना जा रहा है।

गोर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद जम्मू-कश्मीर में बेहतर हुई सुरक्षा व्यवस्था की भी सराहना की और संकेत दिया कि अमेरिका अपनी मौजूदा "डू नॉट ट्रैवल" एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है। पाकिस्तान इस बयान से आंदोलित हो गया और इस्लामाबाद में अमेरिकी राजनयिक को तलब कर औपचारिक विरोध दर्ज कराया।

यही प्रतिक्रिया बताती है कि कुछ शब्द कूटनीति में कितने मायने रखते हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी अपनी पुरानी कश्मीर नीति को किसी औपचारिक दस्तावेज से खत्म नहीं किया है लेकिन उसके राजदूत का श्रीनगर जाकर इस तरह भारत की स्थिति के

करीब खड़ा बयान देना अपने आप में महत्वपूर्ण संदेश है।

संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ से आगे बढ़ी जमीनी हकीकत

कश्मीर का अंतरराष्ट्रीय संदर्भ 1948 से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा रहा है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव - 47 में जनमत-संग्रह की व्यवस्था का सुझाव था, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की ओर से आए लड़ाकों की वापसी और चरणबद्ध ढंग से सैन्य तैनाती में

"डू नॉट ट्रैवल" एडवाइजरी की समीक्षा कर सकता है अमेरिका

कमी जैसी शर्तें पूरी होनी थीं। लेकिन, यह प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हुई और प्रस्तावित जनमत-संग्रह भी नहीं हुआ।

1972 के शिमला समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपने मतभेद शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय बातचीत से हल करने पर सहमति जताई। संयुक्त राष्ट्र आज भी अपनी स्थिति में उन पुराने चार्टर, सिक्योरिटी कौंसिल के प्रस्तावों और शिमला समझौते का उल्लेख करता है तथा यूएनएमओजीआईपी का सीमित मिशन जारी है। इसलिए गोर का बयान महत्वपूर्ण जरूर है, पर इसे यूएन की औपचारिक स्थिति बदलने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

हालांकि यहां पर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस अपनी उपयोगिता पूरी तरह से खो चुका है। यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक बार अंतरराष्ट्रीय मंचों से यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म की बात कह चुके हैं और अब भारत के इस संकल्प को दुनिया के लगभग सभी देश लगातार दोहरा रहे हैं।

इस बीच भारत के भीतर कश्मीर की संवैधानिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने के बाद जम्मू-कश्मीर को विधानसभा वाला और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 से जुड़े केंद्रीय संवैधानिक फैसले को बरकरार रखा।

इसके बाद 2024 में जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और 63.88 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

- शेष पेज 31 पर

'दिमागी नक्सल' पर सियासतः विपक्ष की छटपटाहट... पेज-29 पर

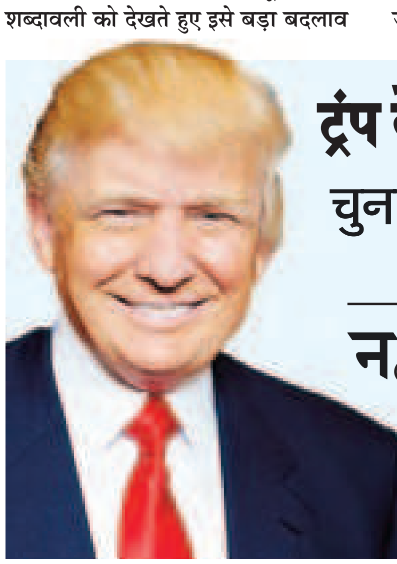

ट्रंप के बयान से पस्त हुआ विपक्ष का 'ईवीएम विलाप' और 'वोट चोरी' का नैरेटिव

चुनाव आयोग, सीईसी की तारीफ, वैश्विक मंच पर बजा भारतीय लोकतंत्र का डंका

विनोद शील

नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों से (जब से विपक्ष सत्ता से बाहर है) लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले भारत में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना कुछ खास समूहों और वैचारिक संगठनों का स्थायी स्वभाव बन चुका है लेकिन जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वैश्विक मंच से भारतीय चुनाव प्रणाली की खुलकर सराहना करते हैं तो भारत के भीतर बैठे संशयवादियों के नैरेटिव की चूलें हिल जाती हैं।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार का विशेष रूप से उल्लेख किया। इस अंतरराष्ट्रीय सराहना ने उन तत्वों को गहरे संकट और बेचैनी में डाल दिया है जिन्हें अक्सर देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों के कारण 'दिमागी नक्सल' या 'अर्बन नक्सल' की संज्ञा दी जाती है।

ज्ञानेश कुमार का सवाल और अमेरिकी राजनीति में हलचल

डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में कड़े चुनावी सुधारों और 'सेव अमेरिका एक्ट' को पारित कराने के समर्थन में भारत के चुनाव प्रबंधन को एक आदर्श वैश्विक बेंचमार्क के रूप में पेश किया है।

- शेष पेज 31 पर

कोलाहल का अखाड़ा न बने संसद

दीपक द्विवेदी
एडीटर-इन-चीफ

प्रधान संपादक की कलम से

संसद का मॉनसून सत्र 2026 अनिश्चितकालीन स्थगन के साथ समाप्त हो गया। यह सत्र लगभग 7,023 मिनट के भारी गतिरोध और हंगामे की भेंट चढ़ गया जिसमें लोकसभा की उत्पादकता मात्र 19 प्रतिशत और राज्यसभा की लगभग 39 प्रतिशत ही दर्ज की गई। मूल्यवान समय की इस भीषण बर्बादी के कारण लगभग 175.6 करोड़ रुपये के करदाताओं के धन का अपव्यय हुआ जबकि कई अहम विधेयक बिना सार्थक चर्चा के जल्दबाजी में पारित कर दिए गए।

कैसा और कितना रहा मौजूदा मॉनसून सत्र?

वर्ष 2026 का मॉनसून सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से अत्यंत निराशाजनक और गतिरोधपूर्ण रहा। नीट पेपर लीक और अन्य ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसा शीतयुद्ध छिड़ा कि सदन की गरिमा लगातार तार-तार होती रही। लोकसभा की उत्पादकता गिरकर मात्र 19 प्रतिशत पर सिमट गई जो हालिया वर्षों के सबसे निचले स्तरों में एक है। राज्यसभा की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं रही और वहां भी बमुश्किल 39 प्रतिशत कामकाज ही हो सका। सत्र के दौरान कुल 12 विधेयक पारित तो हुए लेकिन लोकसभा में अधिकांश विधेयक बिना किसी गंभीर और विस्तृत चर्चा के ही पास करा लिए गए। प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे जनता के सीधे मुद्दों से जुड़े सत्र हंगामे के शोर में लगभग पूरी तरह से गायब रहे और कोई भी सार्थक चर्चा उभर कर सामने नहीं आ सकी।

सत्ता और विपक्ष का हंगामा: कितना औचित्यपूर्ण?

लोकतंत्र में संसद का मंच केवल कानून पास करने की मशीन नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही तय करने और असहमतियों को दर्ज कराने का सर्वोच्च केंद्र होता है लेकिन वर्तमान सत्र में दोनों पक्षों का रवैया अजीब सा रहा। सरकार ने जहां कुछ मुद्दों पर चर्चा कराने की सहमति दी वहीं पूरे विपक्ष का रवैया भी पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना रहा। जब सरकार ने चर्चा की हामी भरी तो विपक्ष यदि चाहता तो उस दौरान सत्तापक्ष को घेर सकता था; पर उसने हंगामे के रास्ते को ही चुना। यही नहीं, विपक्ष सदन के बाहर भी सिर्फ हंगामा ही करता रहा जिससे निश्चित रूप से देश की जनता के हाथ सिर्फ निराशा ही हाथ लगी; इसमें कोई दोराय नहीं।

जनता अपने खून-पसीने की गाढ़ी कमाई से संसद इसलिए चलाती है कि वहां देश के भविष्य का निर्माण हो, न कि वह अरण्यरोदन और कोलाहल का अखाड़ा बने।

विपक्ष का पक्ष: विपक्ष का तर्क था कि नीट जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार चर्चा से बच रही है इसलिए आक्रामक विरोध और नारेबाजी उनकी मजबूरी थी। हालांकि, विरोध का यह तरीका जब सदन के पूर्ण बहिष्कार या वेल में आकर कार्यवाही ठप करने तक सीमित हो जाता है तो जनता के सवालों की गूंज ही दब जाती है।

सत्तापक्ष का पक्ष: सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वे हर मुद्दे पर बहस को तैयार थे लेकिन विपक्ष ने जानबूझकर सदन नहीं चलने दिया और विधायी कार्यों को बाधित किया।

विश्लेषण: ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं दोनों ही पक्ष राजनीतिक श्रेय लेने की इस खुली जंग में संसद की मूल आत्मा यानी 'संवाद और मंथन' को भूल गए। विपक्ष ने व्यवधान को अपनी राजनीतिक जीत माना तो सरकार ने बिना चर्चा के बिल पास करवाकर अपनी राह आसान कर ली जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता।

जनता के धन की बर्बादी और उसकी कीमत

संसद की कार्यवाही का एक मिनट चलाना भी देश के आम नागरिकों के खून-पसीने की कमाई से संभव होता है। एक अनुमान के मुताबिक संसद का परिचालन खर्च लगभग 2.5 लाख रुपये प्रति मिनट बैठता है। इस सत्र में लगभग 7,023 मिनट का समय केवल हंगामे, नारेबाजी और बार-बार के स्थगन की वजह से बेकार चला गया। इस प्रकार करदाताओं के लगभग 175.6 करोड़ रुपये बिना किसी जनहितैषी और सार्थक वैधानिक विमर्श के पानी में बह गए। वित्तीय नुकसान से भी बड़ा आघात लोकतांत्रिक जवाबदेही को पहुंचा है। जब सांसद बहस करने के बजाय सिर्फ शोर मचाते हैं, तो देश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करती है।

कुल मिला कर यह कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि संसद का यह सत्र इस कड़वी सच्चाई को उजागर करता है कि हमारे राजनीतिक दल तीखे मतभेदों को अनुशासित संवाद में बदलने में नाकाम हो रहे हैं। यदि सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष को विश्वास में ले तो विपक्ष को भी यह समझना होगा कि विरोध का अधिकार सदन को बंधक बनाकर नहीं बल्कि सदन के अंदर अपनी बौद्धिक क्षमता से अपनी बात मनवाकर पूरा होता है। जनता अपने खून-पसीने की गाढ़ी कमाई से संसद इसलिए चलाती है कि वहां देश के भविष्य का निर्माण हो, न कि वह अरण्यरोदन और कोलाहल का अखाड़ा बने।

ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा नॉर्थ ईस्ट

जलविद्युत, गैस ग्रिड और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से क्षेत्र बन रहा स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा का नया केंद्र

ब्लिट्ज विशेष

पूर्वोत्तर भारत अब केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के क्षेत्र में भी देश के लिए एक नई मिसाल बनकर उभर रहा है। केंद्र सरकार की निरंतर नीतिगत पहल और लक्षित निवेश के परिणामस्वरूप यह क्षेत्र ऊर्जा की कमी से निकलकर सुरक्षित, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।

जलविद्युत परियोजनाओं से मिली नई रफ्तार

पूर्वोत्तर भारत देश की जलविद्युत क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। पिछले कुछ वर्षों में यहां कई बड़ी और छोटी जलविद्युत परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ है जिससे क्षेत्र के ऊर्जा विकास को नई गति मिली है।असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित 2,000 मेगावाट क्षमता वाली सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। इसके साथ ही, क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए छोटे जलविद्युत परियोजनाओं का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है।

मुख्य बातें

- पूर्वोत्तर में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा विकास को तेजी मिली।
- जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार पर विशेष जोर।
- 2,000 मेगावाट की सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना सबसे प्रमुख परियोजनाओं में शामिल।
- नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड से स्वच्छ ऊर्जा नेटवर्क को मिलेगी मजबूती।
- मिजोरम के चम्फाई में 20 मेगावाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा पार्क शुरू।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा।
- ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास की दिशा में पूर्वोत्तर लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

गैस ग्रिड से मजबूत होगी व्यवस्था

नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा का मजबूत नेटवर्क तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस परियोजना से प्राकृतिक गैस आधारित स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और पूरे क्षेत्र की ऊर्जा व्यवस्था और अधिक मजबूत तथा विश्वसनीय बनेगी।

सौर ऊर्जा बन रही है विकास की नई ताकत

पूर्वोत्तर भारत में अब सौर ऊर्जा और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियां तेजी से विकसित हो रही हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विशेष नीतिगत सहायता से इस क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

मिजोरम के चम्फाई जिले में 20 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा पार्क का संचालन शुरू हो चुका है। यह ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि आम नागरिक भी स्वच्छ, सस्ती और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा का लाभ उठा सकें।

हरित ऊर्जा के क्षेत्र में बन रहा है नया मॉडल

जलविद्युत, गैस ग्रिड और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में लगातार हो रहे निवेश और विकास के कारण पूर्वोत्तर भारत आज ऊर्जा सुरक्षा और हरित विकास का एक मजबूत मॉडल बनकर उभर रहा है। इन पहलों से न केवल क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है, बल्कि स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल विकास की दिशा में भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

स्वच्छ गांव, स्वस्थ जीवन: बदल रहा पूर्वोत्तर भारत

एक समय था जब पूर्वोत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी लोगों के लिए बड़ी चुनौती थी लेकिन पिछले 12 वर्षों में यह तस्वीर तेजी से बदली है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभाव से आज पूर्वोत्तर के गांव पहले से अधिक स्वच्छ बन रहे हैं और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हो रही हैं।

स्वच्छ भारत मिशन से खुले में शौच की समस्या हुई समाप्त

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका है। वर्ष 2014 से 2026 के बीच पूरे क्षेत्र में लगभग 57 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए गए जिससे लाखों परिवारों को स्वच्छ और सुरक्षित जीवन जीने की सुविधा मिली।

अब लक्ष्य है स्वच्छता को बनाए रखना और बेहतर कचरा प्रबंधन

वर्ष 2020 से शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण में केवल शौचालय बनाने पर ही नहीं बल्कि उनके नियमित उपयोग और कचरे के बेहतर प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस चरण के तहत ओडीएफ प्लस गांवों का विकास किया जा रहा है जहां ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन, प्लास्टिक कचरे का निपटान और मल-कीचड़ (फीकल स्लज) के सुरक्षित उपचार जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस दिशा में सिक्किम और त्रिपुरा ने सभी गांवों को 100 प्रतिशत ओडीएफ प्लस बनाकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। वहीं मिजोरम और सिक्किम घरों से ही कचरे को अलग-अलग एकत्र करने की व्यवस्था में अग्रणी राज्यों के रूप में उभरे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिली नई मजबूती

पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास पर बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा ढांचे को लगातार मजबूत बनाया गया है।

अब पूरी तरह से कार्यरत एम्स गुवाहाटी पूर्वोत्तर का प्रमुख सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य संस्थान बन चुका है जहां लोगों को आधुनिक और उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 12 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। इससे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं दोनों को नई मजबूती मिली है।

आयुष्मान भारत से लाखों लोगों को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत अप्रैल 2026 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2.43 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

इस योजना के माध्यम से 900 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों में 46 लाख से अधिक मरीजों को उपचार का लाभ मिला है जिससे क्षेत्र के लाखों परिवारों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हुई हैं।

स्वच्छ भारत मिशन, एम्स गुवाहाटी, नए मेडिकल कॉलेजों और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को नई दिशा दी है।

दीपक द्विवेदी

साम्राज्य की जिरह

एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने भारत के विभाजन के इतिहास को फिर से कटघरे में खड़ा किया

पुस्तक की भूमिका के शुरुआती पन्नों में ही राकेश द्विवेदी एक सहज लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हैं- सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने ब्रिटिश शासन और भारत के विभाजन के इतिहास पर इतना विस्तृत ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस की?

वे अत्यंत विनम्रता से लिखते हैं, "मैं इतिहासकार नहीं हूं; मैं पेशे से एक वकील हूं।"

पहली दृष्टि में यह वाक्य लेखक की विनम्रता का परिचायक लगता है, लेकिन जैसे-जैसे पुस्तक आगे बढ़ती है, स्पष्ट होता है कि यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी है।

इतिहासकार दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों को समझने और उनके ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या करने का प्रयास करता है, जबकि एक वकील उन्हीं दस्तावेजों को इस दृष्टि से परखता है कि वे क्यों तैयार किए गए, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था और वे वास्तव में किस सत्य की ओर संकेत करते हैं।

राकेश द्विवेदी का सबसे बड़ा योगदान कोई नया इतिहास गढ़ना नहीं है, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के आधिकारिक दस्तावेजों को एक अनुभवी अधिवक्ता की पैनी कानूनी दृष्टि से परखना है। उनकी यह विश्लेषणात्मक जिरह कई ऐसे दस्तावेजों की परतें खोलती है, जिन्हें अब तक निर्विवाद मान लिया गया था।

कानूनी दृष्टि से इतिहास की नई व्याख्या

पुस्तक के सबसे प्रभावशाली अध्यायों में लेखक की कानूनी समझ और विश्लेषण क्षमता पूरी मजबूती के साथ सामने आती है।

राकेश द्विवेदी वर्ष 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए शाही चार्टर को केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसकी कानूनी कसौटी पर जांच करते हैं। इसी दौरान वे एक ऐसे तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिस पर अधिकांश इतिहासकारों ने अपेक्षित गंभीरता से विचार नहीं किया।

चार्टर में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि किसी भी ईसाई शासक के क्षेत्र में उसकी अनुमति के बिना व्यापार नहीं किया जा सकता जबकि गैर-ईसाई क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था।

इतना ही नहीं, किले बनाने, बस्तियां बसाने और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करने की भी अनुमति दी गई थी लेकिन उसका लक्ष्य मुख्य रूप से गैर-ईसाई दुनिया थी।

इसी संदर्भ में राकेश द्विवेदी लिखते हैं-

"यह दरअसल धर्मयुद्ध (क्रूसेड) का ही एक नया स्वरूप था।"

यह निष्कर्ष किसी भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों के गहन और तार्किक विश्लेषण पर आधारित है।

समुद्री कानून से साम्राज्यवादी राजनीति तक

लेखक प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं ह्यूगो ग्रोटियस और जॉन सेल्डन के विचारों का भी अत्यंत रोचक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

वे 'मारे लिबेरम' और 'मारे क्लॉजम' को केवल राजनीतिक या दार्शनिक ग्रंथ नहीं मानते बल्कि अपने-अपने संरक्षकों के हितों की रक्षा के लिए तैयार किए गए कानूनी पक्ष-पत्रों के रूप में देखते हैं।

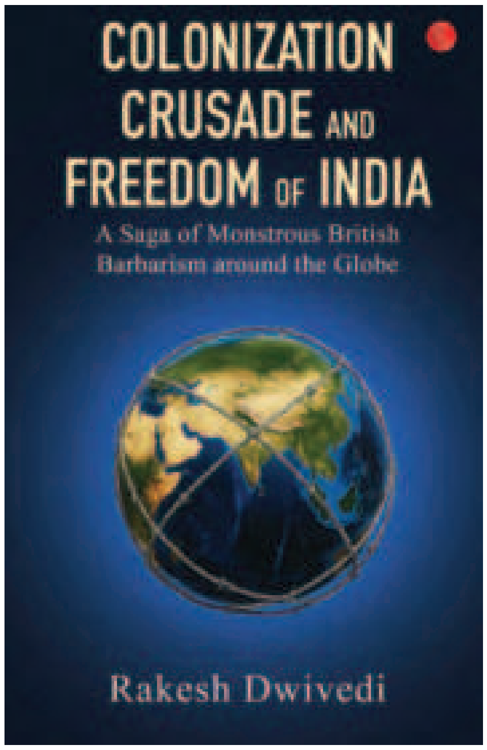

लेखक लिखते हैं-

"समुद्र की स्वतंत्रता का ग्रोटियस का सिद्धांत डच हितों के अनुकूल था, जबकि सेल्डन का तर्क ब्रिटेन को डचों के व्यापारिक लाभ अपने पक्ष में करने में मददगार साबित हुआ।" यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि उस दौर के कानूनी सिद्धांत भी साम्राज्यवादी राजनीति और राष्ट्रीय हितों से पूरी तरह अलग नहीं थे।

भारत के विभाजन को वैश्विक राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास

इस पुस्तक का मूल विचार यह है कि भारत का उपनिवेशीकरण और देश का विभाजन केवल भारत की आंतरिक राजनीतिक घटनाएं नहीं थीं।

राकेश द्विवेदी का मानना है कि ये दोनों घटनाएं उस दौर में विश्व की महाशक्तियों के बीच चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं।

उनके अनुसार, ब्रिटिश नीति-निर्माताओं के निर्णय केवल लाहौर, दिल्ली या कराची को ध्यान में रखकर नहीं लिए जा रहे थे। उनकी रणनीतिक सोच का केंद्र मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरेशिया के भू-राजनीतिक हित भी थे।

यही व्यापक दृष्टिकोण इस पुस्तक को भारत के विभाजन पर लिखी गई पारंपरिक पुस्तकों से अलग पहचान देता है और पाठक को इतिहास को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है।

इतिहास को नए नजरिए से समझने का प्रयास

राकेश द्विवेदी का उद्देश्य केवल स्थापित ऐतिहासिक धारणाओं को चुनौती देना नहीं है, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों का नए दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है।

एक अधिवक्ता के रूप में वे हर दस्तावेज से प्रश्न पूछते हैं, हर दावे को तर्क और प्रमाण की कसौटी पर परखते हैं और पाठकों को भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यही दृष्टिकोण इस पुस्तक को केवल इतिहास का विवरण नहीं रहने देता बल्कि इतिहास के दस्तावेजों, तथ्यों और स्थापित निष्कर्षों की गंभीर, निष्पक्ष और तार्किक पड़ताल में बदल देता है।

यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पाठक को केवल इतिहास पढ़ने के लिए नहीं बल्कि इतिहास को नए दृष्टिकोण से समझने, प्रश्न करने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वयं निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती है।

विदेश में पढ़ाई चुनने वाले भारतीय छात्रों पर एनईपी का असर

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 उन भारतीय छात्रों के फैसलों पर असर डालने लगी है जो पहले हायर एजुकेशन के लिए विदेश का रुख करते थे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और शिक्षा मंत्रालय के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि हायर एजुकेशन के लिए देश छोड़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में लगभग 31% की कमी आई है । 2023 में महामारी के बाद के सबसे ज्यादा स्तर 9.08 लाख से घटकर 2025 में यह संख्या लगभग 6.26 लाख हो गई है। हालांकि, लगभग 18.8 लाख भारतीय छात्र अभी भी विदेश में रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विदेश जाने वाले नए छात्रों की संख्या में भारी गिरावट पारंपरिक विदेश में पढ़ाई के ट्रेंड में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है।

प्रो. पी.एस. शुक्ला
पूर्व वाइस चांसलर,
एनईएचयू, शिलांग

इस बदलाव के पीछे एक अहम वजह एनईपी 2020 के तहत भारत में हायर एजुकेशन के मौकों का बढ़ना है। इस पॉलिसी ने मल्टी-डिसिप्लिनरी एजुकेशन, फ्लेक्सिबल एकेडमिक रास्ते, स्किल-ओरिएंटेड प्रोग्राम, रिसर्च और इनोवेशन, इंटरनेशनल लेवल पर जुड़ाव और भारतीय व विदेशी संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ावा दिया है। भारत में अच्छी क्वालिटी वाली यूनिवर्सिटीज, खास प्रोग्राम, इंटरनेशनल सहयोग और विदेशी यूनिवर्सिटी कैंपस के आने से छात्रों को देश में ही ज्यादा आकर्षक विकल्प मिल रहे हैं।

साथ ही, छात्र और माता-पिता विदेश में पढ़ाई के खर्च और उससे मिलने वाले फायदे (आरओआई) को लेकर ज्यादा सावधान हो रहे हैं। ट्यूशन और रहने-सहने के बढ़ते खर्च, भारतीय रुपये की गिरती कीमत और विदेश में नौकरी को लेकर अनिश्चितता ने विदेश में पढ़ाई को काफी महंगा बना दिया है। जब भारत में ही वैसे ही प्रोग्राम और बेहतर करियर के मौके मिल रहे हों, तो पढ़ाई पर ₹30–50 लाख या उससे ज्यादा खर्च करने को सही ठहराना मुश्किल हो सकता है।

इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव भी छात्रों की पसंद पर असर डाल रहे हैं। कनाडा, यूके और यूएस जैसे देशों ने वीजा, इमिग्रेशन या आश्रितों (डिपेंडेंट) से जुड़ी सख्त पॉलिसी लागू की हैं। नतीजतन, पहले जो उम्मीद थी कि विदेश में पढ़ाई करने से अपने आप नौकरी और स्थायी रूप से बसने का मौका मिल जाएगा, वह अब कम निश्चित होती जा रही है।

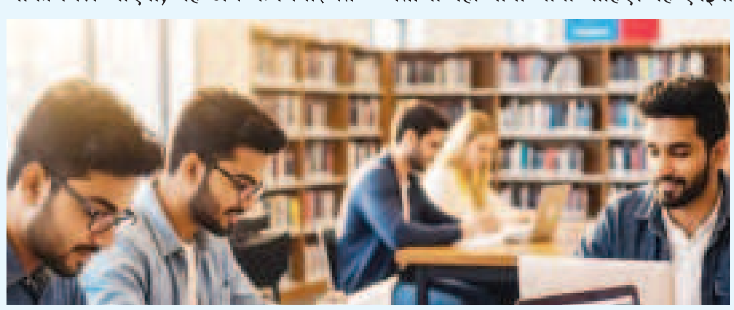

इससे छात्रों की सोच में एक अहम बदलाव आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा छात्र अब विदेश में पढ़ाई को सफल करियर का एकमात्र रास्ता नहीं मान रहे हैं। इसके बजाय, कई छात्र यह सोच रहे हैं कि क्या वे भारत में ही अच्छी क्वालिटी वाली और ग्लोबल लेवल पर काम आने वाली शिक्षा पा सकते हैं, और साथ ही विदेश की महंगी ट्यूशन फीस, करेंसी रिस्क, वीजा की अनिश्चितता और घर से दूर रहने की सामाजिक कीमत से भी बच सकते हैं। इसलिए, विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी को सिर्फ सख्त विदेशी नीतियों या आर्थिक दबावों का नतीजा नहीं माना जाना चाहिए। यह एनईपी 2020 के बढ़ते असर को भी दिखाता है, जो धीरे-धीरे भारतीय उच्च शिक्षा को ज्यादा प्रतिस्पर्धी, लचीला, अंतरराष्ट्रीय और छात्र-केंद्रित बना रहा है।

इसका एक बड़ा और अहम संदेश है। एनईपी इस सोच को बदलने में मदद कर रही है कि बेहतर शिक्षा के लिए मैं विदेश कहां जाऊं? से बदलकर यह सवाल हो जाए कि क्या मुझे भारत में ही वैश्विक स्तर की

> ● छात्रों की संख्या में भारी गिरावट विदेश में पढ़ाई के ट्रेंड में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है

प्रतिस्पर्धी शिक्षा मिल सकती है? अगर भारतीय संस्थान गुणवत्ता, शोध, रोजगार की क्षमता और अंतरराष्ट्रीय अनुभव को बेहतर बनाते रहते हैं, तो ज्यादा छात्र उच्च शिक्षा के लिए देश छोड़ने के बजाय भारत में ही रहना पसंद कर सकते हैं।

इसलिए, भारत के सामने भविष्य की चुनौती सिर्फ छात्रों के विदेश जाने को कम करना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि घरेलू शिक्षा प्रणाली वह गुणवत्ता, इनोवेशन, वैश्विक अनुभव और करियर के अवसर दे, जिनकी तलाश में छात्र विदेश जाते हैं। एनईपी 2020 इस बदलाव को लाने के लिए एक जरूरी ढांचा प्रदान करती है।

'वैल्यू चेन' से बदल रही यूपी के कारीगरों की तकदीर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। किसी उत्पाद का सफर उसके बनने पर खत्म नहीं होता, उसको बड़े बाजारों तक पहुंचने के लिए प्रोसेसिंग सुविधाओं, गुणवत्ता जांच, पैकेजिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और डिस्ट्रिब्यूशन तक पहुंच की जरूरत पड़ सकती है। ये सभी गतिविधियां मिलकर एक 'वैल्यू चेन' बनाती हैं। उत्तर प्रदेश के कारीगरों, किसानों, फूड प्रोड्यूसर्स और माइक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमईज) के लिए, इन कड़ियों को मजबूत बनाना, उत्पादन और अंतिम उपभोक्ता के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केट-एक्सेस से जुड़े गैप को पाटने में मदद कर सकता है।

क्या है वैल्यू चेन

वैल्यू चेन का मतलब है वे अलग-अलग गतिविधियां, जो किसी उत्पाद को बनने से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में शामिल होती हैं। उत्पाद के हिसाब से, इसमें शामिल हो सकता है।

ये हैं मुख्य स्टेज-

■ रॉ मटीरियल ■ उत्पादन ■ प्रोसेसिंग ■ टेस्टिंग ■ पैकेजिंग ■ स्टोरेज ■ लॉजिस्टिक्स ■ मार्केटिंग ■ उपभोक्ता

साझा इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका

छोटे कारोबारियों के लिए खुद का टेस्टिंग लैब, प्रोसेसिंग यूनिट या आधुनिक पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना आर्थिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, इसी समस्या के समाधान के रूप में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (सीएफसीज) काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की 'ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर प्रोत्साहन योजना' का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर की वैल्यू चेन को मजबूत बनाना और उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना है।

प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन

प्रोसेसिंग 'वैल्यू चेन' का वह चरण है, जिसके जरिए किसी उत्पाद की कीमत बढ़ सकती है। कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए, इसमें सफाई, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। वहीं हस्तशिल्प और निर्मित उत्पादों के लिए, वैल्यू एडिशन में फिनिशिंग, डिजाइन डेवलपमेंट और अन्य उत्पादन प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं।

गुणवत्ता और टेस्टिंग

गुणवत्ता जांच भी वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा है, खासतौर पर तब जब उत्पाद ऑर्गनाइज्ड रिटेल या बड़े स्तर पर डिस्ट्रिब्यूशन के लिए तैयार किए जा रहे हों। टेस्टिंग सुविधाएं उत्पादकों को यह जांचने में मदद कर सकती हैं कि उनके उत्पाद लागू गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। ओडीओपी या सीएफसी फ्रेमवर्क के तहत तैयार की जा सकने वाली सुविधाओं

में टेस्टिंग लैबोरेटरीज भी शामिल हैं।

पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स

पैकेजिंग के व्यावहारिक और व्यावसायिक, दोनों तरह के काम होते हैं। यह ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उत्पाद की सुरक्षा करती है, उपभोक्ताओं को जानकारी देती है, और प्रोडक्ट ब्रांडिंग में मदद करती है। सीएफसी स्कीम में खासतौर पर पैकेजिंग, लेबलिंग और बारकोडिंग सुविधाओं के साथ-साथ कॉमन लॉजिस्टिक्स सेंटर भी शामिल हैं।

छोटे उत्पादकों के लिए, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि उन्हें विशेष सुविधाएं इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, बिना यह जरूरत हुए कि हर उद्यम अलग से वही इंफ्रास्ट्रक्चर खुद तैयार करे।

उत्पादकों को बाजारों से जोड़ना

आखिरकार, किसी भी 'वैल्यू चेन' को उत्पादन को उपभोक्ताओं से जोड़ना ही होता है। मार्केट एक्सेस में लोकल और ऑर्गनाइज्ड रिटेल, प्रदर्शनियां, इंस्टीट्यूशनल खरीदार, डिजिटल कॉमर्स और अन्य डिस्ट्रिब्यूशन चैनल शामिल हो सकते हैं। सरकारी हस्तक्षेप इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा सकते हैं या मार्केट लिंकेज आसान बना सकते हैं, लेकिन ये व्यावसायिक सफलता की गारंटी नहीं देते।

पूरी चेन को मजबूत बनाना

उत्तर प्रदेश के लोकल उत्पादकों और एमएसएमईज के लिए, वैल्यू-चेन सपोर्ट का मतलब है सिर्फ उत्पादन से आगे भी देखना। प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस, ये सभी आपस में जुड़े हुए चरण हैं, जो यह तय कर सकते हैं कि कोई उत्पाद उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है।

गाजियाबाद- जेवर कॉरिडोर में होंगे 11 नमो भारत और 18 मेट्रो स्टेशन

नई दिल्ली। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन स्टेशनों में शामिल हैं, जो गाजियाबाद-जेवर कॉरिडोर पर नमो भारत सेवाओं के लिए प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा साझा किए गए स्टेशन विवरण के अनुसार, इस 72.44 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 11 स्टेशन नमो भारत सेवाएं प्रदान करेंगे, जबकि मार्ग पर 18 स्टेशन मेट्रो सेवाएं देंगे।

कॉरिडोर कितना लंबा-चौड़ा?

इससे यात्री गाजियाबाद, नोएडा और एयरपोर्ट के बीच क्षेत्रीय रैपिड रेल और स्थानीय मेट्रो दोनों से यात्रा कर सकेंगे। हालांकि, इस संबंध में एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी से कहा कि यह कॉरिडोर अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण में है। यह 72.44 किलोमीटर का कॉरिडोर दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के गाजियाबाद स्टेशन को जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा। कुल लंबाई में से लगभग 71.5 किलोमीटर एलिवेटेड और 1.29 किलोमीटर भूमिगत होगा।

दिल्ली में नौकरीपेशा वर्ग के लिए घर खरीदने का सुनहरा मौका

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) राजधानी दिल्ली में घर खरीदने की चाहत रखने वाले नौकरीपेशा लोगों को सुनहरा मौका दे रहा है। डीडीए की कर्मयोगी आवास योजना सेवारत और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जिसका लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।

योजना के तहत उत्तर-पश्चिम दिल्ली के नरेला (सेक्टर ए1 से ए4 और पॉकेट-11) में स्थित 1224 रेडी-टू-मूव फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास दिल्ली या अन्य जगहों पर पहले से प्रॉपर्टी है। एक आवेदक अलग-अलग श्रेणियों में कई फ्लैट भी खरीद सकता है।

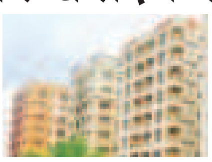

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का देश का नागरिक और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष का होना जरूरी है। यह योजना मुख्य रूप से दो श्रेणियों के पेशेवरों के लिए है:

सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी: केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू , स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक बैंकों, स्थानीय निकायों, सरकारी विश्वविद्यालयों और अस्पतालों के सेवारत या रिटायर्ड नियमित कर्मचारी।

पेशेवर: डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और शिक्षक।

किस श्रेणी में कितने फ्लैट्स और क्या है बुकिंग राशि?

1-बीएचके (ब्लॉक वाई): 384 फ्लैट्स। क्षेत्रफल: 60–61 वर्ग मीटर। बुकिंग राशि: 50,000

2-बीएचके (ब्लॉक ए, बी, सी): 432 फ्लैट्स। बुकिंग राशि: 4,00,000

3-बीएचके (ब्लॉक क्यू,आर, एस): 408 फ्लैट्स। क्षेत्रफल: 164–184 वर्ग मीटर। बुकिंग राशि: 10,00,000

कब से होगी बुकिंग?

इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन डीडीए के आधिकारिक पोर्टल पर 24 जुलाई से रजिस्ट्रेशन जारी है जबकि बुकिंग प्रक्रिया 15 अगस्त से शुरू हो चुकी। यह 30 अक्टूबर (या सभी फ्लैट्स बुक होने तक) चलेगी।

दिल्ली में वोकेशनल व स्पेशल गेस्ट टीचर्स की सैलरी में 15 हजार की बढ़ोतरी

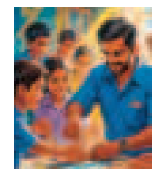

नई दिल्ली। दिल्ली में वोकेशनल व स्पेशल गेस्ट टीचर्स की सैलरी में 15 हजार से अधिक की बढ़ोतरी की गई है।

दिल्ली सरकार के स्कूलों में तैनात 1131 वोकेशनल शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक परामर्श व मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के साथ ही उनका कौशल आकलन कर उचित परामर्श देते हैं। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित विशेष केंद्रों में तैनात शिक्षक पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करते हैं।

परंतु इन शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। पिछले काफी समय से इन शिक्षकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग की जा रही थी। इसे अब पूरा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में इनके वेतन वृद्धि को स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वोकेशनल शिक्षकों को पहले 20 हजार से 23 हजार रुपये के बीच वेतन मिलता था। इसे बढ़ाकर 38,100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे 784 विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 35,420 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा से जोड़कर मुख्यधारा में लाया जाता है।

गुरुग्राम की 436 बीघा जमीन पर ग्राम पंचायत का हक बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला किया खारिज

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम की 436 बीघा से अधिक जमीन का स्वामित्व ग्राम पंचायत को बहाल कर दिया। शीर्ष अदालत ने 2007 में जमीन पर निजी स्वामित्व के दावों को मान्यता देने वाले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को भी खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गांव की साझा भूमि की अहमियत को हाई लाइट करते हुए गुरुग्राम में 436 बीघा से अधिक भूमि का मालिकाना हक ग्राम पंचायत को वापस दे दिया। शीर्ष अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2007 के उस फैसले को रद कर दिया, जिसमें संबंधित भूमि पर निजी मालिकाना हक के दावों को स्वीकार कर लिया गया था।

जस्टिस संजय कुमार और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि भूमि को 'नया सोना' माना जाता है, खासकर तब, जब ऐसी भूमि गुरुग्राम जैसे तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों के पास हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित भूमि हरियाणा कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 के तहत गांव की साझा भूमि थी।

हाईकोर्ट का फैसला रद

पीठ ने हाईकोर्ट के 2007 के फैसले को रद कर दिया। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि हाईकोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड में गांव की 'पट्टियों'(मालिक समूहों) के नाम दर्ज होने के चलते भूमि को निजी मानकर भूल की थी। हाईकोर्ट के फैसले को रद करने के साथ ही

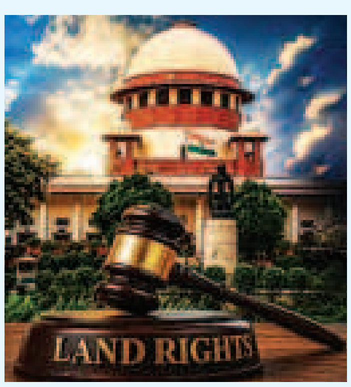

सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, 1955 को वजीराबाद ग्राम पंचायत के पक्ष में किए गए म्यूटेशन (मालिकाना हक के बदलाव) की पुष्टि कर दी है, जिसका फायदा उसके उत्तराधिकारी, नगर निगम, गुड़गांव (अब गुरुग्राम) को मिलेगा।

हैदरपुर की शामलात पट्टी का हिस्सा

शीर्ष अदालत ने कहा कि वादी 13 सितंबर, 1955 को वजीराबाद ग्राम पंचायत के पक्ष में किए गए म्यूटेशन में दखल देने के लिए कोई ठोस आधार पेश करने में नाकाम रहे। तथ्यों से पता चलता है कि संबंधित भूमि 'शामलात पट्टी' नहीं थी, बल्कि हैदरपुर की शामलात पट्टी का हिस्सा थी।

पंचायत के अधिकार में ऐसे आई

हालांकि मालिकों यानी चित्रू, रामरतन, मेधा, सदासुख और अहमद अली खान को अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कराने का अधिकार था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसा कोई बंटवारा नहीं हुआ। नतीजतन, 436 बीघा 18 बिस्वा की 'शामिलात देह' वैसी ही बनी रही, जिस पर 1961 के एक्ट की धारा 2(जी)(1) लागू हुई और वह वजीराबाद ग्राम पंचायत के अधिकार में आ गई।

क्या किया था दावा?

यह विवाद हैदरपुर के निर्जन गांव (जिसे बे-चिराग मौजा कहा जाता है) में 436 बीघा और 18 बिस्वा भूमि से जुड़ा था। यह गांव आज के गुरुग्राम में वजीराबाद से सटा हुआ है। गांव के कुछ लोगों ने भूमि पर मालिकाना हक का दावा करते हुए कहा था कि 'भूमि निजी पट्टियों की थी और कभी भी पंचायत के अधिकार में नहीं आई थी।'

एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला नाइट सफारी और जू बनेगा गुजरात में

2700 जानवरों का होगा बसेरा

ब्लिट्ज ब्यूरो

बनासकांठा। गुजरात के बनासकांठा जिले का डीसा शहर में जल्द ही एशिया का पहला रेगिस्तान-थीम वाला नाइट सफारी और जू बनेगा। इस जू में लगभग 2700 जानवरों और 83 प्रजातियों का बसेरा होगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी (सीजेडए) से मंजूरी मिलने के बाद एशिया के पहले डेजर्ट-थीम वाले ड्राइव-थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। यह परियोजना जूना डीसा में करीब 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर विकसित की जाएगी।

गुजरात के वन मंत्री ने दी जानकारी

गुजरात के वन मंत्री अर्जुन मोधवाडिया ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना को सीजेडए की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है और इसकी अनुमानित लागत 542.14 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक पार्क में करीब 83 प्रजातियों के 2,700 देशी और विदेशी जानवरों तथा पक्षियों को रखा जाएगा। पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली नाइट सफारी

होगी, जहां पर्यटक रात में सक्रिय रहने वाले वन्यजीवों को करीब से देख सकेंगे।

पांच विशेष बाड़े बनाए जाएंगे

परियोजना में अलग डे जू के साथ नाइट सफारी के लिए पांच विशेष बाड़े बनाए जाएंगे। गुजरात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (वाइल्डलाइफ) और चीफ वाइल्डलाइफ वॉर्डन डॉ. जयपाल सिंह ने बताया कि पूरे पार्क का डिजाइन रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

यहां प्राकृतिक सूखे लैंडस्केप विकसित किए जाएंगे। पार्क में चिंकारा, ब्लैकबक, इंडियन वाइल्ड ऐस, एशियाई शेर और तेंदुए जैसी प्रमुख प्रजातियां होंगी। इसके अलावा इंडियन साही, भारतीय खरगोश, हेजहॉग, रेगिस्तानी खरगोश, स्लॉथ बियर, इंडियन काराकल, भारतीय भेड़िया, सुनहरा सियार, धारीदार लकड़बग्घा और भारतीय रेगिस्तानी लोमड़ी भी आकर्षण का केंद्र होंगी।

अलग-अलग बाड़े

पार्क में शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के लिए अलग-अलग बाड़े, एवियरी, रेप्टाइल हाउस, बटरफ्लाई पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर की सुविधा होगी। पर्यटकों के लिए फूड कोर्ट, स्मारिका दुकान और गोल्फ कार्ट सर्विस भी उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा रेप्टाइल सफारी, रेनफॉरेस्ट बायोम और एक्वेरियम भी विकसित किए जाएंगे। अफ्रीकी रेगिस्तान की प्रजातियां भी यहां आकर्षण बढ़ाएंगी। इनमें अंगोलन जिराफ, ग्रेवी जेब्रा, सिमिटार ओरिक्स, अफ्रीकी कुडू, स्प्रिंगबॉक, काला गैंडा, चिंपैंजी, मीरकट, अफ्रीकी चीता, अफ्रीकी शेर और फेनेक लोमड़ी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तानी प्रजातियों में कंगारू, एमु और वालाबी भी रखे जाएंगे।

जबलपुर-रायपुर के बीच बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे

केंद्र ने दी मंजूरी, रायपुर से भोपाल का सफर 6-7 घंटे में होगा पूरा

ब्लिट्ज ब्यूरो

कबीरधाम। केंद्र सरकार ने जबलपुर-भोपाल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और जबलपुर-मंडला-छत्तीसगढ़ सीमा-कवर्धा-सिमगा-रायपुर 6-लेन मार्ग परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ सीमा से कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा होते हुए रायपुर तक के मार्ग को 6-लेन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। क्षेत्रीय सांसद संतोष पांडेय ने परियोजना की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।

15 हजार करोड़ का बजट, कई शहर जुड़ेंगे

सांसद संतोष पांडेय के अनुसार, केंद्र सरकार ने पूरी परियोजना के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में भोपाल, सागर, दमोह, जबलपुर और मंडला से होते हुए छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा। इसके बाद यह कवर्धा, बेमेतरा और सिमगा होते हुए रायपुर से जुड़ेगा।

नए एक्सप्रेसवे के बनने से भोपाल और रायपुर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। वर्तमान में रायपुर से भोपाल पहुंचने में करीब

14 से 15 घंटे लगते हैं। परियोजना पूरी होने के बाद यह सफर घटकर करीब 6 से 7 घंटे रह जाने का दावा किया गया है।

वहीं, जबलपुर से रायपुर की यात्रा भी आसान होगी। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं, जबकि प्रस्तावित 6-लेन कॉरिडोर बनने के बाद यह समय 3.5 से 4 घंटे तक आने की उम्मीद है।

मध्य भारत के लिए बनेगा अहम कॉरिडोर

सांसद पांडेय ने इसे मध्य भारत की महत्वपूर्ण लाइफलाइन बताते हुए कहा कि जबलपुर से छत्तीसगढ़ सीमा, चिल्फीघाटी, कवर्धा होते हुए रायपुर तक बनने वाला यह कॉरिडोर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच प्रमुख व्यापारिक मार्ग को और मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। साथ ही दोनों राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच आवागमन भी आसान होगा।

'विकसित भारत' के संकल्प को मिलेगी गति

सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकसित हो रहे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में मध्य भारत में कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 'विकसित भारत' के संकल्प को गति देने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

महाराष्ट्र में कैब चलाने के लिए अब मराठी भाषा जरूरी

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा के नियमों को और सख्त कर दिया है। विगत दिवस 'महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026' में बड़े बदलाव किए गए, जिनमें कड़ी सजा का प्रावधान है। इसमें तीन महीने तक ड्राइविंग ऑथराइजेशन सस्पेंड करना और बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस या बैज रद करना शामिल है।

इन संशोधनों के तहत, यात्रियों को ले जाने वाले कमर्शियल वाहनों, जैसे- ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली एप-बेस्ड कैब के ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान होना जरूरी कर दिया गया है। यह नियम परमिट धारकों पर भी लागू होगा, जिससे कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मराठी भाषा में दक्षता सुनिश्चित करने के राज्य के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। सबसे अहम बदलाव इसे लागू करने के तरीके में किया गया है। नए जोड़े गए नियम 22(3ए) के तहत, एप-बेस्ड मोटर कैब के अधिकृत ड्राइवरों को मराठी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान दिखाना होगा।

भागवत बोले- जेन-जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त

हमें उनकी बात समझनी चाहिए, उनसे बात नहीं हुई तभी तो आंदोलन हुआ

ब्लिट्ज ब्यूरो

मुंबई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विगत दिवस मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया। उन्होंने कहा कि जेन-जी और जेन-अल्फा, पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा देशभक्त और ईमानदार है।

उन्होंने कहा- हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उनसे बातचीत में कमी थी, इसीलिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन हुआ।

उन्होंने ये बात मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी आईआईएमयूएन की 15वीं वर्षगांठ पर कही। प्रोग्राम में 11 से 19 साल की उम्र के करीब 2,000 छात्र शामिल हुए।

नीट पेपर लीक के खिलाफ देशभर में प्रदर्शनों के बाद इसे आरएसएस का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। जंतर-मंतर पर 36 दिन चले आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था।

सुधार के लिए आंदोलन जरूरी

उन्होंने कहा कि आंदोलन तब होता है, जब बातचीत नाकाम हो जाती है। अगर सरकार ने पहले ही बात कर ली होती, तो आंदोलन की जरूरत नहीं होती। आंदोलन भी बातचीत का एक तरीका है।

जेन जी की सोच पर: हम लोग जब जेन

जी की उम्र में थे, तब बड़े जो कहते थे, हम मान लेते थे, सवाल नहीं करते थे। आज की जेन जी सवाल करती है। उन्हें जवाब चाहिए और प्यार भी चाहिए।

जेन जी के अधिकार पर: जेन जी को आंदोलन नहीं करना चाहिए, यह तो हम नहीं कहेंगे। संविधान में लिखा है कि प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन यह कैसे करना है, उसे देखना चाहिए।

जेन जी के विरोध पर: हमें भी देखना होगा कि अगर जेन जी चिल्ला रही है, तो कोई तकलीफ है, तभी चिल्ला रही है। आंदोलन हमारे या आपके खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार के लिए होना चाहिए

जेन जी पर देश विरोधी होने के आरोप पर: अगर जेन जी आंदोलन कर रही है, तो वह एंटी-नेशनल नहीं है। वे अपने लोग हैं, हमारी अगली पीढ़ी हैं। उनसे हमारा संबंध है। उन्हें हमारी बात समझनी चाहिए और हमें उनकी बात समझनी चाहिए।

जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज पर: संघ प्रमुख ने कहा, यह क्यों हुआ, किसलिए हुआ, उसका कारण जानना होगा। इसे देखकर तय करना होगा कि कहां गड़बड़ है। मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। कुछ उपद्रवी शामिल हुए। अगर मुझे आंख मूंदकर भरोसा करना है, तो मैं जेन जी पर कर सकता हूं।

शिक्षण संस्थानों की दुर्दशा पर: शिक्षा कमर्शियल बिजनेस नहीं है। वह सर्वसुलभ हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि सरकार ही पूरी शिक्षा चलाए। हमें भी सहयोग करना होगा।

90 साल बाद एएसआई फिर शुरू करेगा बौद्ध स्तूप की खोदाई

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) मिलकर उज्जैन स्थित 'वैश्य टेकरी' के विशाल बौद्ध स्तूप की नए सिरे से खोदाई कराने की तैयारी कर रहे हैं। जहां मौर्य सम्राट अशोक के काल का करीब 2,200 साल पुराने प्राचीन बौद्ध स्तूप दबे होने की संभावना है। यह स्तूप सांची से भी बड़ा बताया जाता है।

दरअसल, उज्जैन के वैश्य टेकरी में स्थित इस विशाल टीले की 1938-39 में ब्रिटिश शासन के दौरान आंशिक खोदाई हुई। इस दौरान जहरीली गैस के रिसाव से मजदूरों के बेहोश होने के कारण इसका काम रोक दिया गया था। अब लगभग नौ दशकों (90 साल) बाद, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। एमपी सरकार एएसआई के साथ मिलकर नए सिरे से खोदाई करने की तैयारी में है। ब्रिटिश काल की पुरातात्विक रिपोर्ट के अनुसार, उज्जैन स्थित इस स्तूप का व्यास 350 फीट और ऊंचाई कम से कम 100 फीट दर्ज की गई थी।

ओबीसी का ए और बी में बंटवारा ही गलत, हाई कोर्ट ने रद कर दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट

ब्लिट्ज ब्यूरो

यह सर्वेक्षण केवल लगभग 2,500 नमूनों पर आधारित था

कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में, पश्चिम बंगाल की पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के नियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया है। ये प्रमाणपत्र ओबीसी -ए और ओबीसी-बी श्रेणियों के तहत जारी किए गए थे। हाई कोर्ट ने बुधवार (12 अगस्त) को अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ओबीसी-ए और ओबीसी-बी का वर्गीकरण ही अस्तित्व में नहीं है। जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि इस वर्गीकरण के तहत जारी प्रमाणपत्रों ने अपनी वैधता खो दी है।

ओबीसी श्रेणियों को लेकर यह विवाद वर्ष 2010 के बाद तब सामने आया, जब राज्य सरकार ने ओबीसी समुदायों को दो श्रेणियों ओबीसी-ए और ओबीसी-बी में विभाजित कर दिया था। इसके बाद ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस मामले को अदालत में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद 2024 में हाई कोर्ट ने ओबीसी सूची में 66 समुदायों को शामिल करने के फैसले को रद कर दिया था और उनके प्रमाणपत्र भी निरस्त कर दिए थे।

अदालत ने तब राज्य सरकार को एक नया सर्वेक्षण कराने और नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।

सरकार ने दी थी चुनौती

तत्कालीन राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय के निर्देशों के बाद राज्य ने एक नया सर्वेक्षण कराया और ओबीसी -ए और ओबीसी-बी सूचियों में बदलाव किए। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कोर्ट का कहना था कि यह सर्वेक्षण केवल लगभग 2,500 नमूनों पर आधारित था और उसी के आधार पर 142 समुदायों को बाद में ओबीसी सूची में शामिल कर लिया गया। राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों के खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, इस बार भी राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली। नतीजतन, संशोधित नियमों के तहत ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने का सिलसिला जारी रहा।

भाजपा सरकार आने के बाद बदली स्थिति

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के सत्ता में आने के बाद इस मामले की कानूनी स्थिति पूरी तरह बदल गई। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नयी सरकार ने ओबीसी-ए और ओबीसी-बी के वर्गीकरण को खत्म करते हुए एलान किया कि राज्य में केवल एक ही एकल ओबीसी आरक्षण श्रेणी होगी। इसके साथ ही, सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका को भी उच्चतम न्यायालय से वापस ले लिया, जिसे पिछली ममता सरकार ने दायर किया था। चुनौती याचिका वापस लिए जाने के बाद, टीएमसी सरकार की संशोधित व्यवस्था के तहत जारी किए गए सभी प्रमाणपत्रों का कानूनी आधार समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बुधवार को उच्च न्यायालय ने यह अंतिम आदेश सुनाया।

इस फैसले का सीधा असर उन लोगों पर पड़ने की संभावना है जिन्होंने उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान और उसके बाद आवेदन करके नए वर्गीकरण वाले ओबीसी प्रमाणपत्र प्राप्त किए थे।

असम में कांग्रेस के मंसूबों पर बदरुद्दीन ने फेरा पानी

ब्लिट्ज ब्यूरो

गुवाहाटी। असम में नागांव लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले एआईयूडीएफ ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ऑल-इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया है। अजमल ने एलान किया कि उनकी पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और रेजाउल करीम सरकार एआईयूडीएफ के प्रत्याशी होंगे। बता दें कि नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव मौजूदा कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद होने जा रहा है। बोरदोलोई ने इस साल अप्रैल में दिसपुर

विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसके बाद नागांव लोकसभा सीट खाली हो गई।

अजमल ने कांग्रेस पर बोला हमला

बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एआईयूडीएफ कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने कांग्रेस को देश और असम की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। अजमल ने कांग्रेस को बीजेपी की 'बी-टीम' तक करार दिया और स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।

वाजेद अली चौधरी ने फैसले पर उठाए सवाल

वहीं, असम में विपक्ष के नेता वाजेद अली चौधरी ने एआईयूडीएफ के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एआईयूडीएफ ने दबाव में आकर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। चौधरी के मुताबिक, कांग्रेस ने एआईयूडीएफ से नागांव सीट पर समर्थन देने की अपील की थी, लेकिन उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि एआईयूडीएफ उनकी बात नहीं मानेगी। चौधरी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय एआईयूडीएफ ने नागांव सीट पर उम्मीदवार उतारा था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जीत हासिल करने में सफल रही थी। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी एआईयूडीएफ के उम्मीदवार के मैदान में उतरने के बावजूद कांग्रेस नागांव सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी।

सियालदह– जयनगर गंगासागर एक्सप्रेस में लगे आधुनिक एलएचबी कोच

कोलकाता। कोलकाता के सियालदह से बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर के बीच प्रतिदिन चलने वाली 13185/13186 गंगासागर एक्सप्रेस में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आधुनिक एलएचबी (लिंक हाफमैन बुश) कोच लगा दिए गए हैं।

पुराने आइसीएफ कोचों की जगह अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक एलएचबी कोचों वाली रेक के साथ गंगासागर एक्सप्रेस ने विगत दिवस सियालदह स्टेशन से अपनी पहली यात्रा शुरू की। ट्रेन के आधुनिक रूप को देखकर यात्रियों में भी काफी उत्साह और खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर सियालदह स्टेशन पर पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (पीसीसीएम) डा. उदय शंकर झा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

राज्यसभा सांसद नागेंद्रनाथ रॉय से 'बंग विभूषण' सम्मान वापस लिया गया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यसभा सांसद नागेंद्रनाथ रॉय उर्फ अनंत महाराज से 'बंग विभूषण' सम्मान वापस ले लिया है। यह सम्मान उन्हें इसी साल के फरवरी में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया था।

राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने विगत दिवस इसे रद करने का आदेश जारी किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में उनके कथित अपमानजनक बयानों के कारण इस सम्मान को वापस ले लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिया?

यह कदम तब उठाया गया जब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया पर नेताजी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी समेत सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि कानून सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होगा।

बंगाल के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का अध्याय

ब्लिट्ज ब्यूरो

अलग से पुस्तक भी प्रकाशित होगी, बनेगा संग्रहालय

कोलकाता। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके जीवन और योगदान को स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल करने का बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नवान्न में आयोजित विशेष समिति की पहली बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल शिक्षा विभाग की पहल पर पाठ्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके बलिदान से जुड़ा अध्याय शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, विचार और उनके बलिदान को लंबे समय तक पर्याप्त रूप से सामने नहीं लाया गया। इसके पीछे

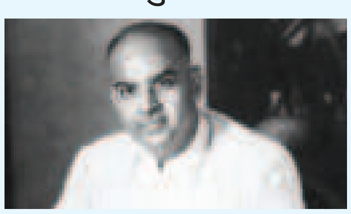

राजनीतिक कारण रहे हैं। अब राज्य सरकार उनके योगदान को समाज के हर स्तर तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर राज्य सरकार ने पूरे वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इसी सिलसिले में उनके जीवन और कार्यों से जुड़े फैसले लेने के लिए विशेष समिति का गठन किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी और उनके आत्मबलिदान को स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उनके जीवन पर अलग से पुस्तक भी प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस संस्था से कभी जुड़े रहे थे, उसकी पहल पर तथागत राय के प्रयास से एक पुस्तक तैयार की गई है। राज्य सरकार की इच्छा है कि संबंधित संस्था के साथ मिलकर उस पुस्तक का प्रकाशन किया जाए। इसके साथ ही राज्य के पुस्तकालय विभाग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विस्तृत जीवनी पर एक अलग पुस्तक तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने हुगली के जीरट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक आवास के संरक्षण और पुनरुद्धार का काम भी शुरू किया है। उनके जीवन और योगदान से संबंधित एक संग्रहालय भी तैयार किया जाएगा।

जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, समिति का गठन

रांची। झारखंड की रांची स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर की न्यास समिति को लेकर चल रहे विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से पेश स्कीम के अध्ययन के लिए समिति का गठन कर दिया। यह समिति स्कीम का अध्ययन कर तीन सितंबर को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और सात सितंबर को सुनवाई होगी। 11 सदस्यीय समिति में महाधिवक्ता रोहितश्व राय को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गयी है। समिति में झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक और रांची के उपायुक्त मंजूनाथ को भी शामिल किया गया है।

थलपति विजय की बढ़ेगी टेंशन, कर्नाटक के नए मंत्री ने मेकेदातु प्रोजेक्ट में तेजी लाने का दिया आदेश

विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक, दिए सख्त निर्देश

ब्लिट्ज ब्यूरो

बेंगलुरु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि कर्नाटक सरकार मेकेदातु परियोजना पर बड़ा कदम उठाने जा रही है। कर्नाटक के नवनियुक्त जल संसाधन मंत्री एन चेलुवरायस्वामी ने अधिकारियों को मेकेदातु पेयजल परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने परियोजना से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की देरी नहीं होने देने को कहा है।

पदभार संभालते ही एक्शन में मंत्री

दरअसल पदभार संभालने के तुरंत बाद एन चेलुवरायस्वामी ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मेकेदातु परियोजना की मौजूदा स्थिति, सामने आ रही चुनौतियों और आगे की कार्ययोजना की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि मेकेदातु परियोजना केवल सिंचाई से जुड़ी योजना नहीं है बल्कि यह बेंगलुरु समेत राज्य के प्रमुख शहरी क्षेत्रों की भविष्य की पेयजल सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में टिकाऊ पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए यह परियोजना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना के किसी भी चरण में देरी से बचने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

मेकेदातु परियोजना के बारे में जाना

बैठक में चेलुवरायस्वामी ने विस्तृत परियोजनाऔ रिपोर्ट (डीपीआर), केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरियों, पर्यावरण एवं वन मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, तकनीकी पहलुओं और कर्नाटक के हितों की रक्षा करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने की रणनीति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी परिस्थिति में कर्नाटक की जनता के पेयजल अधिकारों और राज्य के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। परियोजना के हर चरण में कानूनी और तकनीकी मानकों का पालन होना चाहिए तथा जरूरी मंजूरियां हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।

केंद्र से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा

मंत्री ने अधिकारियों को अब तक उठाए गए कदमों, लंबित मंजूरियों और अगले चरण में किए जाने वाले उपायों को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

उन्होंने संबंधित सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। साथ ही जरूरी दस्तावेज और तकनीकी जानकारी तैयार करने और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि कर्नाटक का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सके।

पानी लोगों की बुनियादी जरूरत

चेलुवरायस्वामी ने कहा कि बेंगलुरु और अन्य शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को देखते हुए भविष्य की पेयजल मांग को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करना जरूरी है।

बैठक के अंत में मंत्री ने अधिकारियों को मेकेदातु परियोजना की मौजूदा स्थिति, प्रमुख लंबित मुद्दों और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदमों को शामिल करते हुए स्पष्ट और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा कर जल्द से जल्द आगे की कार्ययोजना पर रिपोर्ट सौंपने को कहा। मेकेदातु परियोजना को कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाकर नया गति देने के सरकार के प्रयासों के बीच यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

महिलाओं के लिए फ्री बस योजना पर केरल के मंत्री के बयान पर बवाल

कहा, बस के पैसे नहीं, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है

ब्लिट्ज ब्यूरो

तिरुवनंतपुरम। केरल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सी.पी. जॉन ने राज्य सरकार की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना पर टिप्पणी करके एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। केरल बस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राज्य सम्मेलन में मंत्री ने कहा कि केरल के लोगों का व्यवहार और उनके व्यवहार-विज्ञान को समझना और उस पर अमल करना कोई आसान काम नहीं है। कोई अमीर आदमी गरीब या बेसहारा होने का नाटक कर रहा है, नाटक करना कोई मामूली बात नहीं है लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती, वह यह है, एक महिला जिसके पास बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, वह फिर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजती हैं। अगर बिना फीस वाले सरकारी स्कूलों में सीटें उपलब्ध हों, तब भी वह अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूल में भेजती है जहां फीस लगती है।

सरकारी अस्पताल में इलाज को लेकर भी तंज

मंत्री ने आगे कहा कि हालांकि, जब बात हेल्थकेयर की आती है, तो वही महिला अपने पिता या पति के साथ सरकारी अस्पताल आती है और इलाज के लिए जमीन पर भी लेट जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और हेल्थकेयर के क्षेत्रों में केरल के लोगों का व्यवहार मुझे सचमुच हैरान करता है। वे खचाखच भरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में सफर करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन जब उन्हें इलाज की जरूरत होती है, तो वे प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते, क्योंकि उन्हें अस्पताल के बिलों से डर लगता है।

मंत्री बोले- अपनी बात पर कायम

मंत्री की इन टिप्पणियों की आम जनता और राजनीतिक हलकों में काफी आलोचना हो रही है। विवाद बढ़ा लेकिन मंत्री ने फिर दोहराया कि वह अपनी बात पर कायम हैं। जॉन ने कहा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पास घूमने-फिरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। दुख की बात यह है कि राजनीतिक नेतृत्व, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनकी गरीबी को समझने में नाकाम रहा। मैं यही बात कह रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बातों का गलत मतलब न निकाला जाए।

अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिलने पर युवाओं ने घास खाकर जताया विरोध

तिरुवनंतपुरम। केरल में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार अनूठा प्रदर्शन सामने आया है। विगत दिवस तिरुवनंतपुरम के सचिवालय के बाहर लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर (एलपीएसटी) रैंक होल्डर्स ने घास खाकर विरोध जताया। सचिवालय के बाहर जुटे एलपीएसटी रैंक होल्डर्स ने कहा कि पीएससी रैंक लिस्ट में शामिल होने के बावजूद उन्हें अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं मिले हैं। यह प्रोटेस्ट ऐसे वक्त पर सामने आया है जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और युवाओं को नौकरी नहीं मिलने के मुद्दे को खूब उठा रहे हैं।

10 दिन से चल रही भूख हड़ताल

तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन में शामिल एक प्रोटेस्टर ने कहा कि हम यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भूख हड़ताल शुरू

हुए 10 दिन हो गए हैं। यह दुख की बात है कि सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है या हमें इस बारे में बात करने के लिए सकारात्मक बातचीत के लिए भी नहीं बुला रही है कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। पहले उन्होंने हमसे कहा था कि अगर वे पावर में आए, तो वे हमारी जरूरतें पूरी करेंगे और जो भी जरूरी होगा वह करेंगे। हम अपनी मांगें रख रहे हैं। हमने इन पोस्ट के लिए बहुत मेहनत की है। अगर कल हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो सरकार को कम से कम हमें बुलाना चाहिए।

सीएम विजय को देश से प्यारा राज्य, वंदे मातरम् से पहले बजेगा तमिल राज्य गीत

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। तमिलनाडु में वंदे मातरम् और तमिल राज्य गीत (तमिल थाई वाजथू) को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में एक नया बिल पारित हुआ है। इस प्रस्ताव के मुताबिक, तमिलनाडु में अब सभी सरकारी कार्यक्रमों, शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों , सरकारी दफ्तरों और सार्वजनिक कार्यक्रमों की शुरुआत 'तमिल थाई वाजथू' से होगी।

मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि तमिलनाडु में राज्यगीत को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 'तमिल थाई वाजथू' को पहला स्थान देना राज्य का अधिकार है और उनकी सरकार राज्य के भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों से समझौता नहीं करेगी। विधानसभा में भाषण देते हुए विजय ने कहा, 'तमिल हमारी भाषा ही नहीं, हमारी जीवनरेखा और भावनाएं है। ये भाषा राज्य की पहचान और भावना से जुड़ी है।'

तमिलनाडु सरकार के नए प्रस्ताव से केंद्र के इस निर्देश और राज्य के फैसले के बीच टकराव के आसार बन रहे हैं। हालांकि विधानसभा में विजय ने इसे तमिलनाडु के

भाषाई और सांस्कृतिक अधिकारों से जोड़ते हुए अपना रुख साफ किया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकारी कार्यक्रमों में पहले राष्ट्रगीत और फिर राष्ट्रगान बजाने का निर्देश जारी किया था। 9 जुलाई को जारी एक एडवाइजरी में सरकार ने राज्यों से उस निर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

'तमिल थाई वाजथू' को लेकर विवाद तब बढ़ा जब मई में एक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में तमिल राज्यगीत को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बाद तीसरे क्रम में बजाया गया था। इसके कुछ सप्ताह बाद विजय की पार्टी के 23 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के कार्यक्रम में भी राज्यगीत तीसरे क्रम पर रखा गया। टीवीके ने इसके लिए राज्यपाल कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया था इसके बाद तमिलनाडु के 21 सांसदों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मांग की थी कि सरकारी कार्यक्रमों में 'तमिल थाई वाजथू' को पहले और राष्ट्रीय गीत को बाद में रखने की व्यवस्था की जाए।

'तमिल थाई वाजथू' का इतिहास

'तमिल थाई वाजथू' की रचना मनोन्मणियम सुंदरनार के 1891 में लिखे गए नाटक 'मनोन्मणियम' से ली गई है। इस गीत में पूरे भारतवर्ष को एक सुंदर स्त्री के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें दक्षिण का द्रविड़ क्षेत्र उस स्त्री का माथा है और तमिल भाषा उस पर तिलक की तरह है। साल 1970 में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि ने मूल कविता से संस्कृत से तुलना करने वाली कुछ पंक्तियों को हटाकर इसे केवल तमिल की प्रशंसा तक सीमित कर दिया था।

एआई गीगाफैक्ट्री के भीतर होता क्या है?

एआई गीगा फैक्टरियों के संचालन से जुड़ी एक बड़ी चुनौती भी है। एआई आधारित कंप्यूटिंग के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और इससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है।

ब्लिट्ज विशेष

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) गीगाफैक्ट्री एक विशाल, अत्याधुनिक और विशेष रूप से निर्मित कंप्यूटिंग केंद्र है जहां बड़े पैमाने पर उन्नत एआई मॉडल विकसित किए जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, और अधिक सक्षम बनाया जाता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

सामान्य कारखानों में जहां भौतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, वहीं एआई गीगाफैक्ट्री का मुख्य उत्पाद उन्नत एआई मॉडल और एआई आधारित डिजिटल सेवाएं होती हैं। दूसरे शब्दों में, यहां मशीनें या उपभोक्ता वस्तुं नहीं, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नई क्षमताएं विकसित की जाती हैं।

ऐसी गीगाफैक्टरियों में आमतौर पर हजारों अत्यधिक शक्तिशाली एआई चिप्स (जीपीयू और अन्य विशेष एआई प्रोसेसर) स्थापित होते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से एनवीडिया, एएमडी जैसी दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियां करती हैं।

इन केंद्रों में उच्च क्षमता वाले सर्वर, अति-तेज डेटा नेटवर्क, विशाल डेटा भंडारण प्रणाली और अत्यंत सुरक्षित क्लाउड अवसंरचना उपलब्ध होती है। इसके माध्यम से शोधकर्ता, स्टार्टअप, उद्योग और प्रौद्योगिकी कंपनियां दुनिया के किसी भी हिस्से से इस विशाल कंप्यूटिंग क्षमता का दूरस्थ रूप से उपयोग कर सकती हैं।

हालांकि, एआई गिगाफैक्ट्रियों के संचालन से जुड़ी एक बड़ी चुनौती भी है। एआई आधारित कंप्यूटिंग के लिए भारी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और इससे अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है। इसलिए इन केंद्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ अत्याधुनिक और उच्च क्षमता वाली शीतलन (कूलिंग) प्रणाली की भी आवश्यकता होती है।

यही कारण है कि एआई गिगाफैक्ट्रियों की ऊर्जा खपत, बिजली की बढ़ती मांग और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को लेकर आज पूरी दुनिया में गंभीर चर्चा हो रही है। जैसे-जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार तेज़ी से हो रहा है, वैसे-वैसे ऊर्जा-कुशल, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल गीगाफैक्टरियों का विकास वैश्विक प्राथमिकता बनता जा रहा है।

एआई क्षेत्र में बढ़त बनाने के लिए यूरोप का बड़ा दांव

अमेरिका और चीन को टक्कर देने के लिए यूरोपीय संघ सात एआई गीगाफैक्टरियां स्थापित करेगा

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में अमेरिका और चीन से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत यूरोपीय संघ सात अत्याधुनिक एआई गीगाफैक्टरियों की स्थापना के लिए 10 अरब यूरो (लगभग 11.4 अरब अमेरिकी डॉलर) का सार्वजनिक निवेश करेगा। यह जानकारी गत 30 जुलाई को एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में दी गई है।

यूरोपीय आयोग का अनुमान है कि इस सरकारी निवेश के आधार पर निजी क्षेत्र से भी 20 अरब यूरो (लगभग 22.8 अरब अमेरिकी डॉलर) का अतिरिक्त निवेश आकर्षित किया जा सकेगा।

यूरोपीय आयोग में तकनीकी संप्रभुता (टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी) की जिम्मेदारी संभाल रहीं कार्यकारी उपाध्यक्ष हेन्ना विरक्कुनेन ने कहा, "कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास अभूतपूर्व गति से हो रहा है। ऐसे में एआई गीगाफैक्टरियों के माध्यम से उपलब्ध विशाल कंप्यूटिंग क्षमता तक पहुंच यूरोप के लिए अब एक रणनीतिक आवश्यकता बन गई है।"

तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में यूरोप का बड़ा कदम

ब्रुसेल्स लंबे समय से यूरोप को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। अब इन प्रयासों में और तेजी आ गई है क्योंकि यूरोपीय नेताओं का मानना है कि विदेशी तकनीकों पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में यूरोप के हितों के खिलाफ दबाव का साधन बन सकती है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार यूरोपीय संघ के तकनीकी नियमों की आलोचना कर चुके हैं जबकि चीन ने एआई उद्योग के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति पर नियंत्रण लगा दिया है।

एक लाख से अधिक अत्याधुनिक एआई चिप्स से लैस होंगी गीगाफैक्टरियों

यूरोपीय संघ ने अब इन गीगाफैक्टरियों के निर्माण के लिए कंपनियों से निविदाएं (बिड्स) आमंत्रित की हैं।

प्रत्येक गीगाफैक्ट्री में कम-से-कम एक लाख अत्याधुनिक एआई चिप्स लगाए जाएंगे। इनकी कंप्यूटिंग क्षमता वर्तमान में यूरोपीय संघ में संचालित डेटा सेंटरों की तुलना में लगभग चार गुना अधिक होगी।

फिलहाल यूरोपीय संघ के पास फिनलैंड से स्पेन तक फैले 19 एआई डेटा सेंटरों का नेटवर्क है। नई सात गीगाफैक्टरियां शुरू होने के बाद यूरोप की कुल कंप्यूटिंग क्षमता दोगुने से भी अधिक हो जाएगी।

एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन अभी भी आगे

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा वर्ष 2025 में किए गए आकलन के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यूरोप अभी भी अमेरिका और चीन से पीछे है।

चीन के पास डेटा सेंटरों के लिए विशाल विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध है जबकि निजी क्षेत्र से एआई में सबसे अधिक निवेश अमेरिका आकर्षित कर रहा है। दूसरी ओर, यूरोप में डेटा सेंटरों के लिए आवश्यक लाखों इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उत्पादन अभी सीमित है। इसके अलावा, यूरोप में बिजली की लागत अमेरिका और चीन की तुलना में दो से तीन गुना अधिक है। यह जानकारी यूरोपीय आयोग द्वारा जून में यूरोपीय संसद के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में दी गई थी।

मिस्ट्रल का प्रयास, लेकिन प्रतिस्पर्धा अभी भी कठिन

फ्रांस की मिस्ट्रल एआई फिलहाल पेरिस स्थित अपने परिसर में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े एआई डेटा सेंटरों में से एक का संचालन कर रही है।

मिस्ट्रल ने 'ले चैट' नामक चैटबॉट विकसित किया है लेकिन वह अभी तक अमेरिका की ओपनएआई के चैटजीपीटी और चीन की डीपसीक जैसी अग्रणी कंपनियों की बराबरी नहीं कर सकी है।

गोपनीयता और अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित यूरोप के कई नेताओं ने चिंता व्यक्त की है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकने वाली स्वदेशी एआई कंपनियों की यूरोप में अभी भी कमी है। इसके साथ ही एआई के तेजी से बढ़ते उपयोग का रोजगार, अर्थव्यवस्था और नागरिकों की व्यक्तिगत गोपनीयता पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर भी पूरे यूरोप में गंभीर बहस चल रही है।

डेटा सुरक्षा और नैतिक मानकों का सख्त पालन

यूरोपीय आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन गीगाफैक्टरियों में विकसित होने वाली सभी एआई सेवाएं और उत्पाद डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, सुरक्षा मानकों और नैतिक मूल्यों से जुड़े यूरोपीय संघ के सभी नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे। इसके लिए डिजिटल सर्विसेज एक्ट और डिजिटल मार्केट्स एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को लागू किया जाएगा।

मेहमानों की बहार

आजादी के बाद भारत के आतिथ्य उद्योग ने रचा विकास का नया इतिहास

आजादी के बाद भारत के आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी) क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 1947 में देशभर में जहां संगठित होटलों में केवल 5,000 कमरे उपलब्ध थे वहीं आज यह संख्या बढ़कर लगभग 2 लाख तक पहुंच चुकी है। यानी इस क्षेत्र में करीब 3,900 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस विषय पर ब्लिट्ज रिसर्च की ये शानदार रिपोर्ट पढ़िए...

ब्लिट्ज ब्यूरो

विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद (डब्ल्यूटीटीसी) के इकोनॉमिक इम्पैक्ट रिसर्च के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत के यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का कुल आर्थिक आकार 263.6 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें होटल, वाणिज्यिक विमानन, यात्री रेल सेवाएं, रेस्तरां, टूर ऑपरेटर, पर्यटन आकर्षण केंद्र तथा उनसे जुड़ी आपूर्ति श्रंखलाओं से उत्पन्न आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं।

वर्तमान में भारत की लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 5.2 से 6.6 प्रतिशत के बीच है।

पिछले आठ दशकों में भारत का आतिथ्य उद्योग पूरी तरह बदल चुका है। एक समय यह क्षेत्र मुख्यतः ब्रिटिश अधिकारियों, विदेशी मेहमानों और सरकारी प्रतिनिधियों तक सीमित था लेकिन आज यह 280 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य वाला देश के सबसे तेजी से विकसित होते सेवा क्षेत्रों में से एक बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी ताकत अब विदेशी पर्यटक नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों घरेलू यात्री हैं।

डब्ल्यूटीटीसी के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत के यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का कुल आर्थिक आकार 263.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

इसमें केवल होटल उद्योग ही नहीं, बल्कि विमानन सेवाएं, रेल परिवहन, रेस्तरां, पर्यटन सेवाएं, मनोरंजन उद्योग तथा उनसे जुड़े हजारों छोटे-बड़े व्यवसाय भी शामिल हैं।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में होने वाले कुल खर्च का 86 प्रतिशत से अधिक, यानी लगभग 203 अरब अमेरिकी डॉलर, भारतीय यात्रियों द्वारा किया गया जबकि विदेशी पर्यटकों का योगदान अपेक्षाकृत काफी कम रहा। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत का आतिथ्य उद्योग अब मुख्य रूप से घरेलू पर्यटन की मजबूत नींव पर खड़ा है।

1947 से 1980 का दौर : सरकारी पहल से रखी गई मजबूत नींव

आज़ादी के समय भारत को ब्रिटिश शासनकाल की होटल व्यवस्था विरासत में मिली थी। मुंबई का ताज महल पैलेस, नई दिल्ली का द इम्पीरियल और कोलकाता का द ग्रैंड होटल जैसे कुछ प्रतिष्ठित होटल ही उस समय देश के आतिथ्य उद्योग की पहचान थे।

आधारभूत सुविधाओं का अभाव

उस दौर में संगठित होटल बहुत कम थे। अधिकांश भारतीय यात्री धर्मशालाओं, सरायों, सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों अथवा निजी लॉज में ठहरते थे।

सरकार की निर्णायक पहल

वर्ष 1956 में आयोजित यूनेस्को सम्मेलन की मेजबानी के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में द अशोक होटल के निर्माण का निर्णय लिया। इसे भारत के आधुनिक आतिथ्य उद्योग की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

इसके बाद वर्ष 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) की स्थापना की गई जिसने देशभर में सरकारी होटलों और पर्यटन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास में अहम भूमिका निभाई।

निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी

इसी अवधि में ओबेरॉय समूह और ताज समूह जैसे भारतीय होटल समूहों ने देश के प्रमुख महानगरों के साथ-साथ राजस्थान, शिमला और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधुनिक होटल विकसित करने की शुरुआत की।

अब छोटे शहर भी बन रहे हैं विकास के नए केंद्र

आज भारत का आतिथ्य उद्योग केवल दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रह गया है।

अब दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में देश की आधे से अधिक नई होटल परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। यह दर्शाता है कि पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार तेजी से छोटे शहरों तक पहुंच रहा है।

हर वर्ग के यात्रियों के लिए बेहतर ठहरने की सुविधाएं

आज भारत में हर आय वर्ग और हर प्रकार के यात्री के लिए उसकी आवश्यकता और बजट के अनुरूप ठहरने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

इनमें शामिल हैं-

- लक्जरी होटल
- उच्च मध्यम श्रेणी के होटल
- मध्यम श्रेणी के होटल
- किफायती होटल
- व्यावसायिक होटल
- विरासत होटल
- होमस्टे
- पर्यावरण-अनुकूल रिसॉर्ट

वर्तमान में विकसित हो रही नई होटल परियोजनाओं में लगभग 39 प्रतिशत हिस्सेदारी मध्यम और उच्च मध्यम श्रेणी के होटलों की है। ये मध्यम वर्ग और बजट यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए जा रहे हैं।

तकनीक ने आतिथ्य उद्योग को दी नई पहचान

तकनीक आधारित होटल प्रबंधन कंपनियों ने देशभर के हजारों असंगठित किफायती होटलों को एक व्यवस्थित मंच से जोड़कर यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

इसके साथ ही होमस्टे, विरासत संपत्तियां और प्रकृति आधारित पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है। आज का यात्री केवल ठहरने की जगह नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली से जुड़ा एक यादगार अनुभव भी चाहता है।

घरेलू पर्यटन बना भारत के आतिथ्य उद्योग की सबसे बड़ी ताकत

आज़ादी के शुरुआती वर्षों में भारत का आतिथ्य उद्योग मुख्य रूप से विदेशी पर्यटकों पर निर्भर था लेकिन आज इस उद्योग की सबसे बड़ी ताकत भारतीय मध्यम वर्ग की बढ़ती आय, घरेलू पर्यटन का निरंतर विस्तार, व्यावसायिक और अवकाश यात्राओं का बढ़ता चलन तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन का अभूतपूर्व विकास है।

यही कारण है कि भारत का आतिथ्य उद्योग आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बाज़ारों में शामिल है। इसकी विकास यात्रा अब विदेशी पर्यटकों के बजाय देश के अपने करोड़ों यात्रियों की बढ़ती भागीदारी और मांग पर आधारित है।

आर्थिक सुधारों ने उद्योग को दी नई उड़ान

वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत के आतिथ्य उद्योग में तेज़ी से बदलाव आया।

इस दौर की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रहीं-

- होटल और पर्यटन क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति मिली।
- इसके बाद दुनिया की कई अग्रणी होटल श्रंखलाओं ने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया।

- सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्र के विस्तार के साथ वर्षभर व्यावसायिक यात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिससे होटल उद्योग को निरंतर नया कारोबार मिलने लगा।
- ऑनलाइन बुकिंग मंचों के आगमन से होटल आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह बदल गई और पारंपरिक ट्रैवल एजेंटों पर निर्भरता काफी घट गई।

यूरिया की एक सही खुराक बदल देगी धान की तस्वीर

इसमें शामिल नाइट्रोजन पौधों के लिए करती है प्राथमिक भोजन का काम

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। धान की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है और यूरिया इसका सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है। फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉ. हादी हुसैन के अनुसार, सही समय और सही मात्रा में यूरिया का इस्तेमाल करने से धान के पौधे मजबूत होते हैं, पत्तियां हरी-भरी रहती हैं और कल्लों से लेकर दानों के विकास तक बेहतर परिणाम मिलते हैं। हालांकि, ज्यादा मात्रा में यूरिया का उपयोग फसल और मिट्टी, दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

नाइट्रोजन सबसे मुख्य पोषक तत्व

डॉ हादी हुसैन ने बताया कि धान की फसल के उचित विकास और बेहतर पैदावार के लिए नाइट्रोजन सबसे मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। यूरिया में लगभग 46 प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, जो पौधों के लिए एक प्राथमिक भोजन का काम करती है। जब खेतों में यूरिया डाला जाता है, तो यह मिट्टी की नमी में घुलकर सूक्ष्मजीवों की मदद से अमोनियम और नाइट्रेट में बदल जाता है। इसी रूप में धान की जड़ें नाइट्रोजन को आसानी से अवशोषित करती हैं।

अमोनियम रूप को बहुत आसानी से सोखता है पौधा

धान की फसल जलमग्न खेत में उगाई जाती है, जहां यूरिया का अवशोषण विशेष प्रक्रिया द्वारा होता है। मिट्टी में घुलने के बाद यूरीएज एंजाइम यूरिया को अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित करता है। धान का पौधा अमोनियम रूप को बहुत आसानी से और तेजी से सोखता है। यह रासायनिक परिवर्तन पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचकर उनके जैविक कार्यों को सक्रिय करता है। समय पर मिला यह नाइट्रोजन धान के पौधों को शुरुआती अवस्था से ही मजबूत और निरोग बनाने में मदद करता है।

पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने का मुख्य आधार

नाइट्रोजन पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने का मुख्य आधार है। जब धान के पौधों को यूरिया के माध्यम से पर्याप्त नाइट्रोजन मिलती है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल का स्तर काफी बढ़ जाता है। इससे पत्तियां गाढ़ी हरी और चौड़ी हो जाती हैं। अधिक क्लोरोफिल होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है, जिससे पौधे अधिक मात्रा में भोजन बनाते हैं। नतीजा यह होता है कि पौधे तेजी से बढ़ते हैं और उनकी जीवन शक्ति बनी रहती है।

यूरिया पौधों के कोशिकीय विभाजन को बढ़ाता है

फसल की मजबूती उसके तने और जड़ों की बनावट पर निर्भर करती है। यूरिया पौधों के कोशिकीय विभाजन को बढ़ावा देता है, जिससे तना मोटा और मजबूत बनता है। मजबूत तने के कारण तेज हवा या बारिश में फसल के गिरने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके साथ ही, प्राथमिक अवस्था में यूरिया मिलने से जड़ों का फैलाव गहराई तक होता है, जिससे पौधे मिट्टी से अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों और पानी को आसानी से सोख पाते हैं।

कल्ले फूटने की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण

धान की खेती में कल्ले फूटने की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रोपाई के दो से तीन सप्ताह बाद यूरिया देने से पौधों में शाखाओं और कल्लों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। जितने ज्यादा स्वस्थ कल्ले निकलेंगे, फसल में बालियों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी। इसके बाद बालियां बनते समय दिया गया यूरिया दानों का आकार बड़ा करने, उनमें चमक लाने और उनका वजन बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है।

धान में यूरिया का छिड़काव कितना

धान में यूरिया का छिड़काव एक बार में करने के बजाय तीन अलग-अलग किस्तों में करना सबसे अधिक फायदेमंद रहता है। पहली खुराक रोपाई के समय, दूसरी खुराक कल्ले निकलते समय और तीसरी खुराक बालियां बनने की शुरुआती अवस्था में देनी चाहिए। यूरिया हमेशा खेत में हल्की नमी होने पर ही छिड़कना चाहिए। यदि खेत में बहुत अधिक पानी भरा हो, तो पहले पानी निकाल देना चाहिए, ताकि यूरिया बहकर बर्बाद न हो और जड़ें इसे सोख सकें।

नीम-कोटेड यूरिया

पारंपरिक यूरिया की तुलना में नीम-कोटेड यूरिया धान की फसल के लिए अधिक फायदेमंद साबित हुआ है। नीम का तेल यूरिया के घुलने की गति को धीमा कर देता है, जिससे नाइट्रोजन धीरे-धीरे और लंबे समय तक पौधों को मिलती रहती है। इससे नाइट्रोजन का वाष्पीकरण और पानी के साथ बहकर नुकसान होना काफी कम हो जाता है। इसके अलावा, नीम के प्राकृतिक गुणों के कारण मिट्टी में हानिकारक कीटों और रोगों का प्रकोप भी नियंत्रित रहता है।

यूरिया धान की फसल के लिए जितना फायदेमंद है, इसका अत्यधिक उपयोग उतना ही हानिकारक हो सकता है। जरूरत से ज्यादा यूरिया डालने से पौधा कोमल हो जाता है और उस पर कीट-पतंगों का हमला बढ़ जाता है।

इसलिए, मिट्टी की जांच करवाकर फास्फोरस और पोटाश के साथ संतुलित मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता और किसान को न्यूनतम लागत में धान की अधिकतम उपज मिलती है।

फसल सुरक्षा वैज्ञानिक डॉ हादी हुसैन ने बताया कि धान की फसल के उचित विकास और बेहतर पैदावार के लिए नाइट्रोजन सबसे मुख्य पोषक तत्व माना जाता है। यूरिया में लगभग 46 प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, जो पौधों के लिए प्राण वायु का काम करती है।

किसानों का जुगाड़, सुरंग से होती है 10 एकड़ खेत की ऑटोमेटिक सिंचाई

न पाइप लगाने का झंझट, न खेत में जाने की टेंशन

रांची। झारखंड की राजधानी रांची के इटकी क्षेत्र के जितने भी किसान हैं, वे खास तरीके से खेतों की सिंचाई करते हैं। दरअसल, यहां 5-5 एकड़ खेत किसानों के पास है। फिलहाल अभी धान रोपने का समय है और उसके लिए पानी की जरूरत काफी होती है। ऐसे में किसानों ने अपने खेत को खासतौर पर ऊपर से नीचे की तरफ स्टेप बाय स्टेप जाते हुए बनवाया है और उसके बाद हर के खेत के बाद दूसरे खेत के बीच के मेड में एक सुरंग बना दी है।

यहां के किसान किशन चौधरी बताते हैं कि इससे एक बार जब कुएं से एक खेत में पानी जाता है, तो एक खेत में पानी भरता है और फिर उस सुरंग से दूसरे खेत में चला जाता है और फिर दूसरे खेत की सुरंग से तीसरे खेत में चला जाता है। यानी कि पानी

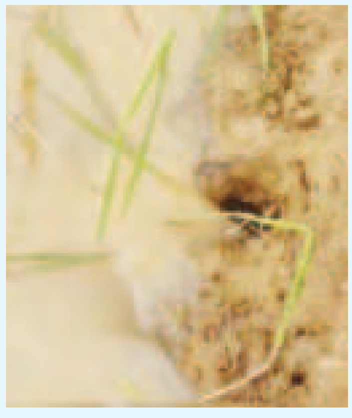

सिंचाई की कोई टेंशन ही नहीं है। यहां पर ऑटोमेटिक सारे खेतों में पानी जाते रहते हैं। न पाइप लगाने का झंझट, न खेत में जाने की टेंशन। इससे फसलें भी लहलहा उठती हैं।

किशन बताते हैं कि यहां पर खेत में आप देखेंगे एकदम लबालब पानी भरा रहता है और उससे एक फायदा और हमें यह मिलता है कि खेत में पानी जमा नहीं होता। बल्कि, पानी जितना ज्यादा होता है वह तीन चार सुरंग से दूसरे खेत में चला जाता है। फिर वहां से जो ज्यादा होता है वह तीसरे खेत में चला जाता है। इस तरीके से पानी आखिरकार एकदम नीचे आ जाता है।

जहां पर वह एक नाले के रूप में बाहर निकल जाता है। अब इससे फायदा यह हुआ कि पूरे दिनभर पूरे खेत में पानी जाता रहता है। जहां पानी जो बेकार है, वह बाहर की तरफ से निकल जाता है। यानी काफी अधिक पानी भी नहीं खराब होता और पानी की कमी भी नहीं रहती।

इससे एकदम बैलेंस बना रहता है। न हमें जाने की जरूरत, न देखने की टेंशन, 12 घंटे इस तरह की प्रक्रिया चलती रहती है। बता दें कि सुरंग बनाने का तरीका भी अनोखा है।

जैसे कि एक खेत की जो मेड है, उसमें आप सुरंग बना दीजिए और सुरंग ऐसी बनानी है कि दूसरे खेत के नीचे की तरफ वह निकले ताकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आराम से आ जाए। इस तरीके से 1 मिनट में तीन सुरंग बन जाती हैं। ताकि पानी उस सुरंग से ऊपर से नीचे की तरफ आए और फोर्स पानी का बढ़िया बना रहे। ऐसे में 10 एकड़ खेत में इसी तरीके से पानी जाता है और धान की सिंचाई होती है।

खेती के साथ शुरू करें मधुमक्खी पालन, मिलेगी सरकारी सब्सिडी

किसानों को दोतरफा लाभ की 'फुल गारंटी'

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। आजकल बहुत से किसान खेती के साथ-साथ अपनी कमाई बढ़ाने के नए तरीके ढूंढ़ रहे हैं। ऐसे में मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा तरीका बनकर सामने आया है। इसे शुरू करने में ज्यादा जमीन या भारी खर्च की जरूरत नहीं पड़ती, और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार भी इसके लिए सब्सिडी देती है।

मधुमक्खी पालन से किसानों को दो तरह का फायदा मिलता है। पहला, शहद बेचकर सीधी कमाई होती है। दूसरा, जब मधुमक्खियां खेत के आसपास फूलों पर बैठती हैं, तो इससे फसल भी अच्छी होती है और फल-सब्जी ज्यादा लगते हैं। यानी किसान को एक साथ दो फायदे मिलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए पैसों की मदद देती हैं। नेशनल बी-कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत मधुमक्खी के बॉक्स खरीदने, ट्रेनिंग लेने और शहद निकालने की मशीन लगाने पर पैसा मिलता है। हर

राज्य में यह रकम और नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए सही जानकारी के लिए अपने राज्य के किसान विभाग से संपर्क करना चाहिए।

मधुमक्खी पालन से होने वाली कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि कितने बॉक्स लगाए गए हैं और शहद कितना अच्छा है। शुरुआत में कम बॉक्स से भी ठीक-ठाक कमाई शुरू हो जाती है, और समय के साथ बॉक्स बढ़ाकर कमाई भी बढ़ाई जा सकती है। शहद के अलावा मोम और दूसरी चीजें बेचकर भी अतिरिक्त पैसा कमाया जा सकता है।

मधुमक्खी पालन से होने वाली कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि कितने बॉक्स लगाए गए हैं और शहद कितना अच्छा है। शुरुआत में कम बॉक्स से भी ठीक-ठाक कमाई शुरू हो जाती है, और समय के साथ बॉक्स बढ़ाकर कमाई भी बढ़ाई जा सकती है। शहद के अलावा मोम और दूसरी चीजें बेचकर भी अतिरिक्त पैसा कमाया जा सकता है।

सही ट्रेनिंग जरूरी

मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले सही ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र, खादी ग्रामोद्योग और कई राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त या कम कीमत में ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बॉक्स की देखभाल, मधुमक्खियों को बीमारी से बचाने और शहद निकालने का सही तरीका सिखाया जाता है।

मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले सही ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र, खादी ग्रामोद्योग और कई राज्य सरकारों की तरफ से मुफ्त या कम कीमत में ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बॉक्स की देखभाल, मधुमक्खियों को बीमारी से बचाने और शहद निकालने का सही तरीका सिखाया जाता है।

विभाग की वेबसाइट पर करें आवेदन

सरकारी मदद पाने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि या बागवानी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। इसके लिए जमीन के कागजात, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स जैसे कागज जमा करने होते हैं। आवेदन मंजूर होने के बाद ही पैसा मिलता है। सरकारी मदद पाने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि या बागवानी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन करना होता है। इसके लिए जमीन के कागजात, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स जैसे कागज जमा करने होते हैं। आवेदन मंजूर होने के बाद ही पैसा मिलता है।

ऐसे करें तैयारी

मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले मधुमक्खी के बॉक्स चाहिए। इसके साथ ही मधुमक्खियों का एक झुंड भी चाहिए होता है, जो किसी अनुभवी बी-कीपर या सरकारी सेंटर से खरीदा जा सकता है। शुरुआत में 10-20 बॉक्स से भी यह काम शुरू किया जा सकता है, और धीरे-धीरे इसे बढ़ाया जा सकता है। मधुमक्खी के बॉक्स को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आसपास फूल वाले पौधे या फसलें हों, क्योंकि मधुमक्खियां इन्हीं फूलों से रस लेकर शहद बनाती हैं। खेत के किनारे या बगीचे के पास की जगह इसके लिए सबसे सही रहती है। बॉक्स को सीधी तेज धूप और तेज हवा से बचाकर रखना चाहिए।

गमले में उगाएं तोरई, आसान है तरीका

ब्लिट्ज ब्यूरो

बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत

नई दिल्ली। सीजन कोई भी हो, हरी सब्जियों का मौसम कभी नहीं जाता। गर्मियों में तो वैसे भी हरी सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा सेवन की सलाह दी जाती है। हरी सब्जियों में शुमार तोरई (तुरई) स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। यह सब्जी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। खून साफ करती और पेट से जुड़ी समस्याएं भी दूर करती है। तोरई को घर की छत या किचन गार्डन में लगाना बहुत आसान है। 45 से 60 दिनों में पौधे फल देने लगते हैं। यानी तोरई तोड़ने लायक हो जाती है।

कैसे उगाएं: तोरई की सब्जी हर घर में की जरूरत है। हर सीजन में बनती है। बाजार में मिलने वाली तोरई की क्वालिटी को लेकर भी चिंता रहती है। ऐसे में घर की छत पर गमले में भी ऑर्गेनिक तरीके से इसे उगाया जा सकता है। बिना केमिकल वाली तोरई को खाने का मजा भी अलग ही है। घर की उगाई तोरई हेल्दी भी होती है। गमले में या ग्रो बैग में तोरई उगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा पैदावार लेने के लिए कई बातों का ध्यान रखना चाहिए।

तीन बार तोड़ाई

वैसे तो तरई (तुरई) की खेती मुख्य रूप से साल में तीन बार की जाती है। फरवरी से मार्च (गर्मी के मौसम के लिए), जून से जुलाई (बरसात या खरीफ के मौसम के लिए), और अक्टूबर से नवंबर (रबी के मौसम के लिए)। तोरई की बेल आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। शर्त यह है कि अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद लें। बीज लगाने से पहले मिट्टी तैयार करनी होती है। मिट्टी जितनी अच्छे से हम तैयार करेंगे, जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होगा। बीज को पहले डिस्पोजल गिलास में बो सकते हैं।

जर्मिनेशन के बाद बेल को बड़े गमले में ट्रांसफर किया जा सकता है।

बेल वाले पौधों को लगाने के लिए बड़े गमले या ग्रो बैग की जरूरत होती है। ग्रो बैग 18x18 का या फिर 21x21 का होना चाहिए। अगर आप नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो गोबर की खाद या वर्मिपोस्ट, मिट्टी और कोकोपीट तीनों को बराबर-बराबर मिला लें। थोड़ी सी नीम की खली और थोड़ा सा जिप्सम मिला लें। किसी तरह का फंगस न लगे, इसलिए मिट्टी में थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिला लें। सभी को अच्छे से मिक्स कर लें।

बीज लगाने से पहले उन्हें 10-12 घंटे के लिए पानी में भिगो लें। अगर आप बारिश के सीजन में लगा रहे हैं तो सूखे बीज भी लगा सकते हैं। एक इंच का गड्ढा बनाएं और उसमें बीज रख दें। थोड़ा सा दबाएं और ऊपर से मिट्टी ढंक दे। बड़े ग्रो बैग में 3-4 बीज ही लगाए जा सकते हैं। बीज लगाने के बाद अगर धूप खिली हो तो पानी डाल दें। अगर बारिश होने की संभावना हो तो पानी ना डालें। अगर बीज लगाने के बाद दो-तीन दिन बारिश हो रही हो तो गमले/ग्रो बैग को प्लास्टिक शीट से ढंक दें ताकि बीज गल नल जाए।

लगभग 10 दिन में जर्मिनेशन होने लगता है

जर्मिनेशन के बाद बेल तेजी से बढ़ती है। एक माह में ही बेल को सपोर्ट चाहिए होता है। बेल वाले पौधों की अच्छी पैदावार के लिए क्रीपर नेट जरूरी होता है। क्रीपर नेट ना हो तो बेल को सपोर्ट देने के लिए बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करें। या फिर रस्सी के सहारे बेल को बांध दें और दीवार पर चढ़ा दें। नेट भी लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का भी रखें कि ग्रो बैग/गमला ऐसी जगह रखें जहां धूप आए।

गोबर की खाद का कम इस्तेमाल करें

बरसात के समय में तोरई लगाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि गोबर की खाद का कम इस्तेमाल करें। वर्मिपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी धूप निकले और गमले की मिट्टी सूख जाए तो गोबर की खाद डाल सकते हैं। 10-15 दिन में खाद जरूर डालें। इससे पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी। समय-समय पर हल्की निराई करते रहें। इससे फ्रूटिंग भी ज्यादा होगी। करीब 50-55 दिन बाद बेल में तोरई लगने लगती है।

बारिश के मौसम में भेड़पालकों की कमाई पर लग सकता है 'फुलस्टॉप'

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान खेती के साथ भेड़ पालन से अच्छी अतिरिक्त आमदनी कमा रहे हैं, लेकिन बरसात का मौसम उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। बारिश, नमी और गंदगी के कारण भेड़ों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पशु विशेषज्ञों के अनुसार, इस मौसम में कुछ जरूरी बातों का ध्यान देकर भेड़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

सीमांत किसानों के लिए भी लाभदायक

लखीमपुर खीरी जिले में आज भी बड़ी संख्या में किसान पारंपरिक तरीके से भेड़ पालन कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। खेती के साथ भेड़ पालन किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई का अच्छा जरिया बन गया है। भेड़ों से ऊन, मेमनों की बिक्री और खाद के रूप में भी किसानों को फायदा मिलता है। कम लागत में शुरू होने वाला यह व्यवसाय छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी लाभदायक साबित हो रहा है।

भेड़ों की सेहत के लिए खतरनाक मौसम

बरसात के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी भेड़ों की सेहत पर असर डाल सकती है। कई बार सही देखभाल न होने पर भेड़ बीमार पड़ जाती हैं और उनकी मौत तक हो सकती है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए बारिश के दिनों में भेड़ों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है।

नमी, कीचड़ और गंदगी

बारिश के मौसम में नमी, कीचड़ और गंदगी

बढ़ने के कारण भेड़ों में कई तरह के बैक्टीरियल, वायरल और परजीवी रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय रहते बचाव के उपाय न किए जाएं तो एक भेड़ से बीमारी पूरे झुंड में फैल सकती है। इसलिए इस मौसम में बाड़े की साफ-सफाई, संतुलित आहार और भेड़ों की नियमित जांच करना बेहद जरूरी है।

सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी

बरसात के दौरान भेड़ों को हमेशा सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। कई बार बारिश का पानी बाड़े में भर जाता है, जिससे वहां नमी बढ़ जाती है

ध्यान रखें कि भेड़ों के रहने वाली जगह पर पानी जमा न हो और फर्श हमेशा सूखा रहे। लगातार गीले स्थान पर रहने से भेड़ों के खुर गलने लगते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बाड़े की नियमित सफाई करें और समय-समय पर चूना या पशुपालन विभाग द्वारा बताए गए कीटाणुनाशक का छिड़काव करते रहें।

ज्यादा गीला या सड़ा-गला चारा भेड़ों के लिए नुकसानदायक

बरसात के मौसम में खेतों में हरा चारा आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा गीला या सड़ा-गला चारा भेड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे अपच, दस्त और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

छात्रों पर पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए समिति गठित

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रेड्डी 5 सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी के अध्यक्ष

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। पेपर लीक के मुद्दे पर संसद मार्च के दौरान आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और ज्यादती की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अगुवाई में 5 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (एचपीईसी) का गठन किया है। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही, उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति से कहा कि आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा अत्यधिक बल और हिंसा (जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल भी शामिल है) की जांच करें। कोर्ट ने आंदोलन के दौरान पुलिस अधिकारियों व अन्य सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की भी जांच का आदेश दिया है।

देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रेड्डी के अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व पुलिस महानिदेशक एल.आर. बिश्नोई को शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन कई बातों को ध्यान में रखकर किया है, जिनमें इसके हर सदस्य की अपनी विशेषज्ञता और अनुभव, साथ ही कमेटी की विविधता और अन्य कारक शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 अगस्त पारित आदेश (जिसे 20 अगस्त को अपलोड किया गया) में कहा है 'हमें भरोसा है कि उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति की सिफारिशें इस अदालत के लिए बहुत मददगार साबित होंगी और उम्मीद जाहिर की है कि समिति उन

सभी मुद्दों का व्यापक मूल्यांकन कर पाएगी जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।'

पीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि पूरी सावधानी बरतते हुए, एचपीईसी की जांच सिर्फ एक बार की जाने वाली प्रक्रिया नहीं होगी। पीठ ने समिति से कहा कि वह मुद्दों का लगातार और समय-समय पर मूल्यांकन करे और समय-समय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट इस अदालत को सौंपे। पीठ ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान पुलिस बलों को लगी चोटों, और उसके कारण उनके परिवारों को हुए मानसिक और भावनात्मक सदमे को भी याचिकाकर्ताओं की शिकायतों के बराबर ही महत्व और विचार दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने मामले को पहले ही साफ कर दिया था कि आरोप गंभीर हैं और इसकी स्वतंत्र जांच की जरूरत है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की जांच को प्राथमिकता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति को कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करने को कहा है, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। पीठ ने कहा कि एचपीईसी दोनों पक्षों-चाहे पुलिसकर्मी हों या प्रदर्शनकारी-में से घायल हुए लोगों को अंतरिम मुआवजा देने के मुद्दों पर भी विचार कर सकता है। अपने आदेश में कोर्ट ने समिति से प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों की हरकतों से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर भी रिपोर्ट सौंपने को कहा। इसमें सरकारी प्रतिष्ठानों, वाहनों और राज्य व निजी नागरिकों की अन्य संपत्तियों को हुए नुकसान और तोड़-फोड़ शामिल है।

'शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने की गाइडलाइंस पर कर रहे पुनर्विचार'

राजेश दुबे

नई दिल्ली। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के विवादित दिशानिर्देशों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह इन पर पुनर्विचार कर रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इन नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें यूजीसी के नए दिशानिर्देशों को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि इनमें जातिगत भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तक सीमित रखा गया है। सामान्य वर्ग को इससे बाहर रखा गया है।

इससे पहले 29 जनवरी को सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी यूजीसी विनियम, 2026 पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि यह मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है कि जिन्हें यदि बिना जांचे छोड़ दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यह समाज को बांट सकता है। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा था कि आगे के आदेश तक 2012 के पुराने विनियम ही लागू रहेंगे। पीठ ने प्रथम दृष्टया माना था कि 2026 के नियमों के कुछ प्रावधानों में अस्पष्टता है और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अदालत ने क्या-क्या कहा ?

सुनवाई के दौरान पीठ में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने कहा था, हमें उस स्थिति तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां अमेरिका की तरह अलग-अलग स्कूल हों। जैसे कि अश्वेत बच्चे एक स्कूल में जाएं और श्वेत बच्चे दूसरे में। भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में झलकनी चाहिए।

अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि यदि एक ही जाति के भीतर कोई आर्थिक रूप से सक्षम छात्र किसी अन्य छात्र को परेशान करता है तो नए नियम इससे कैसे निपटेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई थी कि ऐसे प्रावधानों का फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं।

नए नियम को लेकर क्या है आपत्ति ?

मृत्युंजय तिवारी, अधिवक्ता विनीत जिंदल और राहुल दीवान द्वारा दायर याचिकाओं में मुख्य रूप से इसकी धारा 3(1)(सी) को चुनौती दी गई है।

आपको बता दें कि ये दिशानिर्देश 2019 में पायल तडवी की माता रेणुका तडवी और रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद तैयार किए गए थे।

अडाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत!

नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनी अडाणी पावर को देश की सर्वोच्च अदालत से एक बहुत बड़ी और अहम कानूनी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अडाणी पावर के करोड़ों रुपये के बकाया इनवॉइस को चुनौती दी थी।

यह पूरा विवाद लगभग ₹1005 करोड़ के बकाया भुगतान और लेट पेमेंट सरचार्ज से जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कर्नाटक सरकार की बिजली कंपनियों को बड़ा झटका लगा है, जबकि अडाणी पावर के लिए यह बड़ी वित्तीय जीत है।

'सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे', सुप्रीम कोर्ट की पार्श्वनाथ ग्रुप के बिल्डरों को सख्त चेतावनी

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने पार्श्वनाथ ग्रुप के अटके प्रोजेक्ट्स पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि यदि उन्होंने 3000 परेशान घर खरीदारों की शिकायत का समाधान नहीं किया, तो उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

अदालत ने ग्रुप के व्यवहार पर एतराज जताते हुए कहा कि उन्हें मालूम है कि कैसे घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और सिस्टम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोर्ट ने पार्श्वनाथ ग्रुप को दो सप्ताह का समय दिया है।

3000 खरीदार अधर में लटके

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। पार्श्वनाथ ग्रुप की ओर से सीनियर वकीलों की एक टीम जिरह कर रही थी। ग्रुप ने कोर्ट में दावा किया कि जो भी खरीदार अपना पैसा वापस पाना चाहते हैं, उन्हें ब्याज सहित निवेश की गई रकम वापस कर दी जाएगी।

इस पर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि पार्श्वनाथ ग्रुप ने हर प्रोजेक्ट के लिए एक नई कंपनी बनाई। उन्होंने कहा कि अभी भी 3000 खरीदार अधर में लटके हुए हैं। पार्श्वनाथ ग्रुप ने सफाई देते हुए कहा कि लगभग 27 हजार फ्लैट बनाए जाने थे, जिसमें 24 हजार बिक चुके हैं और 21 हजार पर कब्जा भी दिया जा चुका है।

अदालत नाराज

अदालत ने कहा, 'ग्रुप अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग नामों का इस्तेमाल कर रहा है। हम जानते हैं कि वे कैसे घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और सिस्टम को बेवकूफ बना रहे हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, 'अगले दो हफ्ते में अगर सभी 3000 घर खरीदारों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो हम सारी संपत्ति फ्रीज कर देंगे और निर्माण पूरा करने और फ्लैट सौंपने की देखरेख के लिए घर खरीदारों की एक कमेटी बना देंगे।'

अकाउंट अनफ्रीज करने से इनकार

कोर्ट ने कहा कि अगर बिल्डर का प्रस्ताव पार्श्वनाथ और उसकी सहयोगी या सिस्टर कंपनियों के सभी घर खरीदारों की मांगों को पूरा नहीं करता है, तो अदालत को एक हाई-पावर्ड कमेटी बनानी पड़ेगी। बेंच ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और यूपी रेरा को बिल्डर पर बकाया रकम का विवरण देते हुए हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने ग्रुप के किसी भी अकाउंट को अनफ्रीज करने से भी इनकार कर दिया है।

चुनाव में धांधली के केस वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

अब राज्य सरकारों को लेनी होगी हाईकोर्ट की मंजूरी

नई दिल्ली । यह आम बात रही है कि चुनाव प्रक्रिया में गलत तरीकों (जैसे काले धन का इस्तेमाल) का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों पर दर्ज मामले सरकार बदलने पर राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिए जाते हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों को वापस लेने के लिए संबंधित हाई कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कि मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े केस सिर्फ हाई कोर्ट की मंजूरी से ही वापस लिए जा सकते हैं, जस्टिस संजय करोल और एन.के. सिंह की बेंच ने कहा कि यह नियम चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होना चाहिए।

अदालत ने क्या कहा ?

पीठ ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यह

सुझाव निष्पक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम है। असल में इससे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी आपराधिक मुकदमों के मामले में चुने हुए सांसदों और विधायकों के बराबर आ जाएंगे। हमारी राय में इससे उम्मीदवारों और संभावित उम्मीदवारों को यह संदेश मिलता है कि गलत कामों में शामिल होना कोई मामूली बात नहीं है। एक बार जब उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाता है तो सिर्फ राजनीतिक सत्ता बदलने से ही वे बच नहीं पाएंगे।

पीठ ने आगे कहा, दूसरे शब्दों में एक संवैधानिक लोकतंत्र अपने प्रतिनिधियों से उसी स्तर की नैतिक ईमानदारी और सच्चाई की उम्मीद करता है।

'न्याय प्रणाली की भावना के खिलाफ'

अदालत ने यह भी कहा, चुनाव आयोग का मानना है कि आम तौर पर केस वापस नहीं लिए जाने चाहिए। हालांकि, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राजनीतिक सत्ता में बदलाव के कारण अक्सर ऐसे फैसले लिए जाते हैं। ऐसा करना निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली की भावना के पूरी तरह खिलाफ है। यह प्रणाली संवैधानिक रूप से चलने वाले गणतंत्र की पहचान है, खासकर भारत जैसे देश की।

अदालत का एक निर्देश यह भी था कि अगर चेकिंग के दौरान स्टैटिक सर्विलांस टीम को 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद मिलता है तो इनकम टैक्स विभाग को कार्रवाई के लिए सक्रिय किया जाए।

आर्मी चीफ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी कैप्टन शिवानी

भारतीय सेना में पहली महिला एडीसी बनकर रचा इतिहास

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने महिलाओं की भागीदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में एक नया इतिहास रच दिया है। कैप्टन शिवानी को भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की पहली महिला एड-डी-कैंप (एडीसी) नियुक्त किया गया है। यह उपलब्धि न केवल कैप्टन शिवानी के लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन सभी युवतियों के लिए भी प्रेरणा है जो सेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। सेना का यह फैसला बताता है कि अब जिम्मेदार और प्रतिष्ठित पदों पर भी महिलाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर अवसर मिल रहे हैं।

क्या होता है एडीसी का पद

एडीसी यानी एड-डी-कैंप सेना प्रमुख का सैन्य सहायक होता है। इस अधिकारी की जिम्मेदारी सेना प्रमुख के ऑफिशियल प्रोग्राम को कॉर्डिनेट करना, प्रोटोकॉल का पालन कराना, प्रशासनिक कार्यों को संभालना और अलग-अलग सैन्य एवं सरकारी आयोजनों में उनके साथ मौजूद रहना होती है।यह पद भारतीय सेना के सबसे सम्मानित और जिम्मेदारी वाले पदों में से एक माना जाता है.

एडीसी की जिम्मेदारी केवल उन्हीं अधिकारियों को दी जाती है, जिनका सर्विस रिकॉर्ड बेहतरीन हो। इसके अलावा उनका डिसिप्लिन, लीडरशिप एबिलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर और काम के प्रति समर्पण भी हाई लेवल का होना चाहिए। यही कारण है कि इस पद पर नियुक्ति को किसी भी युवा सैन्य अधिकारी के करियर की बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है।

कैप्टन शिवानी की उपलब्धि क्यों है खास?

कैप्टन शिवानी का इस पद पर नियुक्त होना भारतीय सेना में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का बड़ा उदाहरण है। लंबे समय तक सेना के कई अहम पदों पर केवल पुरुष अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब समय बदल रहा है. महिलाओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और वे अपनी क्षमता से हर क्षेत्र में खुद को साबित कर रही हैं

नई पीढ़ी के लिए बनेंगी प्रेरणा

कैप्टन शिवानी की यह सफलता उन लाखों छात्राओं और युवतियों के लिए प्रेरणा है जो भारतीय सेना में करियर बनाने का सपना देखती हैं। उनका यह सफर यह संदेश देता है कि मेहनत, अनुशासन और योग्यता के दम पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। भारतीय सेना का यह कदम भी दिखाता है कि वह मॉडर्न सोच के साथ आगे बढ़ रही है और योग्य अधिकारियों को बिना किसी भेदभाव के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगरा की बेटी ने कश्मीर में संभाली टास्क फोर्स की कमान

बाह (आगरा)। बाह तहसील के ग्राम पुरा बाघराज (कैंजरा) की बेटी कर्नल शिखा भदौरिया ने भारतीय सेना में अपनी मेहनत, प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता से क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। कर्नल शिखा ने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रोजेक्ट बीकान के अंतर्गत 32 बार्डर रोड्स टास्क फोर्स (32 बीआरटीएफ) की कमान संभाली है।

वह उत्तर कश्मीर में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क संपर्क को बनाए रखने और सेना के अभियानों को आवश्यक सहयोग देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सड़क मार्गों को सुचारू रखना बीआरओ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

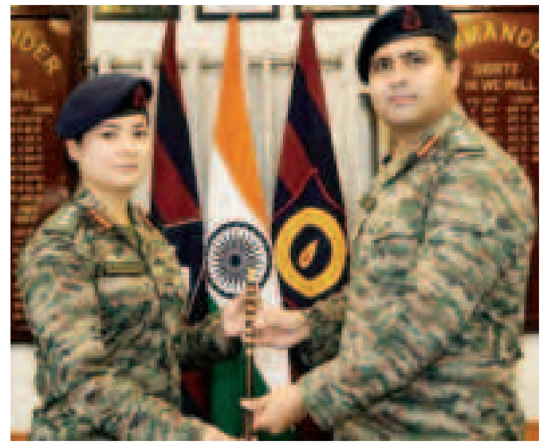

कर्नल शिखा के नेतृत्व में 32 बीआरटीएफ सामरिक महत्व वाले मार्गों के रखरखाव और संचालन से जुड़े कार्य कर रही है। इसके साथ ही पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षित एवं सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने में भी उनकी अहम भूमिका है।

स्वर्ण पदक से कर्नल की कमान तक

कर्नल शिखा भदौरिया का सफर उपलब्धियों से भरा रहा है। वह अकादमी की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2018 में उन्हें 'वूमन ऑफिसर ऑफ द ईयर' सम्मान मिला था। उन्होंने आईआईटी रुड़की से एमटेक की डिग्री हासिल की है। सैन्य सेवा में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए वह कर्नल के प्रतिष्ठित पद तक पहुंची हैं।

सेना सेवा परिवार की परंपरा

कर्नल शिखा विजय प्रताप सिंह भदौरिया की सुपुत्री हैं। उनके परिवार में सेना सेवा की गौरवशाली परंपरा रही है। उनके चाचा कर्नल गजेंद्र सिंह भदौरिया और पति कर्नल ऋषभ सिंह भदौरिया भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। परिवार की इसी सैन्य पृष्ठभूमि और संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए कर्नल शिखा ने देशसेवा में अपनी अलग पहचान बनाई है।

वायुसेना की पहली महिला 'टॉप गन' बनीं भावना कंठ

बिहार की बेटी ने इतिहास के पन्नों में जोड़ा एक नया अध्याय

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना की जांबाज अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने इतिहास के पन्नों में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। वह 'फाइटर कॉम्बैट लीडर' (एफसीएल) कोर्स को पूरा करने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भावना भारतीय वायुसेना की पहली महिला 'टॉप गन' कॉम्बैट टैक्टिशियन भी बन गई हैं।

बता दें कि ग्वालियर स्थित 'टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट' (टीएसीडीई) में आयोजित होने वाला यह 20 सप्ताह का कोर्स भारतीय वायुसेना की सबसे एडवांस और सख्त ट्रेनिंग में से एक है। टीएसीडीई को भारतीय वायुसेना का 'टॉप गन स्कूल' कहा जाता है। इसकी तुलना अमेरिका की नौसेना के ₹टॉप गनर₹ प्रोग्राम से भी की जाती है और इसमें केवल बेहद चुनिंदा फाइटर पायलटों को ही प्रवेश मिलता है। एफसीएल कोर्स पूरा करने वाले पायलट आसमान में जटिल मिशनों का नेतृत्व करने में सक्षम हो जाते हैं।

बिहार के दरभंगा जिले की रहने वाली भावना कंठ ने मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई की पढ़ाई की है। उनका वायुसेना में अब तक का सफर उपलब्धियों से भरा रहा है। इससे पहले भावना जून 2016 में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ देश के पहले महिला फाइटर पायलट बैच में कमीशन हुई थीं।

इसके बाद 2019 में वह डेटाइम फाइटर जेट उड़ाने की योग्यता हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनीं। उन्होंने शुरुआत में एमआईजी-21 बिशन उड़ाया और बाद में एसयू-30 एमकेआई भी उड़ाया।

संजुक्ता पराशर बनीं सीआरपीएफ की नई आईजी

'आयरन लेडी ऑफ असम' के नाम से हैं मशहूर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। साहस, देशभक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति की जब भी बात आती है, तो भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की जांबाज महिला अधिकारियों का नाम सबसे पहले आता है। इन्हीं में से एक बेहद चर्चित नाम है डॉ. संजुक्ता पराशर का। असम की 'आयरन लेडी' के नाम से मशहूर 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में महानिरीक्षक (आईजी) के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। संजुक्ता पराशर की यह नियुक्ति देश भर के उन लाखों युवाओं और छात्रों के लिए एक बड़ा संदेश है, जो चुनौतियों से डरने के बजाय उनका डटकर सामना करने का जज्बा रखते हैं।

3 अक्टूबर 1979 को असम में जन्मीं संजुक्ता पराशर का बचपन से ही पढ़ाई में गहरा लगाव था। उनके पिता सिंचाई विभाग में इंजीनियर और माता स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थीं। गुवाहाटी में अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आ गईं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित इंद्रप्रस्थ कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशन में एमए, एमफिल और पीएचडी की उच्च डिग्री प्राप्त की।

यूपीएससी में 85वीं रैंक

कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास के दम पर संजुक्ता पराशर ने वर्ष 2006 में सिविल सेवा परीक्षा में पूरे देश में 85वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की। इतनी शानदार रैंक होने के बावजूद उन्होंने प्रशासनिक सेवा (आईएए) के बजाय भारतीय पुलिस सेवा को चुना, क्योंकि वह जमीनी स्तर पर देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए काम करना चाहती थीं। उन्हें असम-मेघालय काडर आवंटित किया गया और वह असम की पहली महिला आईपीएस अधिकारियों में शामिल हुईं।

जंगलों में उग्रवादियों का खात्मा

असम में अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने उग्रवाद प्रभावित इलाकों में कानून-

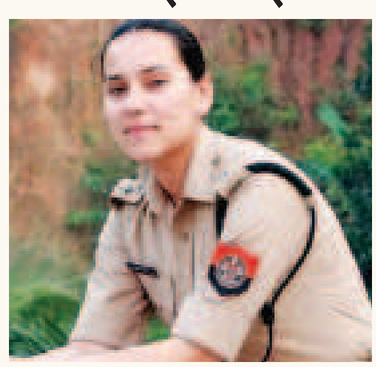

व्यवस्था कायम करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। जब बोडो और अन्य सशस्त्र उग्रवादी गुट असम के घने जंगलों में हिंसा फैला रहे थे, तब संजुक्ता पराशर ने कमांड सेंटर में बैठने के बजाय खुद मैदान में उतरने का फैसला किया। हाथों में एके-47 राइफल थामे घने जंगलों में कमांडो टीमों और सुरक्षा बलों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने महज 15 महीनों में 16 से अधिक खतरनाक उग्रवादियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया और 64 से ज्यादा को गिरफ्तार किया। उनके इसी अदम्य साहस और निडर नेतृत्व के कारण उन्हें 'आयरन लेडी ऑफ असम' का खिताब मिला।

एनआईए से लेकर सीआरपीएफ तक का शानदार सफर

जुक्ता पराशर ने केवल मैदानी अभियानों में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में उप महानिरीक्षक (डीआईजी) के रूप में भी कई राष्ट्रीय सुरक्षा जांचों को अंजाम दिया। देश के प्रति उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें गृह मंत्री पदक' से भी सम्मानित किया जा चुका है।

तेजस के लिए अमेरिका ने इंजन देने में देरी की तो डीआरडीओ ने पलट दी बाजी

आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, कावेरी-2 इंजन लेगा जीई एफ404 की जगह

आस्था भट्टाचार्य

नई दिल्ली। भारत को अब अमेरिका जीई एफ404 इंजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय से चर्चा में रहे कावेरी जेट इंजन को अब पूरी तरह नया रूप देकर कावेरी 2.0 विकसित किया जा रहा है। डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट (जीटीआरई) द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है।

इसका मुख्य मकसद तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिकी जीई एफ404 इंजनों की जगह लेना है। सप्लाई चेन में देरी की वजह से तेजस एमके 1ए के उत्पादन में बाधा आ रही है, इसलिए यह स्वदेशी प्रयास और भी जरूरी हो गया है। कावेरी इंजन की मूल परियोजना 1980 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन थ्रस्ट और वजन संबंधी समस्याओं के कारण इसे तेजस से अलग कर दिया गया था।

अब जीटीआरई ने इसे पूरी तरह से नया कोर डिजाइन करके फिर से बनाया है। नया कावेरी 2.0 बिना आफ्टरबर्नर के 55 से 60 किलोन्यूटन ड्राई थ्रस्ट और आफ्टरबर्नर के साथ 90 से 100 किलोन्यूटन वेट थ्रस्ट देने का लक्ष्य रखता है। यानी इससे फाइटर जेट को तेज उड़ान की ताकत मिलेगी। यह क्षमता मौजूदा जीई एफ 404 इंजनों के बराबर या उससे बेहतर है, जो वर्तमान में तेजस एमके 1ए को ताकत दे रहे हैं।

पुराने कावेरी डेरिवेटिव इंजन (केडीई) में केवल 49 से 52 किलोन्यूटन थ्रस्ट मिलता था, जो आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरतों के लिए कम था। नया कोर हाई-प्रेशर कंप्रेशर पर जोर देता है ताकि दबाव अनुपात और ईंधन दक्षता बढ़ाई जा सके। इंजीनियर एडवांस्ड ब्लिस्क (ब्लेडेड डिस्क) का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टाइटेनियम मिश्रित धातु से बने हैं।

ये सिंगल-पीस डिजाइन हवा के रिसाव को रोकते हैं, वजन कम करते हैं। थ्रस्ट-टू-वेट अनुपात सुधारते हैं। सिंगल-क्रिस्टल ब्लेड्स का उपयोग उच्च तापमान सहन करने के लिए किया जा रहा है, जिससे थर्मल दक्षता बढ़ेगी। वजन में भी उल्लेखनीय कमी लाई जा रही है।

मूल कावेरी का वजन लगभग 1235 किलोग्राम था, जिसे अब 1100 किलोग्राम से कम करने का लक्ष्य है। भविष्य में इसे और घटाकर 1000 किलोग्राम के करीब लाने की योजना है। इसके लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और कंपोजिट सामग्रियों का सहारा लिया जा रहा है।

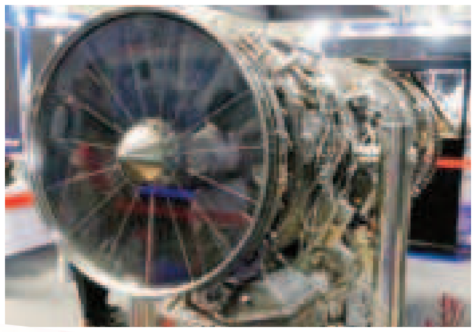

इसके अलावा, फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल (एफएडीईसी) सिस्टम लगाया जाएगा, जो इंजन को डिजिटल तरीके से नियंत्रित करेगा। विभिन्न उड़ान स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करेगा।

तेजस उत्पादन में देरी और स्वदेशी विकल्प की जरूरत

तेजस एमके 1 ए कार्यक्रम अमेरिकी जीई एफ404 इंजनों की आपूर्ति में देरी से प्रभावित हो रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड - एचएएल ने कई एयरफ्रेम तैयार कर लिए हैं, लेकिन इंजन न मिलने से डिलीवरी रुकी हुई है। वैश्विक सप्लाई चेन की समस्याएं और उत्पादन बाधाओं के कारण यह स्थिति बनी है।

- कावेरी की क्षमता मौजूदा जीई एफ 404 इंजनों से बेहतर
- इसका वजन 1235 किग्रा से घटाकर 1100 किलो किया जा रहा
- कावेरी का ड्राई वर्जन संस्करण घातक यूसीएवी के लिए भी उपयोगी
- अधिक ऊंचाई और लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया

ऐसे में कावेरी 2.0 को मिड-लाइफ अपग्रेड के रूप में 2030 के दशक में तेजस बेड़े में फिट करने की योजना है। जब मौजूदा इंजन अपने ओवरहाल साइकिल में पहुंचेंगे, तब स्वदेशी इंजन लगाने से विदेशी निर्भरता कम होगी और आपूर्ति संबंधी जोखिम समाप्त होंगे।

यह प्रयास सैफरान के साथ चल रहे संयुक्त कार्यक्रम से अलग है। सैफरान के साथ 120 किलोन्यूटन या उससे अधिक थ्रस्ट वाला इंजन एएमसीए जैसे पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर के लिए विकसित किया जा रहा है। कावेरी 2.0 मध्यम थ्रस्ट वाला वर्कहॉर्स है, जो तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त है।

इससे भारत दोहरी रणनीति अपना रहा है- एक तरफ मौजूदा जरूरतों को पूरा करना और दूसरी तरफ भविष्य के एडवांस विमानों के लिए तकनीक विकसित करना।

'घातक' यूसीएवी और अन्य चुनौतियां

कावेरी का ड्राई वर्जन यानी बिना आफ्टरबर्नर वाला संस्करण घातक यूसीएवी के लिए भी उपयोगी है। यह मानवरहित लड़ाकू ड्रोन उच्च ऊंचाई और लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया ह। ड्राई इंजन ईंधन की बचत करता है। स्टेल्थ विशेषताओं को बनाए रखने में मदद करता है।

इससे 'घातक' कार्यक्रम को गति मिलेगी और भारत मानवरहित युद्धक क्षमताओं में आत्मनिर्भर बनेगा। भविष्य में कावेरी 2.0 को तेजस एमके 2 या अन्य प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। चरणबद्ध परीक्षण की योजना है।

इसमें ग्राउंड टेस्ट, हाई-अल्टीट्यूड ट्रायल्स और बाद में फ्लाइंग टेस्ट बेड पर उड़ान परीक्षण शामिल हैं। एक संशोधित तेजस विमान को टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि मूल तेजस डिजाइन कावेरी के आयामों को ध्यान में रखकर बना था।

प्रगति उत्साहजनक है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अतीत में देरी और तकनीकी बाधाओं के कारण आलोचना हुई थी। कई विशेषज्ञ और रक्षा विश्लेषक स्थिर और पर्याप्त फंडिंग की मांग कर रहे हैं ताकि परियोजना समय पर पूरी हो। जेट इंजन विकास जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हॉट सेक्शन सामग्री, कंप्रेशर दक्षता और नियंत्रण प्रणालियों पर महारत हासिल करनी पड़ती है।

फ्रांस ने 114 राफेल की डील के लिए भेजा प्रपोजल, भारत में ही बनेंगे 94 विमान

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन ताकत को मजबूती देने के लिए फ्रांस ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। फ्रांस ने 114 राफेल मल्टीरोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए अपना विस्तृत टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल सौंप दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये की ये डील इस समय रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग और भारतीय वायुसेना के विचाराधीन है। फ्रांसीसी प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत भारत में बड़े पैमाने पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है।

बता दें कि भारत सरकार ने इसी साल मई महीने में गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट खरीद मार्ग के तहत फ्रांस को एक अनुरोध पत्र भेजा था। उसी के जवाब में फ्रांस ने ये प्रपोजल पेश किया है।

भारत में निर्माण

प्रपोजल के मुताबिक, 114 राफेल विमानों में से 94 लड़ाकू विमान भारत में ही एक भारतीय औद्योगिक भागीदार के साथ मिलकर बनाए जाएंगे। इस मेगा डील में फ्रांस की रक्षा कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ-साथ एमबीडीए, सैफरान और थेल्स जैसी दिग्गज फ्रांसीसी रक्षा कंपनियां शामिल होंगी। भारत सरकार इस सौदे में स्वदेशी सामग्री बढ़ाने और भारतीय हथियारों को एकीकृत करने पर खास ध्यान दे रही है।

भारत की योजना राफेल विमानों में स्वदेशी रूप से विकसित 'अस्त्र' एयर-टू-एयर मिसाइल सहित दूसरे स्वदेशी हथियारों को लगाने की है। रक्षा विशेषज्ञ और वायुसेना के अधिकारी प्रस्ताव में इस प्रावधान का बेहद बारीकी से आकलन कर रहे है।

भारतीय वायुसेना को मिलेगा बड़ा बूस्ट

भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने बेड़े में एडवांस फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही है। अगर ये 3.25 लाख करोड़ रुपये की डील फाइनल होती है, तो न सिर्फ वायुसेना की युद्ध क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि भारत का रक्षा निर्माण क्षेत्र भी आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ी छलांग लगाएगा।

भारत ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई बढ़ाई

ढाई हजार खेपें 2023 से 2025 की अवधि में भेजीं

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। इजराइल और भारत के बीच रक्षा संबंधों पर चर्चा अक्सर इजराइली निर्यात पर केंद्रित होती है। हालांकि, एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट एक नया पहलू सामने ला रही है, जिससे पता चलता है कि 7 अक्टूबर, 2023 और 30 नवंबर, 2025 के बीच भारत से इजराइल को हथियारों, गोला-बारूद, पुर्जों और कलपुर्जों की कम से कम 2,596 खेपें भेजी गई।

इन आपूर्तियों की जड़ें इजराइली रक्षा कंपनियों की गतिविधियों में हैं - जिनमें एल्बिट सिस्टम्स, इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) और राफेल शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' नीति को अपनाया है। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। हाल के वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता की शर्तों को और कड़ा किया है तथा कम से कम 50% स्थानीय उत्पादन की सीमा तय की है।

इस स्थिति का इजराइल के रक्षा उद्योगों के सबसे बड़े ग्राहक के रूप में भारत की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-2025 में इजराइल के रक्षा निर्यात का लगभग 29% हिस्सा भारत को गया; जर्मनी को 3.5 बिलियन डॉलर में 'एरो 3' सिस्टम बेचने के बड़े सौदे के बावजूद भारत इजराइल के रक्षा निर्यात का सबसे बड़ा गंतव्य बना रहा। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, 2021-2025 के बीच इजराइल के रक्षा निर्यात का 21% हिस्सा जर्मनी को गया।

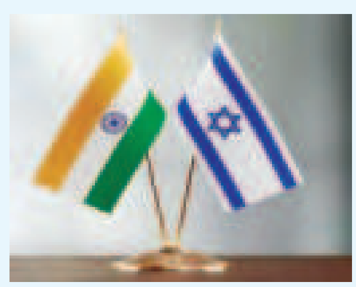

रक्षा मंत्रालय के तहत सिबाट (अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग निदेशालय) के आंकड़ों से पता चलता है कि उन वर्षों में इजराइल का कुल रक्षा निर्यात 71 बिलियन डॉलर था।

10 फरवरी, 2025 को बेंगलुरु के येलाहांका एयर बेस पर 'एरो इंडिया 2025' एयर शो के दौरान इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉल पर 'एयर लोरा' (एक लंबी दूरी का, बहुत सटीक और सुपरसोनिक हथियार) और 'विंड डेमन' (किफ़ायती एयर-टू-सरफ़ेस क्रूज़ मिसाइल) के मॉडल दिखाए गए।

भारत के साथ रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने में इजराइल के मुख्य व्यक्ति रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल (रिटायर्ड) अमीर बारम हैं। पिछले साल जून में, उन्होंने भारत का दौरा किया था, जहां वे रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे। लगभग एक हफ़्ते बाद, हर्ज़लिया सम्मेलन में उन्होंने बताया, युद्ध ने इस क्षेत्र के सभी पक्षों के लिए ईरान के मजबूत होने की चर्चा बढ़ा दी है। इसने भारत से लेकर यूएई होते हुए ग्रीस और साइप्रस तक एक व्यापक गठबंधन बनाने के लिए हितों की समानता पैदा की है।

कुछ मामलों में एमनेस्टी भारत से भेजे गए सामान के इजराइली ग्राहकों का पता लगाने में सफल रही है, जिनमें सबसे प्रमुख एल्बिट है। इसे स्काईस्ट्राइकर के लिए 155एमएम के गोले और वॉरहेड मिले थे।

13,041 करोड़ के चार रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी

मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी और व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में 13,041 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि इनमें चार रेलवे और एक हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

रेलवे के चार प्रोजेक्ट्स में हावड़ा-चेन्नई मुख्य रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग किया जाएगा। इसके अलावा कटक-पारादीप रूट पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन, यानी क्वाड्रुपलिंग का काम किया जाएगा।

पांचवें प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक चार लेन का हाईवे बनाया जाएगा। यह सड़क नेपाल सीमा तक जाएगी।

कैबिनेट ने खड़गपुर-भद्रक (रानीताल) चौथी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3,352 करोड़ रुपये है। इसके अलावा भद्रक-हरिदासपुर चौथी रेल लाइन के लिए 1,583 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

रेलवे नेटवर्क के विस्तार के तहत गुम्मिडिपुंडी-गुडूर तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना पर करीब 2,229 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, कटक-पारादीप तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को 2,286 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा।

कैबिनेट ने बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर-सितामढ़ी-सोनबरसा फोर-लेन हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत 3,591 करोड़ रुपये होगी। यह मार्ग मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के साथ नेपाल सीमा के पास स्थित सोनबरसा तक सड़क संपर्क को बेहतर करेगा। है

पश्चिम बंगाल और ओडिशा में खड़गपुर-भद्रक (रानीताल) चौथी रेल लाइन की लंबाई 173 किलोमीटर होगी, वहीं भद्रक-हरिदासपुर के बीच 75 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन बनाई जाएगी।

सरकार के मुताबिक, इन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे की क्षमता बढ़ेगी और व्यस्त रेल मार्गों पर भीड़ कम करने में मदद मिलेगी। इससे ट्रेनों का संचालन बेहतर होने के साथ यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे

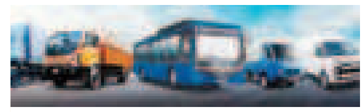

कमर्शियल वाहनों की नेशनल परमिट अवधि 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ईवी, सीएनजी और हाइड्रोजन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों की नेशनल परमिट अवधि 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन का ड्राफ्ट जारी किया है।

प्रस्ताव लागू होने पर बैटरी, हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस वाले वाहनों की उम्र सीमा 12-15 साल से बढ़कर 17-20 साल हो जाएगी।

नेशनल परमिट की प्रक्रिया भी आसान होगी। ऑपरेटर हर साल परमिट लेने के बजाय एक साथ 5 साल का विकल्प चुन सकेंगे। फीस 16,500 रुपए सालाना यानी 5 साल के लिए 82,500 रुपए होगी। आवेदन, परमिट और भुगतान ऑनलाइन किए जा सकेंगे। जरूरी जानकारी 'वाहन' पोर्टल से अपने आप ली जा सकेगी। मंत्रालय ने ड्राफ्ट पर 30 दिनों में सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

रुपए को गिरने से बचाने की जरूरत नहीं

पीएम के सलाहकार बोले- मार्केट को तय करने दें करेंसी का स्तर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत को रुपए में गिरावट रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे मार्केट के हिसाब से अपना स्तर तय करने देना चाहिए। वहीं हमारा मुख्य फोकस महंगाई दर को कंट्रोल में रखने पर होना चाहिए।

सान्याल ने कहा कि जब देश ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को अपनाया था, तब उसने करेंसी एक्सचेंज रेट के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी को चुना था।

महंगाई कंट्रोल करना प्राथमिक लक्ष्य

संजीव सान्याल ने बताया कि ओपन कैपिटल अकाउंट वाली अर्थव्यवस्थाओं में पॉलिसी मेकर्स के सामने कई चुनौतियां होती हैं। भारत का फ्रेमवर्क इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी देश एक साथ स्वतंत्र मॉनेटरी पॉलिसी चलाने और अपनी करेंसी की विनिमय दर को सख्ती से कंट्रोल करने का काम नहीं कर सकता। भारत जैसे बड़े और आंतरिक रूप से मजबूत देश के लिए रुपए की दर तय करने के बजाय महंगाई दर को लक्षित करना ही सही कदम है।

इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की सफलता

सान्याल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को रुपए के स्तर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिस्टम ने देश में बहुत अच्छा काम किया है।

एक समय था जब भारत में महंगाई दर 8% से 12% के दायरे में रहती थी, जबकि पिछले एक दशक में यह सफलतापूर्वक घटकर 2% से 6% के दायरे में आ गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार का सही इस्तेमाल

संजीव सान्याल ने यह भी कहा कि रुपए को

बाजार के भरोसे छोड़ने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केंद्रीय बैंक या संबंधित अधिकारी पूरी तरह चुप बैठेंगे।

उन्होंने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व का इस्तेमाल करेंसी में होने वाले अचानक या तेज उतार-चढ़ाव की रफ्तार को धीमा करने और झटकों को संभालने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग रुपए को उसके स्वाभाविक स्तर पर पहुंचने से रोकने के लिए नहीं होना चाहिए।

कमजोर रुपए से एक्सपोर्टर्स को फायदा

सान्याल ने बताया कि रुपए का कमजोर होना अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। यदि देश में महंगाई दर कंट्रोल रहती है, तो रुपए में गिरावट से भारतीय एक्सपोर्टर्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। दुनिया के कई देशों की करेंसी में काफी उतार-चढ़ाव आता रहता है, इसलिए अगर घरेलू स्तर पर कीमतें स्थिर हैं, तो कमजोर रुपया अर्थव्यवस्था के लिए रुकावट नहीं बनता।

अलग है भारत का दृष्टिकोण

मुख्य चिंता यह होनी चाहिए कि क्या करेंसी में आ रही गिरावट से महंगाई बढ़ रही है। यदि महंगाई कंट्रोल में है और जरूरत पड़ने पर ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं, तो रुपए को जबरन बचाना सही तरीका नहीं है।

भारत में एलपीजी की किल्लत खत्म करने की तैयारी

सरकार ने 21 कंपनियों के लिए तय किए टारगेट

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध के कारण एलपीजी सप्लाई पर पड़े असर से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने पहली बार देश की सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज व अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन के अधिकतम टारगेट तय कर दिए हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विगत सप्ताह जारी आदेश में 21 कंपनियों के लिए कुल 63,810 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन की क्षमता और टारगेट निर्धारित किया है।

यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में हुए कुल घरेलू एलपीजी उत्पादन (35,900 टन प्रतिदिन) से दोगुने से भी अधिक है और देश की कुल रोजाना खपत का लगभग 70% कवर करता है। जब भी बाजार में गैस की कमी या सप्लाई बाधित होगी, यह नया नियम तुरंत लागू हो जाएगा।

रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी को सबसे बड़ा 18,000 टन का टारगेट

सरकार के आदेश के अनुसार, सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिया गया है। रिलायंस की गुजरात स्थित जामनगर की डोमेस्टिक-टैरिफ एरिया रिफाइनरी को रोजाना 18,000 टन एलपीजी तैयार करने का लक्ष्य मिला है।

प्राइवेट सेक्टर की ही रूस के रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी की वाडीनार रिफाइनरी को रोजाना 4,480 टन एलपीजी उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है।

देश में 64% एलपीजी इम्पोर्ट पर निर्भरता

वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में कुल 33.2मिलियन टन एलपीजी की खपत हुई थी (लगभग 91,000 टन प्रतिदिन)। इसमें से केवल 13.1 मिलियन टन (35,900 टन प्रतिदिन) का उत्पादन ही देश में हुआ था, जबकि 21.3 मिलियन टन (58,400 टन प्रतिदिन) एलपीजी विदेश से मंगवानी पड़ी थी।

इम्पोर्ट पर 64% से ज्यादा निर्भरता के कारण जब ईरान युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बाधित हुआ, तो भारत में सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई थी। भारत अपनी जरूरत का 90% इम्पोर्ट इसी समुद्री रास्ते से सऊदी अरब जैसे देशों से करता है।

मार्च में संकट के दौरान उठानी पड़ी थीं इमरजेंसी पाबंदियां

मिडिल ईस्ट संकट के दौरान मार्च में सरकार को पेट्रोकेमिकल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली गैस को एलपीजी बनाने में डायवर्ट करना पड़ा था। उस समय डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाकर 55,000 टन प्रतिदिन तक किया गया था। संकट के समय कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स को बिक्री रोकनी पड़ी थी, घरों में एलपीजी रीफिल बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया था और लोगों को पीएनजी पर शिफ्ट होने के लिए प्रेरित किया गया था। जून के मध्य में स्थिति सामान्य होने पर ये पाबंदियां हटाई गई थीं।

कंपनियों को इन्फ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें

मंत्रालय ने अपने आदेश में साफ किया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज व अपस्ट्रीम कंपनियों को एलपीजी स्टोरेज, निकासी और ट्रांसपोर्टेशन (रेल/सड़क टैंकर) के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित और मेंटेन करना होगा।

6 महीने में रिव्यू होगा प्रोडक्शन शेड्यूल

सरकार ने जरूरत पड़ने पर रिफाइनरीज को उत्पादन बढ़ाने और इनपुट स्ट्रीम के अन्य इस्तेमाल पर रोक लगाने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे हैं। नया फ्रेमवर्क हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपडेट किया जाएगा। इसमें नई रिफाइनरीज, नए अपस्ट्रीम गैस फील्ड्स और तकनीक व इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधारों के हिसाब से नए लक्ष्य जोड़े जाएंगे।

आजादी से विकसित देश त

पीएम मोदी ने 'शक्ति की सप्तधारा' से वि

ब्लिट्ज विशेष

युवाओं को फ्री कोचिंग की घोषणा, 'दिमागी नक्सलों' से सावधान

क्या है 'सप्तध

1-विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग): देश में सेमीकंडक्टर औ
2-कृषि और खाद्य प्रसंस्करण: आधुनिक कृषि पद्धतियों
3-तकनीक और इनोवेशन: एआई, रोबोटिक्स और डेटा
4-गतिशक्ति: आधुनिक बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिव
5-रक्षा शक्ति: रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता।
6-ग्रीन और ब्लू इकॉनमी: हरित ऊर्जा और गहरे समुद्र (
7-सॉफ्ट पावर: वैश्विक मंच पर सांस्कृतिक और कूटनी

नई दिल्ली। स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करते हुए आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 12 वर्षों में स्वतंत्रता दिवस का उत्सव देश की विकास यात्रा का उत्सव भी बन गया है। लक्ष्य स्पष्ट है- 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत विश्व के अग्रणी विकसित देशों के साथ खड़ा हो।

प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वें और 75 मिनट के अपने संबोधन में स्वतंत्रता से 'विकसित भारत 2047' तक नए भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 'शक्ति की सप्तधारा' का विजन पेश किया जिसमें युवाओं के लिए एआई कौशल और वैचारिक खतरों से आगाह करने जैसे महत्वपूर्ण संदेश शामिल रहे।

प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन मुख्य रूप से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर केंद्रित था। इसके अलावा, पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गान से पहले पूर्ण 'वंदे मातरम्' का गूंजना इस भाषण का एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहलू रहा।

भारत के संदर्भ में निहितार्थ

1. युवा शक्ति और जेन-जी पर फोकस

भाषण का सबसे बड़ा सामाजिक निहितार्थ युवाओं से जुड़ा था। बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी बदलावों के बीच, पीएम मोदी ने अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कौशल का प्रशिक्षण देने और गरीब तथा मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की।

यह कदम आधुनिक श्रम बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को तैयार करने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत प्रयास है।

2. आर्थिक राष्ट्रवाद और बड़े वैश्विक लक्ष्य

भारत के 'फ्रेजाइल फाइव' से निकलकर दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होने का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब देश को छोटे सपनों से आगे देखना होगा।

उनका यह आह्वान कि आने वाले दशक में कम से कम 50 भारतीय कंपनियां 'फॉर्च्यून 500' की सूची में शामिल हों, भारतीय कॉरपोरेट जगत को वैश्विक स्तर पर सिरमौर बनने की चुनौती और प्रेरणा देता है।

3. आंतरिक सुरक्षा और 'दिमागी नक्सलवादी' चेतावनी

सशस्त्र वामपंथी उग्रवाद के खात्मे की बात कहते हुए प्रधानमंत्री ने समाज में वैचारिक स्तर पर सक्रिय रहने वाले तत्वों यानी 'दिमागी नक्सलों' से सतर्क रहने की चेतावनी दी। आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में इसका निहितार्थ यह है कि सरकार अब वैचारिक और बौद्धिक स्तर पर राष्ट्र-विरोधी या भ्रामक प्रवृत्तियों को भी देश की प्रगति में एक गंभीर चुनौती मानती है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार लाल किले से गूंजा 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण

इस बार आजादी का दिन काफी खास रहा क्योंकि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार 'वंदे मातरम' का पूरा संस्करण बजाया गया जो देश के आधिकारिक राष्ट्रीय समारोहों में एक ऐतिहासिक क्षण था। कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रीय गीत गाया गया और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। वंदे मातरम का गायन आज ऐसे समय में हुआ है जब भारत 'वंदे मातरम' की 150 साल पुरानी विरासत का जश्न मना रहा है।

4. वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और वर्ष 2047 का लक्ष्य

वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के तहत परमाणु ऊर्जा (100 गीगावाट का लक्ष्य) और अंतरिक्ष व सेमीकंडक्टर क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तय किए गए हैं। साथ ही, भारत द्वारा 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदारी पेश करने की बात खेल संस्कृति को राष्ट्रीय अस्मिता और युवा ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास दर्शाती है।

कुल मिला कर पीएम मोदी का यह भाषण महज आंकड़ों और उपलब्धियों का लेखा-जोखा नहीं था, बल्कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब बनाने का घोषणापत्र था। इसका निहितार्थ स्पष्ट है कि भारत अब वैश्विक झटकों को झेलने के साथ-साथ डिजिटल और हरित क्रांति के बल पर दुनिया का नेतृत्व करने की आकांक्षा रखता है।

80 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम

नक, नए भारत का संकल्प

दिया विकसित भारत का आर्थिक ब्लूप्रिंट

रहने का संदेश

ारा' विजन

- र इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को बढ़ावा देना।
- ' और मूल्यवर्धन पर जोर।
- केंद्रों का विस्तार।
- स का सुदृढ़ीकरण।
- डीप-सी) के संसाधनों का सतत उपयोग।
- तिक प्रभाव को बढ़ाना।

मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण की शुरुआत 'वंदे मातरम् 'और तिरंगे के जिक्र से की। उन्होंने कहा कि आज हर दिल में वंदे मातरम गूंज रहा है, हर घर में तिरंगा है और हर मन में तिरंगा बस गया है। देश नए संकल्पों और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है।

पीएम ने महात्मा गांधी सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को नमन किया, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। पीएम के भाषण का सबसे बड़ा संदेश बड़े सपने देखने का था। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि अब छोटे सपनों से काम नहीं चलेगा। बड़े सपने सोच का विस्तार करते हैं, क्षितिज को चौड़ा करते हैं और प्रगति की गति बढ़ाते हैं। जब संकल्प दृढ़ होता है तो संभावनाएं खुद रास्ता बना लेती हैं।

स्वतंत्रता आंदोलन का प्रखर जयघोष था 'वंदे मातरम्'

ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर रोम-रोम पुलकित हो उठा

नई दिल्ली। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम् ' के पूरे संस्करण के गायन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 'वंदे मातरम्' स्वतंत्रता आंदोलन का प्रखर जयघोष रहा है और इसका पूरा संस्करण सुनना बेहद भावुक करने वाला पल है। इस वर्ष राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम् ' के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान 21 तोपों की सलामी, सेना के बैंड की प्रस्तुति और भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्पवर्षा ने समारोह को और भव्य बना दिया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनकर न सिर्फ रोंगटे खड़े हो गए, बल्कि रोम-रोम पुलकित हो उठा।

इस वर्ष 'वंदे मातरम् ' की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के कारण स्वतंत्रता दिवस समारोह में इसे विशेष महत्व दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए भी इस ऐतिहासिक क्षण का उल्लेख किया और कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है, जब लाल किले पर पूरा 'वंदे मातरम् ' बजाया गया।

तिरंगा फहराते ही 21 तोपों की सलामी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) ने स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी। इसके बाद सेना के बैंड ने 'वंदे मातरम् ' की धुन प्रस्तुत की। इसी दौरान भारतीय वायुसेना के दो एमआई-17 हेलीकॉप्टरों ने लाल किले के ऊपर से पुष्पवर्षा की। एक हेलीकॉप्टर पर तिरंगा और दूसरे पर 'वंदे मातरम् ' लिखा हुआ ध्वज लहरा रहा था। आसमान से होती पुष्पवर्षा और लाल किले पर गूंजते राष्ट्रगीत ने समारोह को यादगार बना दिया।

हाल ही में 'वंदे मातरम् ' के पूरे संस्करण को राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा दिए जाने की बात सामने आई है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन की शुरुआत और समापन के दौरान भी 'वंदे मातरम् ' बजाया गया था।

तिरंगे की रोशनी से चमका बुर्ज खलीफा

दुबई। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा शुक्रवार (15 अगस्त) की रात तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी दिखाई दी। इस खास नजारे ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा और भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न दुबई में भी देखने को मिला।

दुबई स्थित भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने इस खास मौके की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। पोस्ट में इसे भारत की यात्रा, गर्व और भावना को समर्पित खास श्रद्धांजलि बताया गया। साथ ही इसे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक भी बताया गया। बुर्ज खलीफा पर इस तरह की रोशनी दुनिया के अलग-अलग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मौकों पर दिखाई जाती है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर भी यहां पहले कई बार तिरंगे के रंगों में रोशनी की जा चुकी है।

828 मीटर ऊंचा है बुर्ज खलीफा

बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में जानी जाती है। दुबई की पहचान बन चुकी यह इमारत बड़े राष्ट्रीय समारोहों और अंतरराष्ट्रीय मौकों पर खास रोशनी के लिए भी प्रसिद्ध है।

दुनिया के नेताओं ने दी भारत को बधाई

भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया के कई देशों के नेताओं और सरकारों की ओर से भी शुभकामनाएं दी गईं । फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी। भारत का स्वतंत्रता दिवस देश के साथ-साथ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भी मनाया गया।

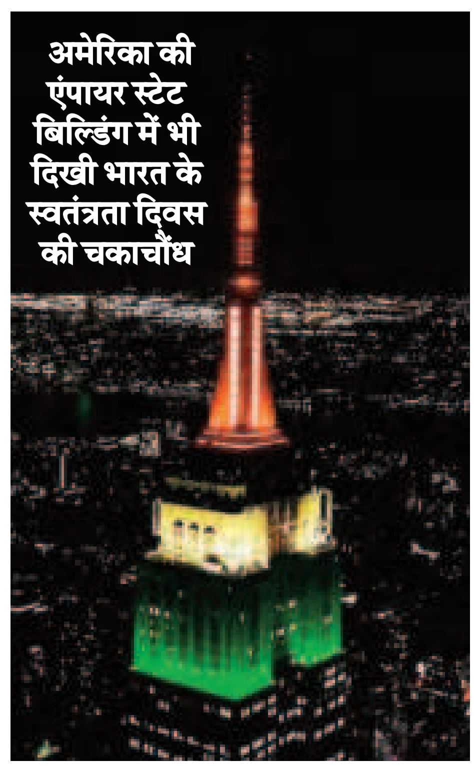

अमेरिका की एंपायर स्टेट बिल्डिंग में भी दिखी भारत के स्वतंत्रता दिवस की चकाचौंध

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की बंपर भर्ती 1654 पदों के लिए आवेदन शुरू

सबसे ज्यादा 504 पद अंग्रेजी विषय के, आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर

ब्लिट्ज ब्यूरो

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले लोक शिक्षण संचालनालय ने ई और टी संवर्ग के तहत शिक्षकों के 1654 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती की परीक्षा का जिम्मा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल यानी सीजीएसएसबी को सौंपा गया है, जिसे पहले सब लोग व्यापम के नाम से जानते थे। परीक्षा का कोड एलएसटी 26 रखा गया है और इसकी तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 7 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

किन विषयों में हैं कितनी सीटें

इस भर्ती में छह अलग-अलग विषयों के शिक्षकों की जरूरत बताई गई है। सबसे ज्यादा 504 पद अंग्रेजी विषय के लिए रखे गए हैं, जबकि संस्कृत में 300, हिंदी में 250, गणित में 250 और सामाजिक विज्ञान में भी 250 पद हैं। कृषि विषय के लिए सबसे कम यानी 100 पद निकाले गए हैं। हालांकि, विज्ञापन में यह भी साफ लिखा गया है कि खाली पदों की यह संख्या घट-बढ़ सकती है, इसलिए अंतिम स्थिति के लिए आधिकारिक सूचना ही देखनी चाहिए। एक जरूरी बात यह भी है कि इन पदों पर चयन सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा।

आवेदन की आखिरी तारीख

जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास 2 सितंबर की शाम 5 बजे तक का समय है। फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 से 5 सितंबर तक सुधार का मौका भी दिया जाएगा।

फीस की बात करें तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 350 रुपये, ओबीसी वर्ग को 250 रुपये और अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांग उम्मीदवारों को सिर्फ 200 रुपये चुकाने होंगे। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो परीक्षा में शामिल होंगे, उनकी फीस बाद में उसी बैंक खाते में लौटा दी जाएगी जिससे भुगतान किया गया था।

कौन कर सकता है आवेदन

पात्रता के मामले में विभाग ने कई रास्ते खुले रखे हैं। कोई ग्रेजुएट होकर दो साल का डी.एल.एड कर चुका है तो वह आवेदन कर सकता है, या फिर 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएशन के बाद बी.एड करने वाले भी योग्य माने जाएंगे। एनसीटीई के नियमों के मुताबिक 45 फीसदी अंकों वाले ग्रेजुएट भी शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 12वीं में 50 फीसदी अंक लाकर चार साल का बी.एल.एड या बी.ए.बी.एड जैसा कोर्स करने वालों को भी मौका मिलेगा। इन सबके साथ टीईटी परीक्षा पास होना अनिवार्य शर्त है। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 35 साल रखी गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को 5 साल की छूट मिलेगी। सारी छूटों के बाद भी उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

कैसे होगा चयन और कहां देनी होगी परीक्षा

चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के नतीजों पर निर्भर करेगा। परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे और हर सही जवाब पर एक अंक मिलेगा, जबकि गलत जवाब देने पर चौथाई अंक काट लिया जाएगा। दो घंटे पंद्रह मिनट की यह परीक्षा 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होकर सवा बारह बजे तक चलने की संभावना है। इसके लिए 16 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, राजनांदगांव जैसे शहर शामिल हैं।

एनटीए में निकली कई पदों पर भर्ती, यंग प्रोफेशनल को भी मौका

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अलग-अलग क्षेत्रों में कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के तहत कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, टेस्ट सिक्योरिटी और ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। अलग-अलग प्रोफेशनल असाइनमेंट के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

इसके अलावा, एनटीए ने यंग प्रोफेशनल पदों पर भी आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा, वैकेंसी और अन्य पात्रता शर्तों की जांच कर लें। आवेदन प्रक्रिया और पदों से जुड़ी विस्तृत जानकारी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

इन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में स्पेशलिस्ट पदों के साथ यंग प्रोफेशनल के पद भी शामिल हैं। एजेंसी की ओर से जारी वैकेंसी डिटेल के अनुसार कुल 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों का विवरण इस प्रकार है:

पद का नाम- पदों की संख्या

- वीडियो एडिटर कम ग्राफिक डिजाइनर - 1
- इंग्लिश कंटेंट राइटर-1
- डेटा एनालिस्ट कम मीडिया मॉनिटरिंग एग्जीक्यूटिव - 1
- रिसर्चर- 1
- जनरल मैनेजर - टेस्ट सिक्योरिटी एंड लाइव ऑपरेशंस - 1
- यंग प्रोफेशनल - एकेडमिक रिसर्च- 12
- यंग प्रोफेशनल - लीगल रिसर्च- 2
- यंग प्रोफेशनल - फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिसर्च- 2
- कुल 21

इनमें यंग प्रोफेशनल - एकेडमिक रिसर्च के लिए सबसे ज्यादा 12 पद हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से जांच लें।

ऐसे करें आवेदन

भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

1. सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं।
2. वेबसाइट पर दिए गए संबंधित भर्ती विज्ञापन को खोलें।
3. विज्ञापन में दी गई पात्रता, योग्यता और पद से जुड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ें।
4. इसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
5. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
6. आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
7. भरा हुआ आवेदन निर्धारित ईमेल आईडी dir-admin@nta.gov.in पर भेज दें।
8. भविष्य में जरूरत पड़ने के लिए भेजे गए आवेदन की एक कॉपी सुरक्षित रख लें।

प्रतिभा सेतु पोर्टल से करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से जांच लें। साथ ही, आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी भी अच्छी तरह पढ़ना जरूरी है। इन यंग प्रोफेशनल पदों के लिए आवेदन यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

इनोवेटिव आइडिया देकर जीतें 5 लाख तक का कैश प्राइज

फाइनल प्रेजेंटेशन और पुरस्कार वितरण अक्टूबर में

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। अगर आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास स्पेस या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई शानदार आइडिया है, तो आपके लिए बड़ा मौका है। दरअसल, वायासेट ने 'स्पेस फॉर गुड इंडिया चैलेंज 2026' लॉन्च किया है। इस प्रतियोगिता में छात्र अपने इनोवेटिव आइडिया को पेश कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने पर 5 लाख रुपये तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता में छात्रों को स्पेस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने का मौका भी मिलेगा।

क्या है 'स्पेस फॉर गुड इंडिया चैलेंज'

बता दें कि यह चैलेंज भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को यह सोचने का मौका देना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल अंतरिक्ष अभियानों तक सीमित न रहकर पृथ्वी पर लोगों और समुदायों की समस्याओं को हल करने में कैसे किया जा सकता है। देशभर के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने तकनीकी और क्रिएटिव आइडिया पेश कर सकते हैं।

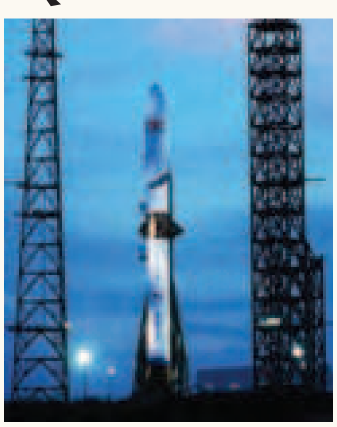

किन विषयों पर बना सकते हैं आइडिया?

प्रतिभागी ऐसे क्षेत्रों में समाधान तैयार कर सकते हैं, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इनमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स , ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस तक टिकाऊ पहुंच जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों में कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने से जुड़े आइडिया भी प्रतियोगिता का हिस्सा हो सकते हैं। छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी तकनीकी जानकारी और रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके ऐसे समाधान तैयार करें, जो वास्तविक दुनिया में उपयोगी साबित हो सकें। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। पहले स्थान पर आने वाले छात्र को 5 लाख रुपये, दूसरे स्थान के विजेता को 3.75 लाख रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्र को 2.75 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों को स्पेस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत और अपने आइडिया को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की मेंटरशिप भी मिलेगी।

कैसे होगा चैलेंज?

प्रतियोगिता कई चरणों में आयोजित होगी। शुरुआत में प्रतिभागियों को अपने आइडिया की डिजिटल सबमिशन करनी होगी। चयनित प्रतिभागी अगले चरण में पहुंचेंगे।

आईटीबीपी में मेडिकल ऑफिसर के 282 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

दीपक सहगल

आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 सितंबर

नई दिल्ली। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) ने ग्रुप 'ए' के तहत मेडिकल ऑफिसर के कुल 282 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी आईटीबीपी के आधिकारिक भर्ती पोर्टल recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) निर्धारित की गई है।

पदों की डिटेल्स और सैलरी

इस भर्ती के माध्यम से कुल 282 पदों को भरा जाएगा।

- सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (सेकेंड-इन-कमांड): कुल 05 पद (वेतनमान: पे मैट्रिक्स लेवल-12- 78,800 रुपये - 2,09,200 रुपये)।

- स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (डिप्टी कमान्डेंट): कुल 162 पद (वेतनमान: पे मैट्रिक्स लेवल-11, 67,700 रुपये - 2,08,700 रुपये)।
- मेडिकल ऑफिसर (असिस्टेंट कमान्डेंट): कुल 115 पद (वेतनमान: पे मैट्रिक्स लेवल-10, 56,100 रुपये - 1,77,500 रुपये)।

शैक्षणिक योग्यता: मेडिकल ऑफिसर पदों के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस या संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा व सुपर स्पेशलिटी योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का नेशनल मेडिकल कमीशन या राज्य मेडिकल काउंसिल में वैलिड रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: मेडिकल ऑफिसर (असिस्टेंट कमान्डेंट) के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए 40 वर्ष तथा सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिकों और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू/पर्सनालिटी टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

- अभ्यर्थी सबसे पहले आईटीबीपी के आधिकारिक भर्ती पोर्टल recruitment.itbpolice.nic.in पर जाएं।
- वहां रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रोफाइल बनाएं और एप्लीकेशन फॉर्म में सभी शैक्षणिक व व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
- मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद श्रेणी अनुसार शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म जमा कर उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2107 पदों पर भर्ती के लिए तय होगी योग्यता

ब्लिट्ज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के 330 एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली 2107 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक उच्च स्तरीय समिति समकक्ष अर्हता का स्पष्ट निर्धारण करेगी।

उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे गए सभी विषयों और उपाधियों की शैक्षणिक व विशेष अर्हता की समकक्षता को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद योग्यता को लेकर होने वाले कानूनी विवादों और मुकदमों पर ब्रेक लगेगा।

बद्री नाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय समिति

शासन में उच्च शिक्षा अनुभाग के उपसचिव संजय कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार विशेष सचिव बद्री नाथ सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है।

समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह आगामी 15 दिनों के भीतर अपनी स्पष्ट संस्तुतियों सहित पूरा प्रस्ताव प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को सौंपेगी।

कौन-कौन हैं समिति के सदस्य ?

गठित समिति में प्रशासनिक अधिकारियों और शिक्षाविदों को शामिल किया गया है:

- अध्यक्षः बद्री नाथ सिंह (विशेष सचिव)
- सदस्य सचिवः उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा नामित अधिकारी
- सदस्यः शकील अहमद सिद्दीकी (संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग)
- सदस्यः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव द्वारा नामित अधिकारी
- सदस्यः लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित अधिकारी

गौरतलब है कि कार्मिक विभाग ने 7 अक्तूबर 2021 को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। निर्देशों के मुताबिक, जहां भी सेवा या भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हता के साथ 'समकक्ष अर्हता' शब्द का उल्लेख हो, वहां चयन प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही समकक्षता को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया जाए। इसके बाद ही पदों का अधियाचन चयन एजेंसियों को भेजा जाना चाहिए।

कार्मिक विभाग ने लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विभिन्न भर्ती बोर्डों से भी यह अपेक्षा की थी कि वे पद विज्ञापित करने से पहले विज्ञापन में ही समकक्ष अर्हता का स्पष्ट उल्लेख करें। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का विज्ञापन जारी करने से पहले शासन से समकक्षता स्पष्ट करने का अनुरोध किया था।

पशुधन प्रसार अधिकारी के 1251 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने पशुधन प्रसार अधिकारी की 1200 से ज्यादा रिक्तियां निकाली हैं। हाल ही में इस नई भर्ती से जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन आयोग ने अपनी वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी किया है। यह भर्ती पशुपालन निदेशालय के अंतर्गत की जाएगी। कुल मिलाकर सभी कैटेगिरी में 1251 पदों को भरा जाएगा। यूपीएसएसएससी की बाकी भर्तियों की तरह इसमें भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी 2025) के जरिए शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। इसके बाद सीधे मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों को उपस्थित होना होगा।

योग्यता

- मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से साइंस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट (12वीं) या समकक्ष परीक्षा पास की हो।
- 12वीं के बाद किसी पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय/पशुचिकित्सा महाविद्यालय से दो साल का पशुधन प्रसार डिप्लोमा होना चाहिए।
- अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए।
- अधिमानी अर्हता में प्रादेशिक सेना में दो साल की सेवा एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो ये भी लग सकते हैं।
- अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो और अधिकतम उम्र 40 वर्ष का न हुआ हो।
- अधिकतम उम्र में एससी/एसटी और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी।
- प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2025) में शामिल हुआ हो, इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड होना चाहिए।

ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर

09 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे

- अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 सितंबर रहेगी।
- एप्लिकेशन फीस और फॉर्म सुधार करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर
- एप्लिकेशन फीस सभी वर्गों के लिए ₹25 ।

बिहार में एजुकेशन से जुड़े चार विभागों का होगा एक कल्याण निदेशालय

ब्लिट्ज ब्यूरो

सम्राट चौधरी बोले, शिक्षा-परीक्षा में होगा सुधार

पटना। बिहार में शिक्षा और परीक्षा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अहम एलान किए हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को बिहार का भविष्य बताते हुए कहा कि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

बिहार में छात्र कल्याण से जुड़े कामकाज को प्रभावी ढंग से लागू करने और समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए चार सरकारी विभागों का एक अलग निदेशालय गठित होगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी तथा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग मिलकर यह निदेशालय बनाएंगे। इस नई व्यवस्था से शिक्षा और परीक्षा में सुधार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिवेशन भवन में शिक्षा अधिकारियों के दो दिवसीय कार्यशाला सह चिंतन शिविर के उद्घाटन के मौके पर यह घोषणा की। कार्यशाला में शिक्षा विभाग के 322 अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा और परीक्षा में सुधार के लिए दो राज्यस्तरीय कमेटियों के गठन की भी घोषणा की। एक कमेटी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराएगी ताकि हर विद्यालय उत्कृष्टता का केंद्र बने और छात्रों के सीखने के स्तर में निरंतर सुधार हो। दूसरी कमेटी परीक्षा सुधार की होगी, जो परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए कार्य करेगी। यह समिति बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ कक्षा आधारित मूल्यांकन में तकनीकी एवं एआई के उपयोग के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, समझ एवं विश्लेषण क्षमता के बेहतर आकलन का सुझाव देगी।

मुख्यमंत्री ने युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आने वाली पीढ़ी ही राज्य का नवनिर्माण करेगी। सरकार ऐसी शिक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहती है, जिससे बिहार के बच्चों को बेहतर पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा कि समर्थ लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं लेकिन, संसाधनों की कमी से जूझने वालों के लिए बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगभग 18 हजार करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं और इसका बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में जा रहा है। कोटा में लाखों बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पढ़ाने वाले अधिकतर शिक्षक भी बिहार के हैं।

छात्रों के लिए प्रत्येक माह सहयोग शिविर लगेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक एवं वरीय पदाधिकारी स्कूलों-कॉलेजों में जाकर छात्रों से संवाद करेंगे। उनसे प्राप्त सुझावों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह छात्रों के लिए सहयोग शिविर का आयोजन होगा और उनकी समस्याओं और सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबतक 551 मॉडल स्कूल बनाए जा चुके हैं। लक्ष्य 1001 मॉडल स्कूल बनाने का है। शिक्षा से जुड़े अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट और सीसीए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दोषियों को एक वर्ष तक कैद का प्रावधान है।

किसान के बेटे ने दूसरे अटैम्प्ट में हिंदी मीडियम से किया यूपीएससी क्रैक

सात किमी दूर साइकिल से जाते थे कोचिंग के लिए, कहा- कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है स्टडी मैटीरियल

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। छोटे-छोटे शहरों, गांवों और कस्बों में ज्यादातर छात्र आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। इस सपने को साकार करने के लिए छात्रों को यूपीएससी की सिविल सर्विसेस एग्जाम को पास करना पड़ता है, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ छात्र पहले ही अटैम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और कुछ 2 या उससे अधिक प्रयास में। कुछ ऐसी ही कहानी है आदित्य सिंह की, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों की चुनौतियों को पार करते हुए यूपीएससी की परीक्षा दूसरे ही प्रयास में पास कर ली। हालांकि उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। उनके पिता एक किसान हैं और मां हाउसवाइफ। ऐसे में इस उपलब्धि से न सिर्फ वह अपने माता-पिता को गौरवान्वित कर रहे हैं, बल्कि अपने गांव और जिले का नाम भी रोशन कर रहे हैं।

कौन हैं आदित्य सिंह

आदित्य सिंह आजमगढ़ जिले के लालपुर गौहर गांव के निवासी हैं। वो चार भाई बहन हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें पढ़ाई के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब वो कक्षा 12वीं में तब उनके मन में आईएएस बनने का ख्याल आया। हालांकि तब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि यूपीएससी में कितने पेपर होते हैं, या क्या सिलेबस होता है।

कहां से मिली प्रेरणा

एक इंटरव्यू में आदित्य सिंह बताते हैं कि उन्हें आईएएस बनने की प्रेरणा गांव और परिवार की समस्याओं को देखकर मिली। वो कहते हैं कि गांव में छोटी-छोटी स्कीमों को लेकर कोई जागरुकता नहीं है। साथ ही गांव में इंफ्रा से लेकर कनेक्टिविटी तक कई सारी समस्याएं हैं।

उनका मानना है कि इन सभी समस्याओं को एक अच्छा सिविल सर्वेंट ही खत्म कर सकता है। ऐसे में बचपन से ही दिमाग में ये था कि मुझे भी अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है।

पिता जी का सबसे ज्यादा रहा योगदान

आदित्य सिंह की सफलता के पीछे कई लोगों का योगदान रहा लेकिन सबसे ज्यादा योगदान उनके पिता जी का था। साथ ही छोटी बहन का भी खूब सहयोग रहा। वो बताते है कि अगर किसी ने मेरी पूरी जर्नी को अच्छे तरीके से जाना है, तो मेरी छोटी दीदी है, जो अभी पढ़ाई कर रही है।

आदित्य सिंह यूपीएससी की तैयारी के लिए आजमगढ़ से प्रयागराज पहुंचते थे। हालांकि वो दिल्ली में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति की वजह से उन्होंने प्रयागराज का चुनाव किया। उन्होंने दृष्टि कोचिंग संस्थान से पढ़ाई की।

आदित्य सिंह के कमरे से कोचिंग केंद्र की दूरी करीब 7 किलोमीटर थी। ऐसे में वो रोजाना साइकिल से कोचिंग जाया करते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में ये कोचिंग ज्वाइन की।

कितने घंटे पढ़ते थे आदित्य

यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आदित्य सिंह करीब 8 से 9 घंटे रोजाना पढ़ाई करते थे। हालांकि वो बताते हैं कि प्रीलिम्स के बाद पढ़ाई की टाइमिंग और मेहनत दोगुनी हो जाती है।

2024 में दिया पहला अटैम्प्ट

आदित्य सिंह हिंदी मीडियम के छात्र थे। उन्होंने अपना पहला अटैम्प्ट 2024 में दिया। इसे बाद वो दिल्ली आए गए। यहां आने के बाद उन्होंने पिछली कमियों पर काम किया और उन्हें सुधारा।

पिछले कई सालों से नहीं मनाई दिवाली और होली

आदित्य सिंह बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने न जाने कितने त्याग किए। वो पिछले कई सालों से होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर भी घर नहीं जाते थे। हालांकि उनकी मेहनत रंग लाई और दूसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में 508वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल की है।

यूपीएससी की तैयारी के लिए प्लानिंग

आदित्य सिंह ने बताया कि सबसे जरूरी है स्टडी मैटीरियल। आपको इनको एक बार बहुत ध्यान से चुन लेना है और इसी पर भरोसा करना है। साथ ही पीवाईक्यू का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। वो बताते हैं कि अगर आप पीवाईक्यू (प्रीवियस ईयर क्वेश्चन) नहीं देखते हैं, तो गलत डायरेक्शन में जाते हैं। इसके लिए खूब मेहनत करते रहिए। आदित्य सिंह की यह जर्नी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।

5 देशों से करें एमबीबीएस, बिना एफएमजीई परीक्षा दिए भारत में कर सकेंगे डॉक्टरी

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत में हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और इसके लिए नीट की तैयारी करते हैं। हालांकि, देश में सीमित एमबीबीएस सीटों और कड़े मुकाबले के कारण बड़ी संख्या में छात्र विदेश जाकर एमबीबीएस करने का रास्ता चुनते हैं। रूस, चीन, यूक्रेन जैसे देशों से पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत लौटने पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (एफएमजीई) को पास करना होता है।

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) द्वारा आयोजित एफएमजीई परीक्षा का पास प्रतिशत अक्सर बहुत कम रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 5 ऐसे देश भी हैं जहां से यदि आप एमबीबीएस मेडिकल की डिग्री प्राप्त करते हैं, तो आपको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजीई परीक्षा देने की जरूरत नहीं होती?

ये हैं वे 5 देश

अमेरिका : अमेरिका में छात्रों को एमबीबीएस की जगह एमडी की डिग्री दी जाती है। वहां डॉक्टर बनने के लिए पहले चार साल का ग्रेजुएशन और फिर चार साल का एमडी कोर्स करना होता है, जिसमें कुल आठ साल का समय लगता है। इसी दौरान छात्रों को उच्च स्तरीय प्रैक्टिकल और क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। यही कारण भारत में अमेरिका से पढ़े डॉक्टरों को बिना एफएमजीई परीक्षा के सीधे प्रैक्टिस की इजाजत मिलती है।

यूनाइटेड किंगडम : ब्रिटेन (यूके) में एमबीबीएस की पढ़ाई 5 से 6 साल की होती है। यहां पढ़ाई की शुरुआत से ही छात्रों को नेशनल हेल्थ सर्विस (एनएचएस) के अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। यूके की विश्वस्तरीय शिक्षा गुणवत्ता के कारण भारत में उनकी डिग्री को सीधे स्वीकार किया जाता है।

कनाडा : कनाडा भी अमेरिका की तरह 8 साल का मेडिकल एजुकेशन पैटर्न अपनाता है, जिसमें 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री के बाद एमसीएटी परीक्षा पास कर 4 साल का एमडी प्रोग्राम पूरा करना होता है। यहां का मजबूत क्लिनिकल एक्सपोजर भारतीय छात्रों को भारत में बिना एफएमजीई दिए प्रैक्टिस का अवसर देता है।

ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया में 5 से 6 साल का मेडिकल प्रोग्राम होता है। यहां छात्रों को बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक क्लिनिकल ट्रेनिंग मिलती है। इस कारण ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त मेडिकल डिग्री को एनएमसी द्वारा सीधे मान्यता प्रदान की जाती है।

न्यूजीलैंड : न्यूजीलैंड में लगभग 6 साल की पढ़ाई के दौरान छात्रों को अस्पतालों में प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है। यहां की एमबीसीएचबी डिग्री को भारत में बिना किसी प्रवेश या लाइसेंसिंग परीक्षा के सीधे प्रैक्टिस के लिए मान्य माना जाता है।

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

छात्रों को इन पांच देशों में दाखिला लेने से पहले पढ़ाई की लागत, कोर्स की अवधि और एनएमसी के सभी नए दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी या शैक्षणिक अड़चन का सामना न करना पड़े।

आईआईटी धनबाद के 3 छात्रों को रिकॉर्ड 1.59 करोड़ का पैकेज

ब्लिट्ज ब्यूरो

धनबाद। आईआईटी, आईएसएम धनबाद के 2026 बैच के छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले हो रही है। बीटेक समेत अन्य कोर्स के छात्र-छात्राओं को देश-विदेश की नामी-गिरामी कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट के दौरान हाथों-हाथ लपकते हुए रोजगार दिया। कैंपस प्लेसमेंट में चार छात्र-छात्राओं को एक करोड़ रुपए से अधिक का पे पैकेज मिला है। इनमें तीन छात्रों को 1.59 करोड़ रुपए सालाना व एक छात्र को 1.22 करोड़ रुपए सालाना पैकेज मिला है। 1.59 करोड़ रुपए का पैकेज अमेजन जापान की ओर से देने की चर्चा है। संस्थान ने इन चार छात्र-छात्राओं के नाम, ब्रांच व सीटीसी को गोपनीय रखा है।

अब तक का सर्वाधिक पे पैकेज

इसे अब तक का सर्वाधिक पे पैकेज माना जा रहा है। वहीं कोर्स वाइज सीटीसी की बात करें तो एमएससी के छात्रों को सबसे कम औसतन 9.16 लाख सालाना पे पैकेज मिला है। सर्वाधिक औसतन सीटीसी डुएल डिग्री (बीटेक प्लस एमटेक) को 31.07 लाख मिला है।

1153 विद्यार्थियों को जॉब ऑफर

संस्थान के कॅरियर डेवलपमेंट सेंटर ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 का कैंपस प्लेसमेंट डेटा जारी कर दिया है। संस्थान के 1153 विद्यार्थियों को जॉब ऑफर मिला। इनमें से 214 को प्री प्लेसमेंट ऑफर प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि छह छात्रों (बीटेक से 1, इंटीग्रेटेड एमटेक से 2, एमटेक से 3) को विदेशी कंपनियों ने इंटरनेशनल जॉब ऑफर दिया है। वहीं पीएसयू से 67 को नौकरी मिली। देश के अंदर कंपनियों ने संस्थान के 1016 छात्रों को नौकरी ऑफर दिया।

350 से ज्यादा कंपनियां आईं

फुल टाइम हायरिंग के लिए 350 से ज्यादा कंपनियां आईआईटी आईएसएम धनबाद पहुंचीं। 275 से अधिक छात्रों को 20 लाख से अधिक का पे पैकेज मिला, जबकि 10 से 20 लाख पे पैकेज का ऑफर 422 छात्रों को दिया गया। 6 से 10 लाख तक सीटीसी का ऑफर 338 छात्र-छात्राओं को मिला।

जूनियर इंजीनियर के 3993 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए 14 अगस्त से प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिये जूनियर इंजीनियर के कुल 3993 पदों को भरा जाएगा। अगर आपके पास भी पद से संबंधित पात्रता है, तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर है।

भर्ती से संबंधित जरूरी तिथि

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट: 14 अगस्त
- रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट: 13 सितंबर
- फीस जमा करने की लास्ट डेट: 15 सितंबर

- फॉर्म में सुधार करने की तिथि: 16 से 25 सितंबर

कितनी मिलेगी सैलरी

जूनियर इंजीनियर के पदों पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये दिए जाएंगे।

आयु-सीमा: आवेदन के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2027 के आधार पर की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन फीसः अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये और एससी एवं एसटी, महिला और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपये निर्धारित है।

कैसे होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन सीबीटी-1, सीबीटी-2, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। सीबीटी-1 में उम्मीदवारों से गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, विज्ञान आदि विषयों से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।

- सीबीटी-1 परीक्षा में पास होने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत अंक, ओबीसी और एससी उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक और एसटी उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
- इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवार सीबीटी-2 की परीक्षा में शामिल होंगे। सीबीटी-2 की परीक्षा में 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे।

कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में निकली 15 हजार शिक्षकों की भर्ती

आवेदन की अंतिम तिथि 07 सितंबर

नई दिल्ली। कर्नाटक में प्राइमरी और हाई स्कूल में सरकारी शिक्षक के कुल 15 हजार पदों पर भर्ती निकली है। ऐसे में अगर आप सरकारी टीचर के भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो बहुत जल्द ऑफिशियल वेबसाइट schooleducation.karnataka.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर दें।

इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू हो गई। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 07 सितंबर निर्धारित की गई है। सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होने के बाद वे तय समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें।

भर्ती संबंधित विवरण

इस भर्ती अभियान के जरिये कुल 15 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी, पदानुसार भर्ती संबंधित विवरण की जानकारी नीचे दी गई है।

पद का नाम- कुल पद

- जीपीएसटीआर- 8,500
- असिस्टेंट मास्टर (एएम)- 4,500
- प्राइमरी स्कूल टीचर- 900
- फिजिकल एजुकेशन टीचर - 600
- कंप्यूटर साइंस टीचर- 500

आवेदन करने के लिए योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री बीएड /डीएड/टीईटी भी होनी चाहिए।

आयु-सीमा: इन पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

रजिस्ट्रेशन फीसः आवेदन करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस का भी भुगतान करना होगा। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 750 रुपये और एससी एवं एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है।

21 की उम्र में किसान के बेटे ने पास की यूपीएससी परीक्षा

आईएएस अभिषेक मीणा बने हरियाणा के 'यंगेस्ट कलेक्टर'

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। सिविल सेवा परीक्षा को पास करने में अभ्यर्थियों को सालों की मेहनत और कई प्रयास लग जाते हैं लेकिन जब इरादे बुलंद हों और सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत की जाए, तो सफलता उम्र की मोहताज नहीं रहती। इस बात को सच साबित कर दिखाया है राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले अभिषेक मीणा ने, जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में अपने पहले ही प्रयास में आईएएस अफसर बनने का कीर्तिमान स्थापित किया।

वर्तमान में हरियाणा कैडर के इस युवा अधिकारी की पहचान राज्य के सबसे कम उम्र के जिला कलेक्टर के रूप में होती है, जो अपने काम से लाखों युवाओं के प्रेरणास्रोत बन चुके हैं।

आईआईटी से आईएएस तक का सफर

अभिषेक मीणा बचपन से ही पढ़ाई में बेहद होनहार थे। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग के दौरान ही उनके मन में देश सेवा करने और प्रशासनिक व्यवस्था में जाकर समाज के लिए कुछ बड़ा करने का विचार आया। इंजीनियरिंग

लक्ष्य स्पष्ट है तो कोई भी मंजिल पाना असंभव नहीं

पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने बिना समय गंवाए यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। अपनी सटीक स्ट्रैटेजी, टाइम मैनेजमेंट और कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने वर्ष 2016 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में 114वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर ली।

2016 बैच के आईएएस अधिकारी के रूप में चयन के बाद अभिषेक मीणा को हरियाणा कैडर आवंटित किया गया। उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत में विभिन्न विभागों में सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त उपायुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दीं।

उनकी शानदार कार्यप्रणाली, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और जनता से जुड़ाव को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी। इतनी कम उम्र में जिला मजिस्ट्रेट का पद संभालकर उन्होंने हरियाणा के इतिहास में सबसे युवा जिला कलेक्टरों में अपना नाम दर्ज करा लिया।

यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए सीख

अभिषेक मीणा की सफलता की कहानी यह साबित करती है कि यूपीएससी में सफलता पाने के लिए बैकग्राउंड से ज्यादा निरंतरता और दृढ़ संकल्प मायने रखता है।

आईआईटी जैसी कठिन परीक्षा पास करने के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आकर्षक सैलरी पैकेज को छोड़कर सिविल सेवा को चुनना और पहली बार में ही इसे क्रैक कर लेना युवाओं को यह संदेश देता है कि यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो कोई भी मंजिल पाना असंभव नहीं है।

एसबीआई में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के 9124 पदों पर होगी भर्ती

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार बैंक में बतौर क्लर्क के रूप में नौकरी करना चाहते हैं, वे इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं। बैंक में क्लर्क के कुल 9124 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 31 अगस्त, तक अप्लाई कर सकते हैं।

जरूरी योग्यता: जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। वे उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र होंगे, जो स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है।

- उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अप्रैल, 2026 के आधार पर होगी। आयु 20 से 28 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
- ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट, एससी एवं एसटी को 5 वर्ष की और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

कैसे होगा चयन

जूनियर एसोसिएट क्लर्क के पदों पर चयन तीन चरणों में किया जाएगा। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण मुख्य परीक्षा और तीसरा चरण लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिग एबिलिटी से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। यह परीक्षा एक घंटे लिए होगी, जिसमें प्रत्येक गलत सवाल के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 200 अंकों के लिए संचालित की जाएगी। इस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए आमंत्रित किए जाएंगे।

मायने रखता है ईंधन का अर्थशास्त्र

इथेनॉल से बचने के लिए ग्राहक महंगे पेट्रोल की ओर बढ़ रहे हैं

ई0 और ई10 की वापसी नहीं हो रही है, और इसकी वजह आर्थिक है। इथेनॉल की क्षमता तय कीमतों पर पक्की खरीद के भरोसे बनाई गई थी — 2025-26 में सी-हैवी मोलासेस के लिए ₹57.97 प्रति लीटर, गन्ने के रस के लिए ₹65.61, और मक्के के लिए ₹71.86। इस क्षमता के पीछे बैंक लोन है, और बैंक लोन के पीछे सरकारी आदेश है। आदेश को कमजोर करने से यह एसेट बेकार हो जाएगा।

ब्लिट्ज ब्यूरो

दिल्ली और मुंबई के कुछ पेट्रोल पंपों पर, कुछ वाहन चालक ऐसा कर रहे हैं जो दो साल पहले अजीब लगता था। वे ₹160 प्रति लीटर वाले पेट्रोल के लिए लाइन में लग रहे हैं, जबकि उनके बगल वाला पंप इसे ₹102.12 में बेच रहा है। मुंबई में यही ईन्धन ₹167.35 का है, जबकि सामान्य पेट्रोल ₹111.21 का है। यह 100-ऑक्टेन वाला पेट्रोल है, और इसकी खासियत यह है कि इसमें बिल्कुल भी इथेनॉल नहीं है।

हाल के महीनों में इसकी बिक्री दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है और जुलाई में इसमें सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। हालांकि, इसका पैमाना अभी भी बहुत कम है, यह भारत की कुल पेट्रोल बिक्री का 0.1 प्रतिशत है, और देश के एक लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में से 1 प्रतिशत से भी कम जगहों पर उपलब्ध है (ज्यादातर बड़े शहरों में)। इसे इंडियन ऑयल एक्सपी100, बीपीसीएल स्पीड 100 और एचपीसीएल पॉवर 100 के नाम से बेचा जाता है। लेकिन कुछ भारतीय जो 57 प्रतिशत ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं। इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि यह पिछले दशक के सबसे सफल औद्योगिक कार्यक्रमों में से एक के खिलाफ ग्राहकों का पहला संकेत है।

इस उपलब्धि पर कोई विवाद नहीं है, और यह बहुत बड़ी है। अब इस कार्यक्रम को बचाव की नहीं, बल्कि डेटा की जरूरत है।

आयात घटाने की दिशा में सफल कदम

भारत का इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम

2013-14 में 1.5% से कम ब्लेंडिंग से बढ़कर 2025-26 तक 20% तक पहुंच गया है। यह मूल लक्ष्य (2030) से पाँच साल पहले हासिल किया गया है; आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने मार्च 2025 में इस लक्ष्य को 2025-26 तक पूरा करने का फैसला किया था। सिर्फ़ ब्राज़ील ही इससे ज़्यादा ब्लेंडिंग करता है, जिसने अगस्त 2025 में E30 का स्तर हासिल किया था।

पेट्रोलियम मंत्रालय के 10 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार, इसके फ़ायदे इस प्रकार हैं: ₹1.97 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत, 316 लाख टन कच्चे तेल (क्रूड) के आयात में कमी, 952 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती, और 2014-15 से किसानों को ₹1.66 लाख करोड़ का भुगतान। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए आईआईटी कानपुर के आकलन के अनुसार, जुलाई 2018 और अगस्त 2023 के बीच ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 183 डिस्टिलरी को फ़ंडिंग मिली, जिससे डिस्टिलेशन क्षमता 2014 में 421 करोड़ लीटर से बढ़कर लगभग 2,000 करोड़ लीटर हो गई यानी लगभग पांच गुना बढ़ोतरी। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 88.5% कच्चा तेल आयात करता है; ब्लेंडिंग के ज़रिए इस्तेमाल होने वाला हर लीटर तेल, आयात न किए गए तेल के बराबर है।

आंकड़ों में अंतर कहां है?

ग्राहकों के लिए मुख्य सवाल माइलेज का है, और इस मामले में एक ही चीज़ के लिए चार अलग-अलग आधिकारिक आंकड़े मौजूद हैं। नीति आयोग के 'भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए रोडमैप 2020-25' (जो इस प्रोग्राम का मुख्य दस्तावेज़ है) के अनुसार, ई0 के लिए डिज़ाइन की गई और ई10 के लिए कैलिब्रेट की गई चार-पहिया गाड़ियों की क्षमता में 6-7 प्रतिशत, ऐसी दो-पहिया गाड़ियों में 3-4 प्रतिशत, और ई10 के लिए डिज़ाइन की गई और ई20 के लिए कैलिब्रेट की गई चार-पहिया गाड़ियों में 1-2 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया गया था। पेट्रोलियम मंत्रालय का आधिकारिक बयान 3-5 प्रतिशत का रहा है। 'सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' (सियाम) नियंत्रित टेस्टिंग के आधार पर 2-4 प्रतिशत का आंकड़ा बताती है। और 30 जुलाई को, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि क्षमता में गाड़ी की श्रेणी और उम्र के आधार पर 2 से 6 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है।

इनमें से कोई भी आंकड़ा गलत नहीं है। ये अलग-अलग तरह की गाड़ियों के समूह (फ्लीट) को मापते हैं। मुश्किल यह है कि भारत को यह नहीं पता कि उसकी गाड़ियों का समूह इनमें किस तरह बंटा हुआ है।

27 जुलाई को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि मंत्रालय ने भारत में ई20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह से चलने लायक गाड़ियों के सटीक प्रतिशत के बारे में कोई आकलन नहीं किया है। जिन गाड़ियों की बात हो रही है, उनमें 20 करोड़ दो-पहिया और 3 करोड़ पेट्रोल कारें शामिल हैं।

इंजीनियरिंग से जुड़े सबूत भरोसा दिलाने वाले हैं। गडकरी के जवाब में यह भी बताया गया कि एआरएआई, सियाम और आईओसीएल द्वारा बीएस-III, बीएस-IV और बीएस-VI गाड़ियों पर की गई टेस्टिंग में डायनामोमीटर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट या रोड ट्रायल, किसी में भी ई20 के कारण कोई खराबी नहीं देखी गई। मारुति सुजुकी ने 2025-26 में 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग की, जिनमें 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां थीं जो ई20 के लिए सर्टिफाइड नहीं थीं; इनमें इथेनॉल से होने वाले जंग या असामान्य टूट-फूट की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। सियाम के पी.के. बनर्जी ने अगस्त 2025 में कहा कि ₹गाड़ी खराब होने या इंजन फेल होने की एक भी घटना सामने नहीं आई है और उन्होंने पुष्टि की कि वारंटी और इंश्योरेंस क्लेम का पूरा सम्मान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को ई20 लागू करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।

एथेनॉल ब्लेंडिंग एक नजर में

ब्लेंडिंग, 2013-14	1.5% से कम
ब्लेंडिंग, ESY 2025-26	20% — पाँच साल पहले
2014-15 से बचाई गई विदेशी मुद्रा	1.97 लाख करोड़
किसानों को भुगतान	1.66 लाख करोड़
कच्चे तेल की जगह इस्तेमाल	316 लाख टन
CO उत्सर्जन में कमी	952 लाख टन
डिस्टिलेशन क्षमता	421 करोड़ लीटर (2014) ₹2,000
	करोड़ लीटर (2026)
एथेनॉल की सप्लाई, ESY 2025-26	1,200+ करोड़ लीटर
सड़क पर मौजूद वाहन	20 करोड़ दोपहिया वाहन,
	3 करोड़ पेट्रोल कारें
कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता	₹88.5%

यह पॉलिसी क्यों बस ऐसे ही वापस नहीं ली जा सकती

ई0 और ई10 की वापसी नहीं हो रही है, और इसकी वजह आर्थिक है। इथेनॉल बनाने की क्षमता इन तय कीमतों पर पक्की खरीद के भरोसे बनाई गई थी — 2025-26 में सी-हैवी मोलासेस के लिए ₹57.97 प्रति लीटर, गन्ने के रस के लिए ₹65.61, और मक्केके लिए ₹71.86। इस क्षमता के पीछे बैंक लोन है, और बैंक लोन के पीछे सरकारी आदेश है। आदेश को कमजोर करने से यह एसेट बेकार हो जाएगा।

कच्चे माल के इस्तेमाल में भी ध्यान देने लायक बदलाव हुए हैं। 2023-24 में इथेनॉल उत्पादन में मक्के का हिस्सा 42.74 प्रतिशत था, जो सबसे बड़ा हिस्सा है; खरीफ मक्के का रकबा 2024-25 में 83.15 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 91.89 लाख हेक्टेयर हो गया, जो 10.5 प्रतिशत और पांच साल के औसत से 16.3 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि तिलहन का रकबा लगभग 7 लाख हेक्टेयर कम हो गया। भारत के मक्के का 60-70 प्रतिशत हिस्सा पोल्ट्री और पशु चारे में इस्तेमाल होता है। पानी के मामले में, नीति आयोग के रोडमैप के अनुसार, गन्ने से इथेनॉल बनाने में प्रति लीटर इथेनॉल लगभग 3,000 लीटर पानी लगता है और चावल से इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर से ज्यादा।

आगे का काम

चार उपाय ऐसे हैं जिनसे सरकारी आदेश में बदलाव किए बिना भरोसे की कमी को दूर किया जा सकता है, और हर उपाय एक साल के भीतर पूरा किया जा सकता है।

- मॉडल के हिसाब से कम्पैटिबिलिटी रजिस्टर जारी करें। मंत्रालय के अपने जवाब में माना गया है कि गाड़ियों के बेड़े का कोई आकलन मौजूद नहीं है।
- गाड़ियों की मेक, मॉडल और साल के हिसाब से एक सार्वजनिक और सर्च करने लायक लिस्ट — अप्रैल 2023 से E20-मटीरियल-कम्पैटिबल, अप्रैल 2025 से ई20-ट्यून्ड से अटकलों की जगह सही जानकारी मिल सकेगी।
- वारंटी स्टेटमेंट को स्टैंडर्डाइज करें। सियाम ने मौखिक रूप से भरोसा दिलाया है। एक कॉमन ओईएम घोषणा, जो ओनर मैनुअल में छपी हो और सर्विस सेंटर पर दिखाई जाए, ज्यादा असरदार होगी।
- स्वतंत्र और सार्वजनिक माइलेज टेस्टिंग करवाएं। नीति आयोग के रोडमैप में बताई गई 1-7 प्रतिशत की रेंज ईमानदार इंजीनियरिंग पर आधारित है। कैटेगरी के हिसाब से नतीजे पब्लिश करने से — जैसे 2023 से पहले के टू-व्हीलर और 2025 के बाद की कारें — खरीदार अपना नंबर देख पाएंगे। इस प्रोग्राम की पूरी लागत का हिसाब लगाएं।

'काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर' (सीईईडब्ल्यू) ने जुलाई में अनुमान लगाया था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 2024-25 में इथेनॉल के लिए ₹62,566 करोड़ चुकाए, जबकि सब्सिडी और न मिलने वाले रेवेन्यू को जोड़ने पर इसकी असल पब्लिक कॉस्ट ₹87,390 करोड़ थी। सीईईडब्ल्यू की सलाह के मुताबिक, सालाना पूरी लागत का स्टेटमेंट पब्लिश करने से प्रोग्राम कमजोर होने के बजाय और मजबूत होगा। भारत ने यह इंडस्ट्री 12 साल में खड़ी की है। बाकी बचा काम उस काम से छोटा है जो पहले ही पूरा हो चुका है।

कार बनाने वाली कंपनियां आपस में क्या चर्चा करती हैं?

मीडिया की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कई कार बनाने वाली कंपनियों ने एक साल के दौरान 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 जगहों पर पंपों से 250 से ज्यादा फ़्यूल सैंपल इकट्ठा करके बड़े पैमाने पर टेस्ट किए। उन्हें 18 राज्यों के कई सैंपल में क्लोराइड की ज्यादा मात्रा और नमी (मॉइस्चर) भी मिली।

एग्जीक्यूटिव्स के ईमेल में डेटा की प्रमाणिकता (ऑथेंटिकेशन) को लेकर कोई चिंता नहीं जताई गई थी।

इन प्राइवेट ईमेल पर टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने बताया कि यह डेटा सिर्फ़ अंदरूनी जानकारी, चर्चा और पुष्टि के लिए था और इसे बहुत कम कार बनाने वाली कंपनियों ने इकट्ठा किया था।

मारुति, टाटा और महिंद्रा, जो रॉयटर्स द्वारा देखे गए सियाम के अंदरूनी ईमेल का हिस्सा थे, भारत के कार बाज़ार का 67 प्रतिशत हिस्सा हैं।

सियाम ने कहा कि टेस्टिंग का आधार और सैंपल का साइज़ पक्के नतीजे निकालने के लिए काफ़ी नहीं था, इसलिए बातचीत को वापस ले लिया गया क्योंकि इसे गलती से भेज दिया गया था। उन्होंने कहा कि वे एक सही वैज्ञानिक अध्ययन करने का इरादा रखते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सियाम से पत्र मिलने के दो हफ़्ते पहले ही, भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने रिटेल आउटलेट्स पर मिलावट की जांच के लिए फ़्यूल की सख़्त टेस्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा कि मिलावट के केवल चार मामले पाए गए। सरकारी फ़्यूल रिटेलर्स ने भी कहा कि बड़े पैमाने पर रैंडम और वैज्ञानिक टेस्ट से पता चला कि फ़्यूल में मिलावट को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है।

महिंद्रा ने कहा कि उसके एग्जीक्यूटिव के ईमेल से निकाले गए नतीजे पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत₹ हैं, इंडस्ट्री का डेटा सीमित और शुरुआती है, और उसे ई20 के साथ कोई समस्या नहीं दिखती। मारुति और टाटा ने टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया।

मारुति, टाटा, महिंद्रा और सियाम के बीच ग्रुप ईमेल में, मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव अनूप भट ने क्लोराइड की ज्यादा मात्रा मिलने पर चिंता जताई और कहा कि इस बारे में पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ प्राइवेट तौर पर चर्चा की गई थी।

इंडस्ट्री द्वारा ग्रुप ईमेल पर शेयर किए गए राज्य-वार नतीजों से पता चला कि उन्होंने राजस्थान में क्लोराइड का स्तर 6 से 570 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम), नई दिल्ली में 1.4 से 420 ppm और महाराष्ट्र में 10 से 357 पीपीएम दर्ज किया। सरकार का कहना है कि स्वीकार्य सीमा 3 पीपीएम है

ई बिक्री के बाद; अब मेथनॉल पर ध्यान देने का समय

इथेनॉल प्रोग्राम तो बहुत सफल रहा है, लेकिन दूसरे जरूरी केमिकल के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई गई

मेथनॉल कोई ऐसी चीज नहीं जो हमेशा सुर्खियों में रहती है, इसलिए इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

हरविंदर आहूजा

फरवरी 2026 में सऊदी अरब ने भारत के कुल मेथनॉल आयात का 34% हिस्सा सप्लाई किया था। मई तक यह सप्लाई ज़ीरो हो गई। इसी दौरान ओमान से होने वाली शिपमेंट लगभग दोगुनी हो गई – क्योंकि ओमान के एक्सपोर्ट टर्मिनल 'स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज' के बाहर हैं, जबकि सऊदी अरब के टर्मिनल वहां नहीं हैं।

ट्रेड डेटा में भूगोल का असर शायद ही कभी इतने साफ तौर पर दिखता है। क्रिसिल इंटेलिजेंस के अनुसार, अप्रैल 2025 और मई 2026 के बीच, भारत के मेथनॉल आयात में वेस्ट एशिया (पश्चिम एशिया) की हिस्सेदारी 88% से घटकर 51% रह गई। इस कमी को चीन ने पूरा किया, जिसकी हिस्सेदारी अप्रैल 2026 में 12% से बढ़कर मई में 26% हो गई – यानी तीन गुना हो गई। कीमतों का रिकॉर्ड और भी चौंकाने वाला है: मई में भारत में 'कॉस्ट-एंड-फ्रेट' (लागत और ढुलाई) कीमतें साल-दर-साल 141% बढ़ गईं; 2026-27 की पहली तिमाही में औसत कीमत $569 प्रति टन रही (114% की बढ़ोतरी); और मई में घरेलू कीमत ₹73,950 प्रति टन तक पहुंच गई (लगभग 182% की बढ़ोतरी)। मई के आखिर तक मेथनॉल से जुड़े लगभग 4.5 मिलियन टन उत्पादन पर असर पड़ा।

चीन वाला रास्ता ही सबसे अहम आंकड़ा है। 2024 में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था।

ज़ीरो से एक-चौथाई तक

एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के रिकॉर्ड के अनुसार, भारत ने 2025 में 3.4 मिलियन टन मेथनॉल का आयात किया, जो 13.5% ज्यादा था; इसमें वेस्ट एशिया की हिस्सेदारी 85% से ज्यादा थी। ओमान सबसे बड़ा सप्लायर था (1.6 मिलियन टन), उसके बाद सऊदी अरब (946,085 टन), कतर (328,932 टन) और बहरीन (237,290 टन) का नंबर था। उस साल चीन का योगदान 49,347 टन था – जबकि 2024 में यह बिल्कुल शून्य था। अठारह महीनों के भीतर ही यह मामूली मात्रा कुल खपत का एक-चौथाई हिस्सा बन गई।

मेथनॉल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बहुत चर्चा होती हो, इसलिए इस बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी, यह भारतीय उद्योग के लिए एक ज़रूरी कच्चा माल है: प्लाईवुड और कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेल्डिहाइड की खपत इसमें सबसे ज्यादा है, इसके बाद फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स, एसिटिक एसिड और एमटीबीई का नंबर आता है। अगर टैंकर नहीं आता है, तो फार्मास्यूटिकल प्लांट, फर्नीचर फ़ैक्टरी और पेंट बनाने वाली फ़ैक्टरी – सभी एक ही वजह से रुक जाते हैं।

देश में उत्पादन की क्षमता कितनी ?

भारत की निर्भरता एक ऐसे गणित पर आधारित है जो पिछले एक दशक से साफ़ दिख रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए किए गए सबसे हालिया सरकारी सर्वे के अनुसार, देश में कुल उत्पादन क्षमता 0.66 मिलियन टन सालाना थी, जो छह उत्पादकों – भरूच में जीएनएफसी, रायगढ़ में दीपक फ़र्टिलाइज़र्स, मुंबई में आरसीएफ, असम पेट्रोकेमिकल्स, जीएसएफसी और एनएफएल नांगल के बीच बंटी हुई थी। ये कंपनियाँ अपनी क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर रही थीं, जबकि 1.8 मिलियन टन का आयात किया जा रहा था। वह डेटा 2015-16 का है और उसे अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है लेकिन उसके बाद की स्थिति साफ़ है: आयात बढ़कर 3.4 मिलियन टन हो गया है, जबकि देश

में कोई बड़ी नई उत्पादन क्षमता नहीं बनी है।

नीति आयोग के मेथनॉल इकॉनमी प्रोग्राम, जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई थी, की सोच कुछ अलग थी– पेट्रोल में एम15 की ब्लेंडिंग, एलपीजी में डाइमिथाइल ईथर की ब्लेंडिंग, 2030 तक कच्चे तेल के आयात में 10 प्रतिशत की कमी, और 2025 तक सालाना 20 मिलियन टन का घरेलू उत्पादन। यह सोच सही थी और इसके लिए बताए गए संसाधन भी वास्तविक थे: 125 बिलियन टन कोयले का प्रमाणित भंडार और सालाना 500 मिलियन टन बायोमास। लेकिन इसे लागू करने का काम लक्ष्य से बहुत पीछे रह गया है।

संसद ने पांच साल पहले ही इस मूल समस्या की ओर इशारा किया था। कनिमोझी करुणानिधि की अध्यक्षता वाली केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स पर बनी स्टैंडिंग कमिटी ने मार्च 2021 में रिपोर्ट दी कि भारत में पेट्रोकेमिकल्स की मांग और सप्लाई के बीच का अंतर 2018-19 में 1,124 हज़ार टन से बढ़कर 2025 तक 7,112 हजार टन हो जाएगा यानी इसमें 533 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जबकि स्टाइरीन और पॉलीकार्बोनेट्स के लिए देश में कोई प्रोडक्शन क्षमता ही नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, 2015-16 और 2024-25 के बीच केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्शन सिर्फ़ 2.8 प्रतिशत की कंपाउंड दर से बढ़ा है।

सरकार की प्रतिक्रिया

सरकार की प्रतिक्रिया तेज़ और सही सोच-समझकर दी गई थी। कस्टम्स एक्ट की धारा 25(1) के तहत 1 अप्रैल 2026 को जारी नोटिफिकेशन नंबर 12/2026-कस्टम्स के ज़रिए, 40 पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर उत्पादों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी शून्य कर दी गई। इनमें टैरिफ हेडिंग 2905 11 00 के तहत मेथनॉल के साथ-साथ एनहाइड्रस अमोनिया, टोल्यूइन, स्टाइरीन, फिनोल, एसिटिक एसिड और मुख्य पॉलीमर शामिल थे।

इसके पीछे पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके कारण सप्लाई-चेन में आई रुकावट को वजह बताया गया। सीबीआईसी के सदस्य संजय मंगल ने इसे जरूरी पेट्रोकेमिकल इनपुट की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी और लक्षित राहत बताया और कहा कि इससे तीन महीनों में लगभग ₹1,800 करोड़ का रेवेन्यू पर असर पड़ेगा। नोटिफिकेशन नंबर 22/2026 के जरिए इसे 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया।

मेथनॉल – एक नजर में

भारत का आयात, 2025	3.4 मिलियन टन (+13.5%)
पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी	% → 51% (अप्रैल 2025 – मई 2026)
चीन की हिस्सेदारी	% (अप्रैल 2026) → 26% (मई 2026)
चीन की सप्लाई, 2024 → 2025	ज़ीरो → 49,347 टन
सऊदी अरब की हिस्सेदारी	34% (फरवरी 2026) → 0% (मई 2026)
सीएफआर कीमत, Q1 FY27	$569/टन, 114% की बढ़ोतरी
घरेलू कीमत, मई 2026	₹73,950/टन, ₹182% की बढ़ोतरी
घरेलू क्षमता	₹0.66 मिलियन टन सालाना (2016 का सर्वे)
क्षमता का इस्तेमाल	₹30%
कस्टम्स में राहत	2 अप्रैल 2026 से 40 उत्पादों पर कोई ड्यूटी नहीं;
	₹1,800 करोड़ का रेवेन्यू पर असर

इंडस्ट्री ने बिना किसी शर्त के इसका स्वागत किया। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के डॉ. विरंची शाह ने कहा कि मुख्य सॉल्वेंट्स पर ड्यूटी हटाने से हाल ही में बढ़ी कीमतों को रोकने में मदद मिलेगी। एडवांस ऑथराइज़ेशन होल्डर्स को 31 अगस्त तक अतिरिक्त तीन महीने दिए गए।

इस रुकावट की व्यापक लागत को मापा जा सकता है। कील इंस्टीट्यूट के मार्च 2026 के पॉलिसी ब्रीफ का अनुमान है कि दुनिया में पेट्रोलियम की खपत का लगभग 21 प्रतिशत और एलएनजी का एक-चौथाई हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है, और खाड़ी देश दुनिया के हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का 73.4 प्रतिशत हिस्सा सप्लाई करते हैं।

अगर रास्ता बंद हो जाता है, तो भारत सबसे ज्यादा प्रभावित 20 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा, जिसमें लगभग 1.78 प्रतिशत का वेलफेयर लॉस (कल्याणकारी नुकसान) होगा – जबकि अमेरिका के लिए यह नुकसान 0.07 प्रतिशत होगा।

विकल्प को सही ढंग से समझना

रूट बदलने का तरीका काम कर गया। भारतीय इंडस्ट्री उस संघर्ष के दौरान भी चलती रही, जिसने एक ज़रूरी इनपुट का 90 प्रतिशत हिस्सा लाने वाली सप्लाई लाइन को बंद कर दिया था। यह एक बेहतर ढंग से काम करने वाला प्रोक्योरमेंट सिस्टम और तेज़ी से प्रतिक्रिया देने वाला टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है।

इससे जो सवाल उठता है, वह कंपोज़िशन (संरचना) का है। डाइवर्सिफिकेशन (विविधता) जिसने निर्भरता को एक स्रोत से दूसरे स्रोत पर स्थानांतरित किया है, उसने मज़बूती के बजाय केवल समय दिलाया है – और भारत साथ ही साथ रेयर अर्थ मैग्नेट में चीनी निर्भरता को कम करने के लिए ₹7,280 करोड़ खर्च कर रहा है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से तीन उपाय किए जाने चाहिए।

डेटा को अपडेट करें। क्षमता और खपत का आधिकारिक सर्वे एक दशक पुराना है। अगर केमिकल और पेट्रोकेमिकल विभाग सालाना मेथनॉल बैलेंस (जिसमें क्षमता, उत्पादन, इस्तेमाल और कहां से कितना आयात हुआ, इसकी जानकारी हो) जारी करे, तो पॉलिसी में बदलावों के हिसाब से तुरंत कदम उठाए जा सकेंगे, न कि एक साल बाद।

कोयला-से-मेथनॉल बनाने के मामले पर फिर से विचार करें। नीति आयोग का 2017 का प्रस्ताव ज्यादा राख वाले भारतीय कोयले पर आधारित था, जिसकी कीमत लगभग ₹19 प्रति लीटर थी। आयातित मेथनॉल की कीमत $569 प्रति टन होने के कारण, इस आर्थिक पहलू पर फिर से सोचने की ज़रूरत है, साथ ही बायोमास और म्युनिसिपल कचरे से मेथनॉल बनाने के तरीकों पर भी।

ड्यूटी की स्थिति साफ़ करें। 15 जुलाई 2026 के बाद छूट बढ़ाने के बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। कीमतें अभी भी पिछले साल के स्तर से काफी ऊपर हैं, इसलिए इंपोर्टर्स और फॉर्म्युलेटर्स को सबसे ज्यादा इस बात की स्पष्टता चाहिए कि क्या यह राहत जारी रहेगी।

सिर्फ एक 'सी' से कितना फर्क पड़ता है

मेथनॉल में एक कार्बन एटम (CH_3OH) होता है, जबकि इथेनॉल में दो कार्बन एटम (C_2H_5OH) होते हैं। इन दोनों गैसों में फ़र्क करने के लिए आयोडोफ़ॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है; इसमें इथेनॉल में आयोडीन और सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिलाने पर एक अलग तरह का पीला प्रेसिपिटेट (आयोडोफ़ॉर्म) बनता है, जबकि मेथनॉल कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। इसके अलावा, इथेनॉल को जलाने पर चमकीली नीली लौ निकलती है जिसके सिरे पीले होते हैं, जबकि मेथनॉल हल्की, लगभग न दिखने वाली सफ़ेद या नीली लौ के साथ जलता है।

इथेनॉल की गंध तेज़, थोड़ी मीठी और जलने जैसी अल्कोहलिक होती है और इसे ड्रिंक्स में इस्तेमाल किया जा सकता है (हालांकि ज़्यादा और शुद्ध मात्रा में यह ज़हरीला होता है)।

दूसरी ओर, मेथनॉल की गंध तीखी और अलग तरह की केमिकल वाली होती है और यह बहुत ज़हरीला होता है; इसकी थोड़ी सी मात्रा भी निगलने से हमेशा के लिए अंधापन या मौत हो सकती है।

चीन दुनिया का आधे से ज़्यादा मेथनॉल बनाता है, जिसमें ज़्यादातर कोयले का इस्तेमाल रॉ मटीरियल के तौर पर किया जाता है। दुनिया के दूसरे बड़े उत्पादकों और एक्सपोर्टर्स में सऊदी अरब, ईरान, त्रिनिदाद और टोबैगो, अमेरिका और रूस शामिल हैं, जो मुख्य रूप से नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके मेथनॉल बनाते हैं।

चीन कोयले से मेथनॉल और मेथनॉल से ओलेफ़िन (एमटीओ) बनाने की खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ईरान और सऊदी अरब सस्ती और भरपूर नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो पश्चिमी गोलार्ध के बड़े उत्पादक और दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर हैं, जिनके पास नेचुरल गैस पर आधारित बड़े प्लांट हैं। अमेरिका और रूस में घरेलू उत्पादन और एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है, जो शेल गैस और नेचुरल गैस के बड़े भंडार की वजह से है।

सामान्य स्थितियों में मेथनॉल एक लिक्विड होता है, इसलिए इसे गैसोलीन और डीज़ल की तरह आसानी से स्टोर, ट्रांसपोर्ट और डिस्पेंस किया जा सकता है। इसे डिहाइड्रेशन के ज़रिए आसानी से डाइमिथाइल ईथर में बदला जा सकता है, जो डीज़ल का एक विकल्प है और जिसका सिटेन नंबर 55 है।

यह पानी में घुलनशील भी है। अगर गलती से मेथनॉल पर्यावरण में फैल जाए, तो गैसोलीन या कच्चे तेल के फैलने की तुलना में इससे बहुत कम नुकसान होगा। इन ईन्धनों के उलट, मेथनॉल बायोडिग्रेडेबल है और पानी में पूरी तरह घुल जाता है। यह तेजी से इतना पतला हो जाता है कि माइक्रोऑर्गेनिज़्म इसका बायोडिग्रेडेशन शुरू कर सकें।

इस गुण का इस्तेमाल पहले से ही वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट में किया जा रहा है, जहाँ मेथनॉल का इस्तेमाल डीनाइट्रिफ़िकेशन और बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रिएंट के तौर पर होता है।

सरकार व सार्वजनिक संस्थान

न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव पटना व जस्टिस रविंद्र होंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में गठित सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने चार उच्च न्यायालयों के लिए मुख्य न्यायाधीशों की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने पटना, कलकत्ता, बॉम्बे और पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित किए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया है। न्यायमूर्ति राव को अप्रैल 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और मार्च 2015 में वे स्थायी न्यायाधीश बने। उनका तबादला 2024 में कर्नाटक उच्च न्यायालय में हुआ और जुलाई 2025 में उन्हें वापस दिल्ली उच्च न्यायालय में लाया गया।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

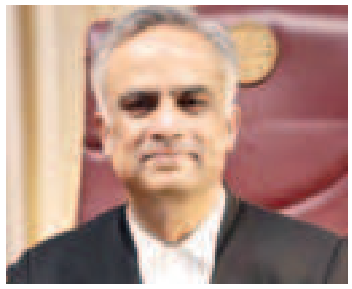

न्यायमूर्ति रविंद्र वी. घुगे को कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नामित किया गया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के बाद न्यायमूर्ति घुगे वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

कॉलेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने का प्रस्ताव दिया है। न्यायमूर्ति त्रिपाठी को सितंबर 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और अप्रैल 2015 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था।

न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा, जिनका मूल न्यायालय इलाहाबाद है और जो वर्तमान में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पीठ में कार्यरत हैं, को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित किया गया है। उन्होंने फरवरी 2014 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और फरवरी 2016 में स्थायी न्यायाधीश बन गए। न्यायमूर्ति मिश्रा का तबादला जुलाई 2025 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में हुआ।

ईडी निदेशक राहुल नवीन को एक वर्ष का सेवा विस्तार

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। राहुल नवीन अगले साल 13 अगस्त तक ईडी निदेशक के पद पर बने रहेंगे।

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गत दिवस आदेश जारी किया। अहम बात यह है कि इस विस्तार में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख (31 जुलाई, 2027) के बाद भी सेवा में बने रहना शामिल है। आदेश में साफ किया गया है कि उनका कार्यकाल 13 अगस्त 2027 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो जारी रहेगा। राहुल नवीन 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं।

दीप्ति गौर मुखर्जी बनीं हायर एजुकेशन विभाग की नई सेक्रेटरी

केंद्र सरकार ने विगत दिवस शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल करते हुए 1993 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी को नया हायर एजुकेशन सेक्रेटरी (उच्च शिक्षा सचिव) नियुक्त किया है। वह विनीत जोशी का स्थान लेंगी, जिन्हें हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय में सचिव बनाया गया था।

दीप्ति गौर मुखर्जी, 1993 बैच की मप्र कैडर की आईएएस हैं। वर्तमान में वह कॉरपोरेट मामलों की सचिव के रूप में कार्यरत हैं। दीप्ति गौर मुखर्जी की उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है, जब देश में नीट परीक्षा पेपर लीक का विवाद गरमाया हुआ है।

भारत ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी और डब्ल्यूटीओ में तैनात किए नए अफसर

सत्यजीत मोहंती

राहुल जैन

बलदेव पुरुषार्थ

हेमंग जानी

कपिल पाटीदार

आदित्य राजेंद्र भोजगढ़िया

जिविषा जोशी गंगोपाध्याय

बृज मोहन मिश्रा

बालमुरुगन डी

गोपालकृष्णन गणेशन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों की विदेशी नियुक्तियों को मंजूरी दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और विभिन्न देशों में भारतीय दूतावासों में नई तैनातियां की गई हैं। इसी आदेश में वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन डीसी में तैनात हेमंग जानी का कार्यकाल दो वर्ष बढ़ाकर 16 जुलाई 2029 तक कर दिया गया है।

आदेश के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी, मनीला, मॉन्ट्रियल, जिनेवा, टोक्यो, रोम और काठमांडू में नई नियुक्तियां की गई हैं। इनमें डिफेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

डिफेंस मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी **सत्यजीत मोहंती** को तीन वर्ष के लिए मॉन्ट्रियल स्थित इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी और 2005 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी राहुल जैन को वॉशिंगटन डीसी स्थित इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर बनाया गया है। उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी और 2002 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी बलदेव पुरुषार्थ को फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है।

इसी आदेश में हेमंग जानी का वॉशिंगटन डीसी स्थित वर्ल्ड बैंक में कार्यकाल दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वह वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। पहले उनका कार्यकाल 16 जुलाई 2027 तक था, जिसे अब बढ़ाकर 16 जुलाई 2029 कर दिया गया है।

वॉशिंगटन और जिनेवा में भी नई पोस्टिंग

डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के डायरेक्टर कपिल पाटीदार को आईएमएफ, वॉशिंगटन डीसी में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एडवाइजर नियुक्त किया गया है। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जॉइंट डायरेक्टर आदित्य राजेंद्र भोजगढ़िया को जिनेवा स्थित वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की डिप्टी सेक्रेटरी जिविषा जोशी गंगोपाध्याय को भी जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन (डब्ल्यूटीओ) में फर्स्ट सेक्रेटरी (लीगल) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

काठमांडू, टोक्यो और रोम में भी तैनाती

मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्टर सुभाष कुमार को काठमांडू स्थित सार्क सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी **बृज मोहन मिश्रा** को जापान की राजधानी टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिनिस्टर (इकोनॉमिक एंड कमर्शियल) बनाया गया है। कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी **बालमुरुगन डी** को इटली की राजधानी रोम स्थित भारतीय दूतावास में मिनिस्टर (एग्रीकल्चर) नियुक्त किया गया है।

गोपालकृष्णन गणेशन को नई जिम्मेदारी

मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डायरेक्टर गोपालकृष्णन गणेशन को भी वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के इकोनॉमिक सेल में काउंसलर (इकोनॉमिक) नियुक्त किया गया है।

इराक में अजय कुमार व सौमेंदु बागची स्विट्जरलैंड में राजदूत नियुक्त

मुंबई। विदेश मंत्रालय में बड़े स्तर पर राजनयिक फेरबदल करते हुए केंद्र सरकार ने इराक और स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूतों की नियुक्ति की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अजय ए कुमार को इराक गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है।

अजय कुमार अभी विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनका कूटनीतिक करियर करीब 24 साल का है और वे पश्चिम एशिया के मामलों के जानकार माने जाते हैं। इराक में भारत के बढ़ते आर्थिक और ऊर्जा संबंधों के बीच उनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इसके अलावा, 1993 बैच के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी सौमेंदु बागची को अब स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। फिलहाल वह बगदाद में भारत के राजदूत हैं। बागची इराक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके कार्यकाल में भारत-इराक के बीच व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति मिली थी। अब उन्हें बर्न भेजा जा रहा है, जहां भारत के यूरोप के साथ बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी।

भारतीय मूल के अनिल मेनन ने रचा इतिहास, आईएसएस के बाहर किया पहला स्पेस वॉक

अंतरिक्ष से भेजी प्रशांत महासागर की तस्वीर, दिखा चक्रवात का अद्भुत नजारा

ललित दुबे

वाशिंगटन। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों ने एक बार फिर नया मुकाम हासिल किया है। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से बाहर निकलकर अपने जीवन का पहला ऐतिहासिक स्पेसवाक किया। यह उनके करियर के लिए एक बड़े मील के पत्थर के तौर पर थी।

इस 6.5 घंटे लंबे कठिन मिशन (ईवीए) में अनिल मेनन के साथ नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर भी शामिल थीं, जो अपने करियर का छठा स्पेसवाक कर रही थीं। इन दोनों ने मिलकर अंतरिक्ष स्टेशन की बिजली प्रणाली को अपग्रेड करने का महत्वपूर्ण काम किया।

समझिए इस मिशन से जुड़ी मुख्य बातें

मेनन और मीर का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन के '3बी पावर चैनल' पर नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना था। यह काम भविष्य में लगाए जाने वाले नए सोलर पैनल की तैयारी के लिए किया गया।

क्यों जरूरी है यह अपग्रेड?

इस बात को ऐसे समझिए कि अंतरिक्ष स्टेशन पर लगे पुराने सोलर पैनल समय के साथ कमजोर हो गए हैं। ये नए और आधुनिक सोलर पैनल स्टेशन की बिजली उत्पादन क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे, जिससे वहां होने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों और जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए लगातार बिजली मिलती रहेगी।अंतरिक्ष से अनिल मेनन ने प्रशांत महासागर की तस्वीर भेजी। चक्रवात के अद्भुत नजारे की भी तस्वीर भेजी गई। अनिल मेनन पहली बार अंतरिक्ष गए हैं। वह आठ महीने तक आईएसएस पर रिसर्च करेंगे।

अंतरिक्ष में स्पेसवाक की चुनौतियां

अंतरिक्ष के निर्वात में काम करना बहुत खतरनाक और मुश्किल होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अत्यधिक तापमान और लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए हर काम पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ करना होता है।

यह स्पेसवाक तीन अंतरिक्ष अभियानों में से पहला था। इसके बाद 13 अगस्त को संचार एंटीना को बदला गया और 25 अगस्त को डेटा रिले सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए दो और स्पेसवाक योजनाबद्ध हैं।

चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने की तैयारी

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच पिछले दिनों अहम बैठक हुई । इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने अंतरिक्ष विज्ञान और इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से जुड़े काम पर चर्चा की।

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है। यह प्रोग्राम आर्टिमिस मिशन का हिस्सा है। इसका मकसद चंद्रमा पर इंसानों को लंबे समय तक भेजने और वहां काम करने की तैयारी करना है। इससे भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में सहयोग और बढ़ सकता है।

यह बैठक बेंगलुरु में इसरो के मुख्यालय में हुई थी। इसमें दोनों देशों के अधिकारियों ने अंतरिक्ष विज्ञान और इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने से जुड़े काम पर चर्चा की। नासा चांद पर ऐसा बेस बनाने की तैयारी कर रहा है, जहां आगे चलकर इंसान लंबे समय तक रह और काम कर सके। इसके लिए पहले रोवर, रोबोट और दूसरे उपकरण चंद्रमा पर भेजे जाएंगे।

रोनाल्डो ने जॉर्जिना रोड्रिगेज से की शादी

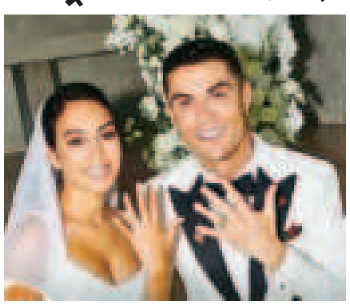

नई दिल्ली। विश्व के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ 11 अगस्त को शादी कर ली। रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर अपनी और जॉर्जिना की तस्वीर शेयर कर इस खबर पर मुहर लगाई है।

अग्निवीरों को फायर सर्विस, जेल विभाग भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने पूर्व अग्निवीरों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार के 2 प्रमुख विभागों में सीधी भर्ती के दौरान 20% आरक्षण देने का फैसला मंजूर कर लिया है। यह निर्णय भारत सरकार की तरफ से पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए बनाई गई नीति के तहत लिया गया है।

दिल्ली गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस फैसले से न केवल युवाओं को सेना से आने के बाद दिल्ली में स्थायी सरकारी नौकरी मिलेगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में उम्र सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) में भी विशेष छूट मिलेगी। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत उपराज्यपाल ने भर्ती नियमों में यह प्रावधान दिया है।

संबंधित विभाग तय करेंगे छूट

पूर्व अग्निवीरों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में कितनी छूट दी जाए, इसका फैसला संबंधित विभाग खुद तय करेंगे। अगर किसी भर्ती में योग्य अग्निवीर पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं तो भारत सरकार की हॉरिजॉन्टल आरक्षण गाइडलाइंस के अनुसार उन सीटों को भरा जाएगा।

सीएपीएफ में खास रियायत

पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ्स) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जीडी) और राइफलमैन (जीडी) के पदों पर 50% आरक्षण देने की घोषणा की थी।

इसके साथ ही कई राज्य सरकारों जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने अपनी पुलिस व अन्य सुरक्षा सेवाओं में भी अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और लिखित परीक्षा से भी छूट दी जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों के भविष्य और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने एक्स-अग्निवीर विंग की भी स्थापना की है। यह विंग विभिन्न सुरक्षा बलों में उनकी नियुक्ति और अन्य अवसरों के लिए को ऑर्डिनेशन का काम करेगा।

36 साल बाद खुली कश्मीरी पंडित और उनके बेटे की 'मर्डर मिस्ट्री' की फाइल

नई दिल्ली। कश्मीर घाटी के इतिहास में 1990 का आतंक का दौर आज भी खौफ पैदा करता है। उस दौरान कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया था। उसी दौर की एक बर्बर दास्तां स्वतंत्रता सेनानी और कवि सर्वानंद कौल 'प्रेमी' और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की भी है। दोनों को घर से अगवा करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शव पेड़ से लटका दिए गए थे।

अब 36 साल बाद जम्मू-कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एसआईए) ने इस दोहरे हत्याकांड की फाइल फिर से खोल दी है। विगत दिवस एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें राजौरी में छह, जम्मू में दो और कश्मीर में दो स्थान शामिल है। सर्वानंद के दूसरे बेटे राजेंद्र कौल ने बताया, 'उस रात तीन आतंकी घर में घुसे थे। आतंकियों ने मुझे, मेरी मां, छोटे भाई और दो बहनों को एक कमरे में बंद कर दिया। वे पिता और भाई को अगवा कर ले गए और हत्या कर दी। अब 36 साल बाद इंसाफ की उम्मीद जगी है।' उन्होंने अपील की कि ऐसे सभी पुराने मामलों की फिर से जांच हो और दोषियों को सजा मिले।

नैशविल फेम में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की गीतकार बनीं टेलर स्विफ्ट

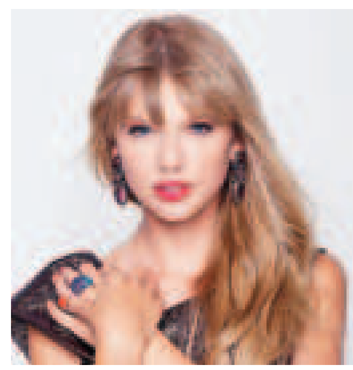

नई दिल्ली। मशहूर पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट नैशविल सॉन्गराइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की (36 वर्ष) गीतकार बन गई हैं। अपने डेब्यू एल्बम की 20वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें 'कंटेंपरेरी सॉन्गराइटर' कैटेगरी में चुना गया है। इससे पहले वे न्यूयॉर्क के 'सॉन्गराइटर्स हॉल ऑफ फेम' में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला सिंगर बनी थीं।

इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद टेलर ने आभार जताते हुए कहा, 'बचपन से ही नैशविल मेरे लिए सपनों का नैशविल सॉन्गराइटर्स हॉल ऑफ फेम शहर रहा है। यह एक ऐसी जगह है जो कड़ी मेहनत, लगन और कल्पनाशीलता को सम्मान देती है। जिस शहर से मैं इतना प्यार करती हूं, उससे यह सम्मान पाना मेरे लिए बेहद खूबसूरत अहसास है।' 1970 में स्थापित इस हॉल ऑफ फेम में इस साल टेलर के अलावा सॉन्गराइटर लायल लोवेट, कंटम्परेरी सॉन्गराइटर शॉन कैंप और ली थॉमस मिलर व ब्रूस चैनल को भी शामिल किया जा रहा है। अब तक इस हॉल ऑफ फेम में लगभग 254 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है।

दुनिया के तीसरे सबसे छोटे देश नौरू ने अपना नाम बदला

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप देश नौरू ने अपना नाम बदलकर नाओएरो गणराज्य कर लिया है। वहां के राष्ट्रपति ने कहा, यह नाम राष्ट्रीय भाषा में वर्तनी और उच्चारण के अनुरूप है

देश का अंतर्राष्ट्रीय कोड एनआरयू से बदलकर एनआरओ हो जाएगा और यहां के लोगों को नौरुआन के बजाय देई-नाओएरो के नाम से जाना जाएगा। विदेशों में आमतौर पर नाउ-रू के उच्चारण से जाना जाने वाला यह नया नाम नाउ-एरो बोला जाता है।

सरकार के फेसबुक अकाउंट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कदम से सुदूर दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र को उसका पारंपरिक नाम वापस मिल जाएगा। सरकार के एक पूर्व बयान के अनुसार, देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौरू के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसका स्थानीय नाम विदेशियों के लिए उच्चारण करना कठिन था और यह पसंद का मामला नहीं बल्कि सुविधा का मामला था।

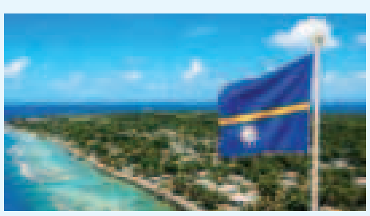

जनवरी में संसद में प्रस्ताव रखते हुए राष्ट्रपति डेविड अदेआंग ने कहा था, यह प्रस्तावित बदलाव हमारे राष्ट्र की विरासत, हमारी भाषा और हमारी पहचान का अधिक ईमानदारी से सम्मान करने का प्रयास करता है। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को सांसदों ने मतदान के दो चरणों में मंजूरी दे दी है, हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ कि दस्तावेज को औपचारिक रूप से संशोधित किया गया है या नहीं।

12,000 निवासियों के साथ, नौरू जनसंख्या के हिसाब से तुवालू और वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। इस छोटे से प्रवाल-चूना पत्थर के द्वीप पर पहले जर्मनी का उपनिवेश था और बाद में ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रशासित किया गया। 1968 में यह एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया।

इस द्वीप को उथल-पुथल भरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 1970 के दशक में फॉस्फेट खनन ने द्वीप पर अपार धन सृजित किया था, लेकिन उद्योग के पतन के कारण 1990 के दशक में नौरू आर्थिक बर्बादी के कगार पर आ गया था। अब, जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते समुद्र के स्तर से यह सबसे अधिक जोखिम वाले देशों में से एक है, जिसके चलते सरकार ने एक सशुल्क नागरिकता कार्यक्रम के माध्यम से विदेशी निवेश की तलाश शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य बढ़ते समुद्र से दूर लोगों और बुनियादी ढांचे को स्थानांतरित करने के लिए धन उपलब्ध कराना है।

मस्क का भारत के दूरदराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का प्लान

ब्लिट्ज विशेष

नई दिल्ली। विश्व के सबसे धनवान उद्योगपति एलन मस्क ने कहा है कि स्टारलिंक से भारत के उन दूरदराज और ग्रामीण इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, जहां अब भी कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। मस्क ने शुक्रवार (21 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर यह बात कही।

एक दिन पहले स्टारलिंक ने भारत में लाइसेंस के लिए री-अप्लाई भी किया है। मस्क ने X पर 'डोजडिजायनर' के एक पोस्ट

को री-शेयर करते हुए लिखा, 'स्टारलिंक भारत में सबसे कम सुविधा पाने वाले लोगों, खासकर ग्रामीण इलाकों की मदद करेगा।'

डोजडिजायनर के पोस्ट के मुताबिक, मई 2026 तक भारत के 11,000 से ज्यादा लिस्टेड गांवों में 4जी नेटवर्क की पहुंच नहीं थी। आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 तक भारत में कुल 109.3 करोड़ इंटरनेट सब्सक्रिप्शन थे।

मस्क के मुताबिक, स्टारलिंक तकनीक दूरदराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों, द्वीपों, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी वाले और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कनेक्टिविटी दे सकती है। डायरेक्ट-टू-डिवाइस कनेक्टिविटी के जरिए मोबाइल फोन्स को बिना टावर कवरेज के भी नेटवर्क से जोड़े रख सकती है।

इसी वजह से मांग की गई है कि भारत सरकार को बाकी बची मंजूरियों को पूरा करके स्पेक्ट्रम एलोकेशन करना चाहिए और जल्द से जल्द स्टारलिंक के कॉमर्शियल लॉन्च का रास्ता साफ करना चाहिए।

नेपाल में भारत की बेटियों को नागरिकता मिलना हुआ आसान

किशनगंज। भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने 'रोटी-बेटी' के पारिवारिक व सामाजिक रिश्ते को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में दोनों देशों के प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। सीमा पार विवाह के बाद महिलाओं को नागरिकता और जरूरी पहचान दस्तावेजों को लेकर होने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए भारत-नेपाल समन्वय समिति की बैठक में विस्तृत सहमति बनी है।

बैठक में तय किया गया कि दोनों देशों में ब्याही गई बहुओं को आवश्यक वैध दस्तावेजों व साक्ष्यों के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

पूर्व पीएम देउबा बोले, सनातन धर्म को ही नेपाल की नई राष्ट्रीय पहचान बनाएं

ब्लिट्ज ब्यूरो

काठमांडो। नेपाल के पूर्व पीएम व नेपाली कांग्रेस (नेकां) के नेता शेर बहादुर देउबा ने देश में सनातन धर्म को नई राष्ट्रीय पहचान देने का फैसला किया है। इससे नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा बलवती हुई है। देउबा नेतृत्व में नेकां गुट के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में इसे आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

देउबा के इस बयान से सियासी माहौल गरमा गया है। हालांकि, प्रस्ताव में हिंदू, बौद्ध, किरात व प्रकृति-आधारित धार्मिक परंपराओं के संरक्षण समेत सभीधर्म समुदायों की आजादी, सहिष्णुता व सामाजिक सद्भाव पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन के समापन समारोह में देउबा ने 'मैं हिंदू हूं' के नारे के साथ अपनी राजनीति की दिशा स्पष्ट कर दी। उन्होंने कहा, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं लेकिन मुझे यह कहने का अधिकार हो कि मैं हिंदू हूं।

इस बयान को सनातन पहचान पर चल रही बहस के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नेपाली कांग्रेस के दूसरे गुट को पारित प्रस्तावों पर आपत्ति है। प्रवक्ता विनोद

चालिसे ने कहा, सम्मेलन में हुए काम और बयानों पर पार्टी की नजर है।

ये हैं पारित प्रस्ताव

- 15वें महाधिवेशन का आयोजन देउबा के नेतृत्व में हो
- राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी ताकतों से संवाद किया जाए
- जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में आवश्यक संशोधन
- सनातन धर्म के साथ हिंदू, बौद्ध और किरात परंपराओं का संरक्षण करने पर जोर
- प्रस्तावों को अंतिम रूप देगी एनपी साउद समिति।

भारत से तेल मंगा रहा रूस पहुंच चुकी है पहली खेप

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली: भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से मंगवाता रहा है लेकिन पहली बार रूस को भारत से पेट्रोल मंगाना पड़ रहा है। असल में यूक्रेन के हमलों के कारण उसकी रिफाइनरीज का कामकाज प्रभावित हुआ है। इस कारण देश में स्थानीय स्तर पर पेट्रोल की भारी कमी हो गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पहली भारत से पेट्रोल का आयात किया है। भारत अपनी जरूरत का 88 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है लेकिन वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस के भारत से पेट्रोल की पहली खेप 5 अगस्त को मिली थी। अभी भारत से और भी खेप आ सकती हैं। भारतीय की घरेलू प्रोसेसर नायरा एनर्जी लिमिटेड ने रूस को पेट्रोल की सप्लाई की है। इस कंपनी में रूस की टॉप ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी रोसनेफ्ट का निवेश है। इस ईंधन को मिस्र के पास ट्रांसफर के जरिए रूसी लिंक वाले टैंकरों की एक चेन के जरिए भेजा जा रहा है।

क्यों हुई कमी?

रूसी रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले और पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उथलपुथल मची हुई है। इससे तेल की आपूर्ति कम हो गई है और रूस को घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल और डीजल का निर्यात रोकना पड़ा है। उल्टा उसे भारत जैसे देशों से पेट्रोल आयात करना पड़ा है। यूक्रेन के हमलों के कारण रूस की प्रोसेसिंग कैपेसिटी में काफी गिरावट आई है।

कैसे बह रही उल्टी गंगा?

ब्लूमबर्ग के शिप-ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक रूस के झंडे वाले प्रोडक्ट टैंकर साइक्लोन ने 18 जून को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वाडिनार रिफाइनरी से 42,000 टन पेट्रोल लोड किया। 6 जुलाई को इसे मिस्र के भूमध्यसागरीय तट पर स्थित डामिएटा पोर्ट पर ओमान के झंडे वाले गार्नेट जहाज में ट्रांसफर किया गया। वह जहाज अगस्त की शुरुआत में रूस पहुंचा।

और बढ़ रही है खेप

प्रोडक्ट टैंकर वर्ग ने भी 6 जुलाई को वाडिनार में लगभग 40,000 टन फ्यूल लोड किया और जुलाई के आखिर में डामिएटा में शिप-टू-शिप ट्रांसफर किया। अभी तक किसी ऐसे जहाज की पुष्टि नहीं हुई है जिसने यह खेप ली हो।

'ऑपरेशन सिंदूर' की कामयाबी पर अमेरिका से मुहर

खोखले साबित हुए पाकिस्तान के न्यूक्लियर डेटरेंस के दावे

ब्लिट्ज ब्यूरो

इस्लामाबाद। अमेरिकी संस्था 'बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट' ने अपने आकलन में पाया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार भारत के हमलों से उसे बचाने में नाकाम रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि मई 2025 में भारत के साथ 4 दिन के सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान के अनुभव ने परमाणु हथियारों से मिलने वाली सुरक्षा (न्यूक्लियर डेटरेंस) की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इसके चलते देश अब पारंपरिक सैन्य शक्ति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।

पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर बड़े-बड़े दावे करते रहे हैं। परमाणु हथियारों से लैस इन दोनों पड़ोसियों के बीच यह सैन्य टकराव 7 मई को शुरू हुआ, जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के तौर पर 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया। रिपोर्ट से पता चला है कि इस टकराव के बाद पाकिस्तान के रणनीतिक नेतृत्व को इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि परमाणु हथियारों की भी अपनी सीमाएं होती हैं।

परमाणु बम नहीं रोक पाए लड़ाई

अमेरिकी संस्था की ये रिपोर्ट कहती है कि परमाणु हथियार संकट को पैदा होने से नहीं रोक पाए। परमाणु हथियार न भारत को पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हमले करने से रोक पाए और न ही लड़ाई शुरू होने के बाद इस्लामाबाद को युद्ध से बाहर निकलने का कोई निर्णायक रास्ता दे पाए।

अमेरिका स्थित इस संस्था का आकलन ऐसे समय आया है, जब सुरक्षा गारंटी और बदलती वैश्विक रणनीतिक स्थितियों की चिंताओं के बीच कई देश परमाणु हथियारों में फिर से दिलचस्पी दिखा रहे हैं लेकिन परमाणु हथियार अब कम महत्वपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान से भी सुरक्षा नीति में परमाणु हथियारों की बदलती भूमिका के संकेत मिले हैं।

परमाणु हथियारों ने न तो संकट को शुरू होने से रोका और न ही संघर्ष बढ़ने पर

नीति-निर्माताओं को कोई रास्ता सुझाया। इसके बजाय परमाणु हथियारों की मौजूदगी ने गलत आकलन और अनजाने में संघर्ष बढ़ने की संभावना के कारण पाकिस्तान के जवाबी विकल्पों को सीमित कर दिया।

पाकिस्तान की विफलता

रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु हथियारों की तुलना में पारंपरिक सैन्य सफलता से सेना और उसके संस्थानों के राजनीतिक हितों को बेहतर ढंग से साधा जा सकता है। इसमें तर्क दिया गया कि परमाणु हथियारों ने पाकिस्तान की सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुख्य संरक्षक के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की है। यह जनता का समर्थन हासिल करने की क्षमता सीमित है।

रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 के संघर्ष ने परमाणु डेटरेंस के दावों और सैन्य संकट के दौरान परमाणु हथियार असल में क्या कर सकते हैं, इसके बीच के अंतर को उजागर किया। परमाणु डेटरेंस मई 2025 के संकट को रोक नहीं पाया। संघर्ष बढ़ने के डर ने भारत को पाकिस्तान के मुख्य इलाकों में गहराई तक हमला करने से नहीं रोका।

परमाणु हथियार चाहने वाले देशों के लिए चेतावनी

रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के रणनीतिक प्रतिष्ठान के लिए परमाणु डेटरेंस की सीमाओं को छिपाना मुश्किल हो रहा है। भारत से टकराव के दौरान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का जखीरा ना केवल समाधान देने में विफल रहा बल्कि इसने अतिरिक्त जोखिम भी पैदा किए। भारत के मिसाइल हमलों का जवाब देने में पाकिस्तान के सामने कई चुनौती आई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान का अनुभव परमाणु प्रतिरोध (न्यूक्लियर डेटरेंस) के सिद्धांत को गलत साबित नहीं करता लेकिन यह दिखाता है कि सुरक्षा चुनौतियों के लिए परमाणु हथियारों को एकमात्र समाधान मानना खतरनाक हो सकता है। इससे अगर कुछ पता चलता है तो यह कि परमाणु हथियारों की उपयोगिता उनके समर्थकों के दावों की तुलना में कहीं कम है।

रिपोर्ट के अनुसार, परमाणु हथियार हासिल करने पर विचार कर रहे देशों के लिए पाकिस्तान का अनुभव एक अलग सवाल खड़ा करता है। इन देशों को सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि परमाणु हथियार सुरक्षा के लिहाज से क्या दे सकते हैं। बल्कि उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि परमाणु बम किन सैन्य सीमाओं और जोखिमों को जन्म देता है।

'दिमागी नक्सल' पर सियासत: विपक्ष की छटपटाहट या 'चोर की दाढ़ी में तिनका'

बिना नाम लिए प्रधानमंत्री के वार से विपक्ष क्यों हुआ असहज?

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वैचारिक मुद्दा उठाया जिसने विपक्षी खेमे में भूचाल सा ला दिया।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने हथियारबंद नक्सलवाद और माओवादी हिंसा को लगभग समाप्त कर दिया है लेकिन अब 'दिमागी नक्सल' (इंटेलेक्चुअल या वैचारिक नक्सल) देश में नई अराजकता और हिंसा के रास्ते तलाशने में जुटे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि ऐसे वैचारिक व दिमागी नक्सलियों की पहचान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा और राष्ट्र निर्माण से अलग (आइसोलेट) किया जाना चाहिए।

पीएम मोदी ने नहीं लिया किसी का नाम

इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री ने किसी भी राजनीतिक दल, नेता या व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया था। इसके बावजूद, इस टिप्पणी के आते ही विपक्षी दलों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कांग्रेस, वाम दलों और अन्य विपक्षी नेताओं ने न केवल इस बयान को अपने ऊपर ले लिया बल्कि सोशल मीडिया पर खुलकर 'दिमागी नक्सली' होने के तमगे भी बांटने शुरू कर दिए। सवाल यह उठता है कि जब प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया था तो विपक्ष को इतनी 'मिर्च' क्यों लगी और वे इतनी जल्दी रक्षात्मक या आक्रामक मुद्रा में क्यों आ गए?

असहमति बनाम राष्ट्रविरोधी वैचारिकी

प्रधानमंत्री मोदी के बयान का मूल आशय लोकतांत्रिक असहमति या राजनीतिक आलोचना को दबाना नहीं था। लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार की नीतियों की आलोचना करना और सवाल पूछना है जिसे हर स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। सरकार और भाजपा का पक्ष स्पष्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बयान जारी कर साफ किया कि 'दिमागी नक्सली' वे राजनेता नहीं हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं, बल्कि वे हैं जो गुप्त रूप से या वैचारिक तौर पर माओवादी हिंसा का समर्थन करते हैं और राष्ट्रीय अखंडता को चुनौती देने वाले तत्वों को बौद्धिक खुराक देते हैं।

विपक्ष को करना होगा आत्ममंथन

जब प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए इस छिपी हुई वैचारिकी पर प्रहार किया तो यह प्रहार सीधे तौर पर उन तत्वों पर लगा जो विकास की मुख्यधारा में बाधा बनते रहे हैं। यदि कोई राजनीतिक दल या नेता खुद को असहज महसूस करता है या इस वक्तव्य को अपनी आलोचना मान बैठता है तो यह आत्ममंथन का विषय है कि क्या उनकी नीतियां या बयान वास्तव में देश विरोधी या अराजक तत्वों के साथ वैचारिक संरेखण (अलाइनमेंट) रखती हैं?

विपक्ष में 'दिमागी नक्सली' घोषित करने की होड़ सी लगी

लोक मनोविज्ञान में एक पुरानी कहावत है– 'चोर की दाढ़ी में तिनका'। प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम और तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेताओं ने जिस तरह से

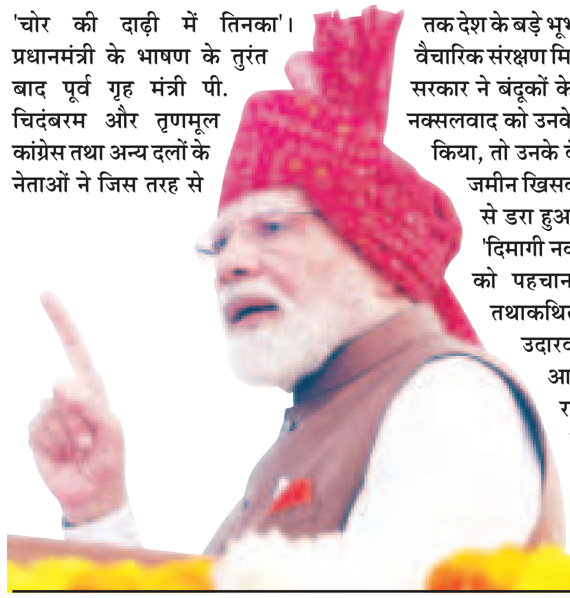

प्रतिक्रिया दी और खुद को 'दिमागी नक्सली' घोषित करने की होड़ सी लगा दी, वह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का यह कहना कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया।

विपक्ष की इस बौखलाहट के पीछे मुख्य कारण उनकी राजनीतिक हताशा है। दशकों तक देश के बड़े भूभाग पर खूनी संघर्ष को वैचारिक संरक्षण मिलता रहा है। जब मोदी सरकार ने बंदूकों के जोर पर चलने वाले नक्सलवाद को उनके गढ़ में जाकर परास्त किया, तो उनके वैचारिक मददगारों की जमीन खिसक गई। विपक्ष इस बात से डरा हुआ है कि यदि जनता ने 'दिमागी नक्सलवाद' के इस चेहरे को पहचान लिया, तो उनकी तथाकथित प्रगतिशील और उदारवादी राजनीति की आड़ में चलने वाला राष्ट्रविरोधी एजेंडा बेनकाब हो जाएगा।

'शब्दावली' बदलने की राजनीति और विक्टिम कार्ड

विपक्ष की यह पुरानी आदत रही है कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा या वैचारिक शुद्धता का कोई सवाल उठता है, वे तुरंत 'विक्टिम कार्ड' (पीड़ित होने का नाटक) खेलने लगते हैं। पहले 'अर्बन नक्सल', फिर 'आंदोलनजीवी' और अब 'दिमागी नक्सल' जैसे शब्दों पर विपक्ष ने यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की कि सरकार हर उस व्यक्ति को दबाना चाहती है जो सवाल पूछता है।

लेकिन यह तर्क अपने आप में कमजोर है। सवाल पूछना और भारतीय संविधान के दायरे में रहकर सरकार बदलना लोकतंत्र का अधिकार है लेकिन भारतीय संविधान को ही खारिज करने वालों, देश के टुकड़े करने का सपना देखने वालों और देश के विकास को विदेशी इशारों पर रोकने वालों की वकालत करना बौद्धिक बेईमानी है। विपक्ष इस वैचारिक अंतर को धुंधला करना चाहता है ताकि वे जनता की नजरों में वैध आलोचना और अवैध अराजकता को एक ही खांचे में रख सके।

यह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'दिमागी नक्सली' वाला बयान किसी राजनीतिक दल के खिलाफ व्यक्तिगत हमला नहीं था बल्कि यह एक सचेत राष्ट्र की ओर से वैचारिक प्रदूषण के खिलाफ चेतावनी थी। विपक्ष का इस पर बिलबिलाना और असहज होना इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं उनके अपने दामन पर उन ताकतों के साथ वैचारिक जुड़ाव के दाग हैं जो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। नाम न लिए जाने के बावजूद यदि जूता दूसरों के पैरों में फिट बैठ रहा है तो दर्द प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि उन लोगों का है जो खुद को उस श्रेणी में पाते हैं। जनता अब समझदार है और वह जानती है कि देशहित की बात करने वाले और देश तोड़ने के रास्ते तलाशने वाले 'दिमागी नक्सलियों' में असल फर्क क्या है।

'वंदे मातरम्' पर विपक्ष के बिगड़े बोल

बड़ा सवाल– संविधान ऊपर या कांग्रेस पार्टी?

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के केवल शुरुआती दो छंद गाने के अपने ऐतिहासिक (1937 के) रुख पर कायम रहने के फैसले ने देश में एक नया राजनीतिक और वैचारिक तूफान खड़ा कर दिया है। सत्तापक्ष इसे संसद के नए दिशा-निर्देशों और देश की भावनाओं की अवहेलना व तुष्टिकरण बता रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी इसे अपने पुराने व स्वतंत्रता सेनानियों के समय से चले आ रहे निर्णय के अनुकूल मानती है। क्या यह फैसला संविधान विरोधी है और क्या कोई दल संसद से ऊपर है, यह आज एक गंभीर विमर्श का विषय बन गया है।

'वंदे मातरम्' और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' भारतीय स्वाधीनता संग्राम का सबसे बड़ा प्रेरणास्रोत रहा है। वर्ष 1937 में जब कांग्रेस के समक्ष इसकी सांप्रदायिक और राजनीतिक संवेदनशीलता का प्रश्न आया, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर इसके केवल पहले दो छंदों को ही राष्ट्रीय सम्मेलनों में गाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। कांग्रेस का तर्क है कि शुरुआती दो छंदों में देश-प्रेम की वह भावना निहित है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, और पार्टी पिछले 80 वर्षों से इसी परंपरा का निर्वाह करती आ रही है।

क्या यह फैसला 'संविधान विरोधी' है?

भारतीय संविधान में 'जन गण मन' को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है, जबकि 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत के रूप में उसके बराबर का ऐतिहासिक सम्मान दिया गया है। हालांकि, संविधान का अनुच्छेद 51ए(ए) नागरिकों से राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने को कहता है, परंतु राजनीतिक दलों के आंतरिक सांगठनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के कितने छंद गाए जाएं, इसके संबंध में कोई कठोर आपराधिक या बाध्यकारी संवैधानिक प्रतिबंध मूल रूप से नहीं रहा है।

तथापि, हाल के दिनों में संसद और गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल व दिशानिर्देशों (जैसे सरकारी कार्यक्रमों में पूरे छह छंदों का गायन) के परिप्रेक्ष्य में, सत्तापक्ष का यह आरोप है कि कांग्रेस का यह निर्णय संसद द्वारा बनाए गए विधायी व राष्ट्रीय सम्मान के मानकों की अनदेखी करता है। यदि कोई कानूनी बाध्यता किसी मंच विशेष पर लागू होती है और उसकी अवहेलना की जाती है, तो उसे कानूनी अनुशासनहीनता कहा जा सकता है, लेकिन किसी दल के आंतरिक सांगठनिक सम्मेलनों पर वैचारिक निर्णय को सीधे तौर पर 'असंवैधानिक' ठहराना एक कानून से अधिक राजनीतिक बहस है।

'वंदे मातरम्' के केवल 2 अंतरे गाने का कांग्रेसी फैसला, न केवल देशविरोधी, संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना बल्कि फिर तुष्टिकरण के रास्ते पर कांग्रेस : अमित शाह

क्या कोई राजनीतिक दल संसद और संविधान से ऊपर है?

इस सवाल का उत्तर स्पष्ट और अकाट्य है: भारत में कोई भी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल संसद, कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार 'संविधान की सर्वोच्चता' है।

जब संसद कोई कानून पारित करती है या देश की सर्वोच्च विधायी संस्था कोई राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तय करती है, तो देश के प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक दल का यह नैतिक व विधिक कर्तव्य है कि वे उसका पालन करें। यदि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक लाभ, वोट-बैंक या वैचारिक जिद के कारण संसद के संकल्पों या राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति निर्धारित सम्मान के मानदंडों को दरकिनार करता है, तो यह लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है।

तुष्टिकरण बनाम वैचारिक स्वतंत्रता की बहस

इस पूरे प्रकरण में दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक तरफ आलोचकों (विशेषकर भाजपा) का मानना है कि 1937 की तर्ज पर केवल दो छंद गाना और संपूर्ण राष्ट्रीय गीत के गायन से परहेज करना तुष्टिकरण की राजनीति का विस्तार है, जो देश के विभाजनकारी इतिहास की याद दिलाता है। उनका तर्क है कि राष्ट्रगीत की पूर्णता को स्वीकार न करना देश की सांस्कृतिक चेतना का अपमान है।

दूसरी ओर, कांग्रेस और उसका समर्थन करने वाले पक्षों का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उनके अनुसार, जब पार्टी अपने आंतरिक कार्यक्रमों में ऐतिहासिक परंपरा का पालन कर रही है, तो इसे राष्ट्रविरोधी या संविधान विरोधी बताना केवल राजनीतिक ध्यान भटकाने की रणनीति है। दरअसल 'वंदे मातरम्' केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आत्मा का स्वर है।

1937 में तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने ही 'वंदे मातरम्' के दो टुकड़े किए

'वंदे मातरम्' को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी के इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टी पर तीखा हमला किया। शाह ने कांग्रेस पर अपनी 'तुष्टिकरण की चरम नीति' को फिर से शुरू करने का आरोप लगाया है।

शाह ने एक्स पर पोस्ट वीडियो में कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति ने 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला लिया है, वह न केवल देशविरोधी है, बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है। 1937 में तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने ही 'वंदे मातरम्' के दो टुकड़े किए। वहीं से दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और आखिरकार देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 'वंदे मातरम्' के 150वें वर्ष पर मोदी सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है।'वंदे मातरम्' के टुकड़े करने की गलती एक बार हो चुकी और देश उसके परिणाम भुगत चुका। देशवासियों से यह अपील है कि एकजुट होकर कांग्रेस के इस तुष्टिकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करें। वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए, उन्होंने न केवल स्वर्गीय बंकिम बाबू की अमर रचना का अपमान किया है, बल्कि उन लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो देश की आजादी के लिए 'वंदे मातरम्' का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे पर चढ़े और कई साल जेल में बिताए।

खेलों पर ₹36441 करोड़ खर्च करेगी सरकार

2036 ओलंपिक में टॉप-10, 2048 में टॉप-5 में आने का टारगेट

गुलशन वर्मा

नई दिल्ली। भारत सरकार अगले 5 साल में खेलों पर 36,441 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने बताया कि 'खेलो इंडिया' योजना के तहत यह पैसा 2026 से 2031 तक खर्च किया जाएगा।

सरकार ने बजट जारी करने के साथ ओलंपिक के लिए मेडल टारगेट भी तय किए हैं। सरकार का लक्ष्य 2036 ओलंपिक की मेडल लिस्ट के टॉप-10 और 2048 ओलंपिक में टॉप-5 देशों में जगह बनाना है। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना चाहता है, जबकि 2048 ओलंपिक में भारत की आजादी के 100 साल पूरे हो चुके होंगे। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिर्फ 6 मेडल जीते थे। मेडल टेली में भारत 71वें स्थान पर था।

प्रतिभाओं की पहचान, खेल ढांचे में सुधार, कोचिंग की क्वालिटी बढ़ाने, खेल विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा।

2036 में 12 से 14 गोल्ड का टारगेट

2036 में 12-14 गोल्ड समेत कुल 30-35 मेडल और 2048 में 35-40 गोल्ड समेत कुल 90-100 मेडल जीतने का लक्ष्य रखा गया है।

इसे हासिल करने के लिए प्रतिभाओं की पहचान, खेल ढांचे में सुधार, कोचिंग की क्वालिटी बढ़ाने, खेल विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा।

खिलाड़ियों की संख्या 10 गुना बढ़ेगी

साई रीजनल सेंटर मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक पांडुरंग चाटे ने कहा कि रिवैंप्ड 'खेलो इंडिया' योजना का मकसद अलग-अलग योजनाओं के बजाय खिलाड़ियों के लिए पूरी खेल यात्रा तैयार करना है।

रिवैंप्ड योजना का बजट 8 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। 2026 से 2031 के बीच योजना के तहत मदद पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी 10 गुना बढ़ाई जाएगी।

30 हजार प्लेयर्स को फायदा

रिवैंप्ड योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच खर्च बांटने का अनुपात 60:40 रखा गया है। इसमें 30 हजार खिलाड़ियों को सहयोग देने की प्लानिंग है। साई रीजनल सेंटर मुंबई ने एक रिलीज में कहा कि 'रिवैंप्ड खेलो इंडिया' योजना महाराष्ट्र के मौजूदा स्पोर्ट्स इको सिस्टम को मजबूत करने का मौका देगा।

17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड

12 साल में पहली बार किसी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं

नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने विगत दिवस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 का एलान किया। 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी खिलाड़ी को खेल रत्न नहीं दिया गया। इससे पहले 2014 में ऐसा हुआ था।

फुटबॉलर अरुमायनायगम को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

इस साल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है। इनमें चेस खिलाड़ी दिव्या देशमुख, विदित गुजराती, एथलीट तेजस्विन शंकर और बैडमिंटन खिलाड़ी गायत्री गोपीचंद व तृषा जॉली जैसे नाम शामिल हैं। फुटबॉल के दिग्गज 84 साल के आई. अरुमायनायगम को अर्जुन अवॉर्ड की लाइफटाइम कैटेगरी में चुना गया है। वे 1962 के जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।

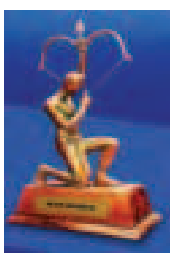

दिव्या ने फिडे विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता था

चेस में दिव्या देशमुख और विदित गुजराती को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है। दिव्या ने 2025 में फिडे विमेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। वह भारत की प्रमुख महिला चेस खिलाड़ियों में शामिल हैं।

बैडमिंटन में गायत्री-तृषा को सम्मान

बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली को अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुना गया है। दोनों महिला डबल्स में भारत की प्रमुख खिलाड़ियों में रही हैं। त्रिशा जॉली-गायत्री गोपीचंद ने 2025 में जीता था सैयद मोदी इंटरनेशनल का महिला डबल्स खिताब।

तेजस्विन शंकर भी सम्मानित

एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर को अर्जुन अवॉर्ड दिया जाएगा। वह हाई जंप के साथ डेकाथलॉन में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकाथलॉन में मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास बनाया था।

भारत ने पाकिस्तान को विश्व कप हॉकी से बाहर किया

5-3 से पीटा, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने 2-2 गोल दागे

ब्लिट्ज ब्यूरो

एम्सटेलवीन। भारत ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम टॉप-8 में पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। नीदरलैंड के वैगनर हॉकी स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक ने 2-2 गोल किए। हार्दिक सिंह ने एक गोल दागा। पाकिस्तान की ओर से हन्नान शाहीद ने 2 और सुफियान खान ने एक गोल किया।

हरमनप्रीत ने 5वें और 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल किए जबकि अभिषेक ने 11वें और 24वें मिनट में फील्ड गोल दागे।

उपकप्तान हार्दिक सिंह ने 35वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर भारत के लिए पांचवां गोल किया। उन्हें आदित्य के खिलाफ पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद के स्टिक फाउल से मौका मिला।

पाकिस्तान की ओर से हन्नान शाहिद ने 22वें और 46वें मिनट में गोल किए। सुफियान खान ने 24वें मिनट में गोल दागा। इन गोल से पाकिस्तान ने भारत की बढ़त का अंतर कम किया।

भारत ने दूसरा मैच जीता

भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में दूसरा मैच जीत लिया है। ग्रुप-डी में टीम 3 मैचों में 6 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं पाकिस्तान बिना किसी जीत के एक अंक के साथ तीसरे नंबर पर रहा।

हरमनप्रीत सिंह टॉप गोल स्कोरर बने

भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह टूर्नामेंट के टॉप गोल स्कोरर बने। उनके अब 5 गोल हो गए हैं। वेल्स के गैरेथ फर्लोंग 4 गोल के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अभिषेक टॉप-5 में शामिल भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं।

पाकिस्तान से 10 साल से नहीं हारा भारत

भारत पिछले 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ अजेय है। इस दौरान हुए 20 मुकाबलों में भारत 18 मैच जीता है। 2 मुकाबले ड्रॉ रहे है। पाकिस्तान ने आखिरी बार साउथ एशियन गेम्स 2016 के फाइनल में भारत को 1-0 से हराया था।

600 वां टेस्ट भारत के लिए रहा खास, श्रीलंका को 165 रन से हराया

ब्लिट्ज ब्यूरो

सुथार के 10 विकेट, पडिक्कल 'प्लेयर ऑफ द मैच'

गॉल। भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। यह भारत का 600वां टेस्ट मैच था। श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का टारगेट मिला था, लेकिन टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ऑलआउट हो गई।

भारत की जीत के हीरो 24 साल के स्पिनर मानव सुथार रहे। उन्होंने मैच में 10 विकेट लिए। दूसरी पारी में 55 रन देकर 6 विकेट लेने वाले सुथार ने श्रीलंका के आखिरी चार विकेट सिर्फ 10 गेंद में लेकर भारत को जीत दिलाई। देवदत्त पडिक्कल को उनकी 167 रन की पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।

सुथार के एक ओवर में 3 विकेट ने मैच पलटा

सुथार ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट लिए। दूसरी पारी में उन्होंने 6 विकेट झटके। श्रीलंका की दूसरी पारी के आखिरी में सुथार ने दो ओवर में 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया।

सुथार ने 75वें ओवर की पहली गेंद पर सोनल दिनुषा को 84 रन पर आउट किया। अगली ही गेंद पर प्रभात जयसूर्या को बोल्ड कर दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लाहिरू कुमारा को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर सुथार ने दूसरी पारी में अपना पांचवां विकेट लिया। इसके बाद अगले ओवर में केशरा नुवानथा को बोल्ड कर उन्होंने मैच में अपना 10वां विकेट लिया।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बारिश और खराब मौसम के कारण मैच में रुकावटें आईं, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा किया।

देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की पारी खेली। उनके अलावा केएल राहुल ने 82 रन और ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट लिए।

भारत के 462 रन के जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। टीम के लिए सोनल दिनुषा ने 100 रन की पारी खेली, जबकि निरोशन डिकवेला ने 80 रन बनाए।

भारत की ओर से मानव सुथार ने 4 विकेट लिए। रवींद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके। भारत को 178 रन की बढ़त मिली।

भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर

भारत गॉल टेस्ट जीतने के बाद डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में टीम 53.33% पॉइंट परसेंटेज के साथ 5वें नंबर पर है। भारत के 10 टेस्ट में 5 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ हैं। उसके खाते में 64 पॉइंट्स हैं।

साइलो तोड़िए, युवाओं से संवाद बढ़ाइए: मोदी

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी, सुरक्षा एवं विदेश मामलों तथा सुशासन से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य के कार्य एजेंडे पर चर्चा हुई। इस दौरान बैठक में पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों से युवाओं के साथ सरकार के जुड़ाव को और मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिव केवल तत्काल चुनौतियों और आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि भारत के विकास की दिशा तय करने के लिए लंबी अवधि की सोच जरूरी है।

बैठक में विभागों के बीच तालमेल की कमी (साइलो) को बड़ी चुनौती बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल संगठनात्मक नहीं, बल्कि सोच से जुड़ी समस्या भी है। उन्होंने अधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का स्वामित्व लेने और अपनेपन की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने बेहतर समन्वय के साथ काम किया था। उन्होंने कहा कि ऐसी समन्वय व्यवस्था सरकार की कार्य संस्कृति का स्थायी हिस्सा बननी चाहिए।

एआई के इस्तेमाल पर दिया जोर

एआई के उपयोग पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका प्रभावी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मानव हस्तक्षेप और निर्णय क्षमता भी बनी रहनी चाहिए। उन्होंने एआई और मानवीय विशेषज्ञता को साथ जोड़कर नए समाधान विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेटा देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति और भविष्य का संसाधन है। सरकार डेटा जुटाने, सुरक्षित रखने और प्रबंधन पर बड़े संसाधन खर्च करती है, लेकिन विभागीय अलगाव और बिखरी प्रणालियों के कारण उसकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता। उन्होंने डेटा इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर डेटा साझाकरण की आवश्यकता बताई।

कश्मीर पर बदली अमेरिकी भाषा भारत की बढ़ती साख का संदेश

पेज 1 के शेष

आज वहां उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार है, हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना अभी बाकी है।

युद्धों के बीच भारत से संवाद की उम्मीद

कश्मीर पर बदलती अमेरिकी भाषा को दुनिया में भारत की बड़ी होती भूमिका से अलग करके नहीं देखा जा सकता। रूस-यूक्रेन युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखा। भारत लगातार कहता रहा कि युद्ध का स्थायी समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से निकल सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी भारत से अपनी भूमिका निभाने की अपेक्षा जताई। अगस्त 2025 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रूस तथा अन्य नेताओं तक शांति का संदेश पहुंचाने के भारत के प्रयास का स्वागत किया। भारत ने भी स्पष्ट किया कि वह शांति की वापसी के लिए हर संभव योगदान देने को तैयार है। पश्चिम एशिया में भी भारत ने संवाद का यही रास्ता अपनाया।

ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत में मोदी ने दोहराया कि समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत हर युद्ध में औपचारिक मध्यस्थ बन चुका है लेकिन बड़ी बात यह है कि एक-दूसरे के विरोध में खड़े देश भी नई दिल्ली से बात करने में सहज हैं। यही भारत की बढ़ती कूटनीतिक पूंजी है।

अर्थव्यवस्था ने भी बढ़ाया भारत का वजन

कूटनीति को ताकत भारत की अर्थव्यवस्था से भी मिल रही है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर 7.6 प्रतिशत रही और वह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहा। वैश्विक व्यापार तनाव और युद्धों से पैदा हुई अनिश्चितता के बीच यह प्रदर्शन भारत की आर्थिक क्षमता को और महत्वपूर्ण बनाता है।

अमेरिकी चुनावी बहस में भी 'इंडिया मॉडल'

इसी दौर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने घरेलू चुनाव सुधार अभियान में भारत की चुनाव व्यवस्था को उदाहरण बनाया है। उन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का उल्लेख करते हुए फोटो पहचान पत्र, 646 मिलियन से अधिक मतदाताओं और बेहद सीमित पोस्टल वोटिंग की चर्चा की तथा अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट को आगे बढ़ाने की मांग की।

यहां तथ्य की एक सीमा स्पष्ट है- ट्रम्प ने भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया की सीधे प्रशंसा नहीं की है। उनकी तारीफ मुख्य रूप से भारत की वोटर पहचान पत्र और चुनाव प्रबंधन व्यवस्था को लेकर थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके बाद कहा कि भारतीय चुनाव व्यवस्था की मजबूती और विश्वसनीयता दुनिया में स्थापित है।

फिर भी प्रतीकात्मक बदलाव बड़ा है। कभी अमेरिका दूसरे लोकतंत्रों को चुनावी व्यवस्था पर सलाह देता दिखाई देता था; आज उसका राष्ट्रपति अपने घरेलू चुनाव सुधार के समर्थन में भारत का उदाहरण पेश कर रहा है।

बदलते भारत की बड़ी तस्वीर

सर्जियो गोर का कश्मीर बयान, पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया, ट्रम्प द्वारा भारतीय चुनाव व्यवस्था की सराहना, युद्धरत देशों के साथ मोदी का निरंतर संवाद और 7.6 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि- इन घटनाओं को साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ होती है।

भारत अब केवल दुनिया का बड़ा बाजार नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार, संवाद का भरोसेमंद मंच और कई वैश्विक बहसों में संदर्भ-बिंदु बनता जा रहा है।

कश्मीर पर अमेरिका की भाषा में आया ताजा बदलाव इसी बड़ी कहानी का शायद सबसे स्पष्ट संकेत है। दुनिया भारत को केवल सुन नहीं रही, बदलती वैश्विक व्यवस्था में उसकी बढ़ती ताकत और प्रासंगिकता को स्वीकार भी कर रही है।

ट्रंप के बयान से पस्त हुआ विपक्ष का 'ईवीएम विलाप' और 'वोट चोरी' का नैरेटिव

ट्रम्प ने अपने पोस्ट में बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी प्रशासन से एक बेहद तार्किक और तीखा सवाल पूछा था: आप बिना किसी वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करा सकते हैं? ट्रम्प ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत के पिछले आम चुनाव में 64.6 करोड़ (646 मिलियन) मतदाताओं ने हिस्सा लिया था जिनमें से 1% से भी कम लोगों ने डाक मतपत्र (पोस्टल बैलट) का उपयोग किया और प्रत्येक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से मौजूद था। जब दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी महाशक्ति का राष्ट्रपति भारत की चुनावी प्रामाणिकता से सीख लेने की वकालत कर रहा हो तो वैश्विक मंच पर यह भारतीय नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है।

2024 के आम चुनाव के अभूतपूर्व आंकड़े और प्रबंधकीय कौशल

भारत का 2024 का आम चुनाव मानव इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन था जिसकी भव्यता और शुचिता को ट्रम्प के बयान ने पुनः प्रमाणित किया है। दिमागी नक्सलियों की 'वोट चोरी' वाली थ्योरी को ध्वस्त करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रबंधित ये आंकड़े ही काफी हैं:

- विशाल मतदाता आधार: देश भर में कुल 96.8 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता थे जिनमें से रिकॉर्ड 64.2 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
- मतदान केंद्रों की विशाल श्रृंखला: देश के कोने-कोने में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे।
- सुरक्षा और पारदर्शिता: पूरी चुनावी प्रक्रिया में 55 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरीफ़ाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी (वीवीपैट या वीवीपीएट) का उपयोग किया गया। इस व्यवस्था के तहत वोटर को वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उनका नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है।
- अधिकारियों की तैनाती: लगभग 1.5 करोड़ चुनाव कर्मियों और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था ताकि बिना किसी हिंसा या धांधली के शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जा सके। इतने विशाल स्तर पर बिना किसी तकनीकी विफलता या बड़े विवाद के चुनाव कराना ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम की असाधारण सफलता को दर्शाता है।

'वोट चोरी' और 'ईवीएम विलाप' करने वालों को करारा झटका

भारत में एक ऐसा तथाकथित बौद्धिक और राजनीतिक वर्ग सक्रिय है जिसका अस्तित्व ही देश की स्वायत्त संस्थाओं के प्रति जनता में अविश्वास पैदा करने पर टिका है। इन्हें 'दिमागी नक्सली' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जंगलों में हथियार लेकर नहीं लड़ते बल्कि वातानुकूलित कमरों में बैठकर देश की लोकतांत्रिक रीढ़ पर वैचारिक प्रहार करते हैं। हर चुनाव परिणाम के बाद इनका एक ही रोना होता है—ईवीएम हैक हो गई, जनादेश चुरा लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब यही ईवीएम और यही चुनाव आयोग विपक्षी दलों को विभिन्न राज्यों में सत्ता दिलाते हैं, तब चुनावी तकनीक बिल्कुल पाक-साफ हो जाती है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पराजय मिलते ही 'वोट चोरी' का पुराना राग फिर से अलापा जाने लगता है। ट्रम्प के इस बयान ने इस दोहरे रवैये को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय चुनाव मशीनरी की विश्वसनीयता और मजबूती वैश्विक स्तर पर स्थापित तथ्य हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव व्यवस्था के खिलाफ दायर किए गए वादों को समय-समय पर खारिज कर दिया है।

दिमागी नक्सलियों की बेचैनी

अंतरराष्ट्रीय सराहना व ज्ञानेश कुमार के कड़े रुख से तथाकथित नैरेटिव-मेकर्स में मची बेचैनी के पीछे ठोस रणनीतिक कारण हैं:

- वैश्विक कार्ड का फेल होना: ये समूह अक्सर विदेशी मीडिया, पश्चिमी विचारकों और मानवाधिकार संगठनों की आड़ लेकर भारत सरकार और भारतीय लोकतांत्रिक संस्थाओं को वैश्विक मंचों पर घेरने की कोशिश करते थे। ट्रम्प जैसी शीर्ष वैश्विक हस्ती द्वारा भारतीय चुनाव प्रणाली को एक रोल मॉडल के रूप में पेश करने से इनका यह अंतरराष्ट्रीय कार्ड पूरी तरह ध्वस्त हो गया है।
- जनता के बीच साख का संकट: भारतीय मतदाता पहले ही चुनावों में भारी हिस्सेदारी दिखाकर इन ईवीएम-विरोधी और 'संस्था-विरोधी' विलापों को खारिज कर चुका है। अब जब वैश्विक स्तर पर भी भारत के चुनाव प्रबंधन की दृढ़ता (यूनिवर्सल फोटो आईडी) की तारीफ हो रही है, तो आम नागरिकों के बीच इन दुष्प्रचार करने वालों की बची-खुची वैचारिक प्रामाणिकता भी समाप्त हो गई है।

संस्थागत मजबूती से खीझ: दिमागी नक्सली हमेशा चाहते हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर, संदेहास्पद और विवादित दिखें ताकि वे देश के भीतर अराजकता या अविश्वास का माहौल बना सकें लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग की इस वैश्विक स्वीकार्यता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय संवैधानिक तंत्र किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त और अभूतपूर्व रूप से सशक्त है।

विपक्ष की हताशा और तंज

ट्रम्प की इस प्रशंसा से बौखलाए राजनीतिक तत्वों और नैरेटिव-मेकर्स की हताशा उनके बयानों में भी साफ नजर आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ताओं ने इस पर तंज कसते हुए यहां तक कह दिया कि 'ज्ञानेश कुमार और ईवीएम दोनों को अमेरिका ले जाइए और वहीं चुनाव कराइए'। यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि जब कोई तर्क नहीं बचता तो संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों का उपहास उड़ाना ही इस वर्ग की अंतिम शरणस्थली बन जाता है।

भारतीय लोकतंत्र का ऊंचा कद

डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की यह सराहना केवल एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक ऊंचे कद का एक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र है। अमेरिका ही नहीं; इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों ने भी भारत की ईवीएम और चुनाव व्यवस्था को अपनाने में रुचि दिखाई है। इसने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि भारत में सत्ता का परिवर्तन किसी 'वोट चोरी' या 'तकनीकी धांधली' से नहीं बल्कि करोड़ों नागरिकों के वैध और प्रमाणित मतों के अधिकार से होता है। ईवीएम और चुनाव आयोग का रोना रोने वाले दिमागी नक्सलियों को अब यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश की संस्थाओं पर कीचड़ उछालकर वे भारतीय जनमानस को और अधिक गुमराह नहीं कर सकते। भारत की चुनावी व्यवस्था अपनी पारदर्शी प्रक्रियाओं, सख्त पहचान नियमों और निष्पक्ष प्रशासनिक नेतृत्व के दम पर आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। यह समय अपनी ही संस्थाओं पर संदेह करने का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की इस वैश्विक गूंज पर गर्व करने का है।

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ चुनावी सहयोग और ईवीएम तकनीक साझा करने या अपनाने में नेपाल, भूटान, नामीबिया और हाल ही में इंडोनेशिया समेत कई देशों ने विशेष रुचि दिखाई है और समझौते किए हैं। इसके अलावा, भारत के चुनाव प्रबंधन निकाय ने दुनिया भर के 28 से अधिक देशों के साथ चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ईवीएम और तकनीकी सहयोग प्राप्त करने वाले प्रमुख देश

भूटान: भारत से तकनीकी सहायता और अनुकूलित ईवीएम अपनाने वाला पहला देश।

नेपाल: प्रायोगिक और संस्थागत तौर पर भारत से ईवीएम और चुनावी सहायता प्राप्त की है।

नामीबिया: राष्ट्रीय चुनावों में भारतीय निर्मित ईवीएम और वीवीपैट का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने वाला प्रमुख अफ्रीकी देश।

इंडोनेशिया: दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र ने 2029 के चुनावों में डिजिटल वोटिंग और ईवीएम प्रणाली को लागू करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है।

चुनावी स्याही और अन्य सहयोग

भारत की प्रसिद्ध चुनावी (अमिट) स्याही मंगोलिया, मेडागास्कर, म्यांमार, कंबोडिया, फिजी और सिएरा लियोन जैसे देशों को भी भेजी जाती है। भारत का निर्वाचन आयोग विभिन्न देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ फिजी, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों के चुनावों में पर्यवेक्षक भी भेज चुका है।

WE STAND COMMITTED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Blitz INDIA Media Group

26 PLATFORMS

INDIA'S GLOBAL VOICE

8 LANGUAGES

4 NATIONAL EDITIONS (PRINT) | 14 GLOBAL EDITIONS (ONLINE) | 5 SOCIAL MEDIA PLATFORMS | 3 WEBSITES

18 EDITIONS

www.blitzindiabusiness.com

NATIONAL (PRINT)

Blitz INDIA | Blitz INDIA Business | ब्लिट्ज इंडिया | ब्लिट्झ इंडिया

International Editions (online)

(UN-recognised Languages)

- Blitz India in Arabic
- Blitz India Business in Arabic
- Blitz India in Chinese
- Blitz India Business in Chinese
- Blitz India in French
- Blitz India Business in French
- Blitz India in Russian
- Blitz India Business in Russian
- Blitz India in Spanish
- Blitz India Business in Spanish

(English Language)

- Blitz United States (New York)
- Blitz UK/Europe (London)
- Blitz Middle East (Dubai)
- Blitz Africa (Tanzania)

For subscription and other querries, connect

contactblitzindia@gmail.com / 9205992246 | 9205992248

A catalyst for Mission Viksit Bharat@2047

RNI No. DELHIN/2022/85477 । संपादित, मुद्रित एवं प्रकाशित द्वारा दीपक द्विवेदी : द इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा- 201301 (उ.प्र.)। संपादकीय, विज्ञापन और प्रशासनिक कार्यालय : 8-बी, वंदना बिल्डिंग, 11 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन नं.- 43502031, 43502032, ई-मेल: info@blitzindiamedia.com, **मुंबई ऑफिस :** 311-बी, आईएनएस टावर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400051, मुख्य सलाहकार : ए.के. शर्मा, संपादक : विनोद शील, ग्रुप क्रिएटिव हैड : कौशल श्रीवास्तव **निदेशक संपादकीय बोर्ड : राकेश शर्मा (समाचार व सभी संपादकीय निर्णयों के लिए पीआरबी एक्ट के अनुसार उत्तरदायी), चेयरमैन एवं प्रधान संपादक : दीपक द्विवेदी** (सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में होगा)